

# राज-भाषा हिन्दी

डा० सेठ गोविन्ददास



हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

प्रकाशन-वर्ष	शक १८८६ : सन् १९६५ ई०
संस्करण	प्रथम संस्करण : ३,००० प्रतियाँ
मूल्य	रु० ४.००
प्रकाशक	गोपालचन्द्र सिंह सचिव, प्रथम शास्त्र-निकाय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
मुद्रक	रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

## प्रकाशकीय

हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वालों में डा० सेठ गोविन्ददास जी का विशिष्ट स्थान है। सेठ जी ने समय-समय पर कौंसिल ऑफ स्टेट से लेकर साहित्यिक समारोहों तक में राज-भाषा हिन्दी के पक्ष को पुष्ट तर्कों द्वारा प्रबल बनाने का अथक एवं अनवरत प्रयास किया है।

सेठ गोविन्ददास जी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के अपराजेय सेनानी के रूप में निरन्तर संघर्ष किया है और आज भी करते आ रहे हैं। आपके लिए हिन्दी का प्रश्न राष्ट्र-हित का अभिन्न अंग है।

हमारा विश्वास है कि आज जबकि राज-भाषा हिन्दी का प्रश्न उग्रतर रूप धारण कर चुका है यह पुस्तक, जोकि उनके राज-भाषा हिन्दी विषयक पाँच भाषाओं का एक संकलन है, रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करने में सहायक होगी।

गोपालचन्द्र सिंह

सचिव, प्रथम शासन-निकाय  
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

## विषय-सूची

१. नियमों में इस प्रकार का संशोधन कि सदस्य हिन्दी और उर्दू में भाषण कर सकें	१
२. कौन भाषा में संविधान-सभा की कार्यवाही चलेगी	११
३. राज-भाषा विधेयक पर	२७
४. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् का अध्यक्षीय भाषण	४३
५. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मेरठ अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण	७१



## नियमों में इस प्रकार का संशोधन कि सदस्य हिन्दी और उर्दू में भाषण कर सकें

१६ मार्च, १९२७

१६ मार्च, १९२७ को 'कौंसिल ऑफ़ स्टेट' में सेठ गोविन्ददासजी ने मांग की कि भारतीय विधान-मण्डल में हिन्दी या उर्दू में भी भाषण करने की अनुमति मिलनी चाहिये। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित कर भाषण दिया—

“अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूँ, वह इस प्रकार है—‘यह कौंसिल गवर्नर-जनरल से सिफारिश करती है कि वैधानिक प्रक्रिया के नियमों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जिससे भारतीय विधान मण्डल के सदस्य हिन्दी या उर्दू में भाषण कर सकें और वे भाषण केन्द्रीय विधान मण्डल की औपचारिक कार्यवाही में नियमानुसार मुद्रित व प्रकाशित हों।’

अध्यक्ष महोदय, हम कई वर्षों से ‘स्वराज’ की बात करते रहे हैं और ‘स्वराज’ शब्द इतना लोकप्रिय हो गया है कि महामहिम सम्राट् ने, महामहिम ड्यूक आर्क ग्रेट के द्वारा जो सन्देश भेजा है, उसमें भी उन्होंने उसकी चर्चा की है। किन्तु, श्रीमन्, मुझे आशंका है कि हम अभी तक इस शब्द का पूरा महत्त्व नहीं समझ पाये। मेरी दृष्टि में राजनीतिक स्वराज्य, जो इस देश की सम्यता, कला, संस्कृति व भाषा से रहित हो, निरर्थक है। स्वाभाविक रूप से एक देश के विधान मण्डल की कार्यवाही उसी भाषा में चलनी चाहिए, जो वहाँ की जनता बोलती हो। ब्रिटिश संसद् की कार्यवाही इटालियन में होना और इटालियन प्रतिनिधि सभा की कार्यवाही अंग्रेजी में चलने की कल्पना भी असम्भव है ; किन्तु यहाँ हमारे मामले में स्टैंडिंग आर्डर नं० २७ में चुपचाप यह व्यवस्था दे दी गयी है कि “इस विधान-मण्डल की कार्यवाही अंग्रेजी में चलेगी।” और फिर धाव पर नमक छिड़कने के लिए लैजिस्लेटिव असेम्बली के भूतपूर्व अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट ने अपनी एक पुस्तक में कहा है—“किसी भी भारतीय भाषा में समस्त भारत की भाषा बनने की सामर्थ्य कदापि नहीं। अतः भविष्य में प्रान्तीय स्तर की भाषा चाहे कोई भी हो, किन्तु सघीय भाषा सदा अंग्रेजी ही रहेगी और भारतीय एकता का यही सबसे बड़ा उपकरण है।”

श्रीमन्, मेरी सम्मति में यह घाव पर नमक छिड़कना है। यदि अंग्रेजी ही संयुक्त भारत की भाषा बनने वाली है, तो मुझे यह कहना पड़ता है कि यह संयुक्त भारत एक अराष्ट्रीय भारत होगा। अंग्रेजी इस देश की भाषा न कभी रही है और न आगे होगी। सदन की सन्तुष्टि के लिए मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूँ।

गत जनगणना के अनुसार भारत की ३२ करोड़ की कुल जनसंख्या में अंग्रेजी केवल ३ लाख व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है और बहुत कम संख्या में समझी जाती है। जनगणना रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि प्रति १०,००० व्यक्तियों में केवल १६० पुरुष और १८ महिलाएँ ही अंग्रेजी लिख व पढ़ सकती हैं। श्रीमन्, इस भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा है। १५० वर्ष के ब्रिटिश शासन में भारतीय जनसंख्या के इतने छोटे भाग को अंग्रेजी में शिक्षित किया जा सका है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि इस गति से इस देश की सारी जनता को अंग्रेजी सिखाने में कितने दिन लगेंगे। फिर क्या यह उचित भी है कि एक विदेशी भाषा दूसरे देश पर राष्ट्रीय भाषा के रूप में लादी जाय। जो लोग अपनी भाषा को दबाते हैं, या दबाने पर बाध्य होते हैं, उनका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। आयरिश कवि थामस डेविस ने इस सम्बन्ध में अपनी मातृ-भाषा गेलिक में कहा है—

“कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। मातृ-भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी जरूरी है, क्योंकि यह विदेशी आक्रमण को रोकने में पर्वतों और नदियों से भी अधिक समर्थ है।”

श्रीमन्, इसीलिए इतिहास में विजेताओं की सदा से विजित भूमि पर अपनी भाषा लादने की नीति रही है। विजित देशों ने भी सदा इन अत्याचारों का सामना किया है और अपने क्षेत्र से भी अधिक अपनी मातृभाषा की रक्षा की है। हम यह बात कई देशों के इतिहास में पाते हैं। इंग्लैण्ड में भी नार्मन-विजय के बाद विजेताओं ने अपनी भाषा थोपने का प्रयत्न किया। समस्त प्रशासनिक कार्य नार्मन-फ्रेंच में किये जाने लगे, किन्तु यह अधिक समय तक नहीं चला और इसका स्थान ऐंग्लो-सैक्सन भाषा ने ही लिया। पोलैण्ड के इतिहास में भी हम यही बात देखते हैं। जब रूस, प्रशिया व आस्ट्रिया ने उसका विभाजन किया और वहाँ अपनी-अपनी भाषा लादने का प्रयत्न किया, तो पोलैण्डवासियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने उन विश्वविद्यालयों का बहिष्कार किया, जहाँ प्रशियन और रशियन भाषाएँ पढ़ाई जाती थी और विल्ना व क्रैको के अपने पुराने विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित किया। यही बात हंगरी में हुई। जब आस्ट्रिया ने हंगरी पर अपनी भाषा लादने का

प्रयत्न किया, तो हंगरी की जनता ने इसका विरोध किया और केवल इस शर्त पर आस्ट्रियन साम्राज्य का अंग बनना स्वीकार किया कि उनकी भाषा को भी प्रशासन में बराबर का दर्जा दिया जायेगा। इसी प्रकार आयरलैण्ड ने भी अंग्रेजी अपनाने से इन्कार कर दिया और अपनी मूल भाषा गैलिक को पुनर्जीवित किया। दक्षिण अफ्रीका में भी बोअरवासियों ने अपने अंग्रेज शासकों को बाध्य कर दिया कि वे उनकी भाषा को प्रशासन में सम्मानपूर्ण दर्जा दें। भारत में भी अंग्रेजों ने भाषा के सम्बन्ध में विजेताओं की पुरानी परम्परा अपनाई, जिसे मैं यहाँ कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के वक्तव्य उद्धृत करके स्पष्ट करूँगा।

१७९२ में चार्ल्स ग्रान्ट ने भारतीयों को इंग्लैण्ड के निकट लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था, कि हिन्दू जनता को अपने साथ बांधने और अपने आधिपत्य को चिरस्थायी करने के लिए हमें बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके अपनाने होंगे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्तर्गत मद्रास के गवर्नर सर चार्ल्स ट्रेवेल्यान ने अपनी एक पुस्तक में कहा—

“अंग्रेजी ढंग से शिक्षित, अंग्रेजी उद्देश्यों में सलग्न और अंग्रेजी साम्राज्य के कार्यों में सक्रिय व्यक्ति हिन्दू से भी अधिक हो जाता है, जिस प्रकार रोमन ढंग से शिक्षित गाल और इटालियन रोमन हो गये।”

उन्होंने आगे कहा—

“अंग्रेजी साहित्य भी हमारी उद्देश्यपूर्ति में कम सहायक नहीं। अंग्रेजी साहित्य से परिचित व्यक्ति यह भूल जाता है कि हम विदेशी हैं और घोर विरोधी की बजाय हमारा निकटतम सहयोगी हो जाता है।”

वह और आगे कहते हैं—

“ऐसा व्यक्ति हमें नापसन्द करने की बजाय हमारे निकट आने में गर्व अनुभव करेगा, हमें अपने संरक्षक व शुभचिन्तक की दृष्टि से देखेगा और स्वेच्छा से हमारे ढाँचे में ढल जायेगा।”

जब भारत की वागडोर ससद् के हाथ में आई, तब भी अंग्रेजी शासकों की यह नीति नहीं बदली। सन् १८८० में सर अलैगज़ैण्डर आर्बटनाट ने कहा—“भारत में शिक्षाप्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि लोग ब्रिटिश शासन को अपना सौभाग्य मानें और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपने लिए दुर्भाग्यपूर्ण समझें।”

सन् १८८० में ही सर रिचर्ड टैम्पल ने अपनी पुस्तक में कहा—“अंग्रेजी भाषा, साहित्य व दर्शन से शिक्षित व्यक्ति अपनी मूल राष्ट्रीयता से बिल्कुल मुक्त होकर इंग्लिश राष्ट्र के निकट आ जायेगा।”

अतः, श्रीमन् यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित करने की नीति अपने साम्राज्य को जमाने के लिए और हमारी राष्ट्रीयता को समाप्त करने के लिए अपनाई थी।

अब प्रश्न उठता है कि जब अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं और न होगी, तो इस विशाल देश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा और कौन-सी भाषा ले सकती है। सौभाग्य-वश इसके लिए हिन्दी या उर्दू का नाम लिया जा सकता है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा है। दोनों की बनावट और दोनों का व्याकरण एक ही है। एक यूरोपियन डा० बीम्स के मतानुसार—“हिन्दी और उर्दू को दो विभिन्न भाषाएँ समझना एक बहुत बड़ी गलत-फहमी है।”

श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र इस सदन के मुस्लिम सदस्य मेरे इस मत को समझे कि हिन्दी व उर्दू दो विभिन्न भाषाएँ नहीं। इसीलिए मैंने अपने प्रस्ताव में “हिन्दी और उर्दू” न कहकर “हिन्दी या उर्दू” कहा है।

अब हमें देखना है कि इस देश में हिन्दी की वर्तमान स्थिति क्या है। गत जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार साढ़े तेरह करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं और पाच करोड़ बंगाली, दो करोड़ मराठे और एक करोड़ गुजराती हिन्दी समझ सकते हैं। यदि प्रयत्न किया जाये, तो ये सब हिन्दी बोल भी सकते हैं। दक्षिण भारत की लगभग साढ़े चार करोड़ जनता इस समय हिन्दी नहीं समझती, किन्तु मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि उनके लिए भी हिन्दी ग्रीक के समान नहीं। गत सात वर्ष से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की एक शाखा वहाँ कार्य कर रही है, जिसके बहुत सन्तोषजनक परिणाम निकले हैं। हाल में कोकनाड़ा में नेशनल कांग्रेस के अवसर पर स्वागत समिति के अध्यक्ष—जो स्वयं तेलगू-भाषी थे—ने हिन्दी में भाषण किया। इसी समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन हुआ और इसमें भी स्वागत समिति के अध्यक्ष ने तेलगू-भाषी होते हुए हिन्दी में भाषण किया। सम्मेलन में भाग लेने वाले कई तमिल व तेलगू-भाषी लोगों ने हिन्दी में विचार व्यक्त किये।

अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत के विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले लोग—बंगाली, गुजराती व महाराष्ट्री—हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लें। मैं इन भाषाओं के विद्वानों के विचार उद्धृत करके इसे सिद्ध करना चाहूँगा।

विश्वविख्यात साहित्यिक व बंगला के सर्वोच्च कवि डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। सर गुरुदास बैनर्जी, श्री रमेशचन्द्र दत्त व डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने भी यही विचार व्यक्त किया है। स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्र दत्त कहते हैं—“यदि कोई भाषा भारत के अधिकांश भाग में स्वीकार

की जा सकती है, तो वह हिन्दी है।” डा० राजेन्द्रलाल मित्र कहते हैं—“हिन्दी भारत की सब से अधिक महत्वपूर्ण भाषा है और यह भारत के शिक्षित लोगों की भाषा है।”

महाराष्ट्रियों में भी हम यही बात देखते हैं। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मराठी साहित्य परिषद् में वहाँ के विद्वान् एकत्रित हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया। प्रथम अखिल भारतीय नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हिन्दुस्तानी से अपनी शिक्षा प्रारम्भ की और मैंने स्वयं उन्हें उनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व जबलपुर में हिन्दी में भाषण करते सुना था। महाराष्ट्र के एक अन्य विद्वान् डा० भाण्डारकर कहते हैं—“भारत में अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए समान भाषा का दर्जा हिन्दी को ही दिया जा सकता है। और इसे समस्त भारत में स्वीकार कराने में अधिक कठिनाई नहीं होगी।” इतिहासवेत्ता रावबहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य कहते हैं—“हिन्दी हर दृष्टि से भारत की राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है।”

हिन्दी में गुजरात की भक्ति को स्पष्ट करने की अधिक आवश्यकता नहीं। स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी गुजरात के दो सबसे बड़े पुत्र हैं। स्वामी दयानन्द ने अपने समस्त ग्रन्थ हिन्दी में लिखे, अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार हिन्दी में किया और महात्मा गांधी ने अपने प्रयत्नों से हिन्दुस्तानी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य भाषा के रूप में स्वीकृत कराया। वह कहते हैं—“अंग्रेजी जनता की भाषा कभी नहीं बन पायेगी और हमें अपने राजनीतिक कार्यों में प्रतिदिन जनता के अधिक से अधिक निकट आना होगा। देश में लगभग एक प्रतिशत लोग भी मुश्किल से अंग्रेजी समझते हैं, जबकि ६० प्रतिशत से अधिक जनता सामान्य रूप से हिन्दुस्तानी समझती है।”

हम यह भी देखते हैं कि अतीत में बंगाल, महाराष्ट्र व गुजरात के बहुत-से लेखकों ने हिन्दी में लिखा। राजस्थान तथा गुजरात के दो प्रसिद्ध कवियों—मीराबाई व नरसी मेहता—ने हिन्दी में लिखा और पश्चात् भी दो कवि—दयाराम और नर्मदाशंकर—हिन्दुस्तानी में लिखते रहे हैं। बंगाल में जस्टिस शारदाचरण मित्र व अमृतलाल चक्रवर्ती ने हिन्दी की समृद्धि में योग दिया। महाराष्ट्र में सन्त तुकाराम व मोरोपन्त ने हिन्दी में लिखा और इनके बाद भी पण्डित माधवराव सप्रे तथा कई अन्य सज्जन हिन्दुस्तानी में लिखते रहे हैं।

अब हमें देखना है कि यूरोपियन इस बारे में क्या कहते हैं? भारतीय भाषाओं के सबसे बड़े ज्ञाता डा० ग्रियर्सन कहते हैं—“भारत में एक भाषा (हिन्दी) ही

राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है। यही एक भाषा है, जिस में दो विभिन्न प्रान्तों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है, क्योंकि इसका व्याकरण भारत की अधिकांश भाषाओं के समान है और इसका शब्द-कोश सबकी सम्मिलित सम्पत्ति है।”

श्री फ्रेडरिक पिनकाट कहते हैं—

“हिन्दी ने अपना स्थान बना लिया है, इसे ६ करोड़ लोग बोलते हैं और इसे उनकी प्रशासनिक भाषा बनाने से अधिक देर तक रोका नहीं जा सकता। हिन्दी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका साहित्य अधिकाधिक आगे बढ़ रहा है और इस गति से यह वर्तमान स्थिति को बनाये रखना असम्भव कर देगी।”

अब हमें देखना है कि हिन्दुस्तानी के बारे में विभिन्न भारतीय राज्यों की क्या नीति है। मैं केवल उन्ही राज्यों के बारे में कहूँगा, जो हिन्दी भाषी नहीं हैं। बड़ौदा में राज-परिवार की भाषा मराठी है और जनता की भाषा गुजराती ; किन्तु वहाँ की शिक्षाप्रणाली में हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। हिन्दी अब वहाँ प्रत्येक को पढ़ाई जा रही है। ग्वालियर और इन्दौर में भी राज-परिवार की भाषा मराठी है ; किन्तु वहाँ प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का उपयोग होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हिन्दी का शब्द-कोश भारत की राष्ट्रभाषा होने के लिए उपयुक्त है। अतीत में यूरोपियन विद्वानों का मत था कि “भारतीय भाषाएँ भद्दी, अवैज्ञानिक, मूर्खतापूर्ण और निरर्थक हैं।” यह धारणा अब बदल गयी है। श्री क्रस्ट अपनी एक पुस्तक में कहते हैं—“भारतीय भाषा में कोई भी मानवीय भावना व्यक्त करने की पूर्ण सामर्थ्य है और यह उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा के लिए भी उपयुक्त है।”

सन् १९०१ की भारतीय जनगणना रिपोर्ट के प्रथम खण्ड के पृष्ठ सं० ३०७ में कहा गया है कि “हिन्दी के पास ऐसा शब्द-कोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है, जो अंग्रेजी से किसी भी प्रकार कम नहीं।”

अब, श्रीमन्, एक और प्रश्न है। यह पूछा जा सकता है कि क्या हिन्दुस्तानी को सीखना आसान है? श्री मकमर्डी कहते हैं—“किसी विदेशी के लिए अंग्रेजी सीखना तीन कारण से कठिन है। इसका अक्षरबिन्द्यास (स्पेलिंग) बड़ा अनियमित है, इसका शब्द-कोश बड़ा विस्तृत है और इसमें मुहावरे विचित्र प्रकार के हैं।” हिन्दी के सम्बन्ध में महात्मा गांधी कहते हैं—“एक औसत बंगाली यदि प्रतिदिन ३ घंटे हिन्दी पढ़े, तो २ मास में और एक द्रविड़ ६ मास में इसे सीख सकता है। बंगाली हो या द्रविड़, वह अंग्रेजी को इतनी जल्दी नहीं सीख सकता।”

इस प्रकार श्रीमन्, जब भारत की सारी जनसंख्या हिन्दुस्तानी समझती है और आधी बोलती भी है, तब क्या यह विडम्बना नहीं कि हमारे केन्द्रीय विधान-मण्डल की कार्रवाई एक ऐसी भाषा (अंग्रेजी) में चलाई जाये, जिसे केवल ३ लाख लोग बोलते हैं और अधिक-से-अधिक ३० लाख समझते हैं। यूरोपियन अपने को भारत का सेवक बताते हैं और यहां हमें कार्रवाई अंग्रेजी में चलाने पर बाध्य किया जाता है। यदि वे सचमुच इस देश के सेवक हैं, तो उन्हें हमारी भाषा सीखनी चाहिए। वे तो भारत के सेवक हैं और भाषा हमें उनकी सीखनी पड़ती है, कार्रवाई हमें उन्हीं की भाषा में चलानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में वर्तमान आदेश में अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हुए कहा गया है—‘यदि अध्यक्ष चाहे, तो परिषद् में अंग्रेजी न जानने वाले सदस्य को देशी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।’

इससे लगता है कि मुख्य स्थान अंग्रेजी का है और देशी भाषाओं को केवल सहन किया गया है। इसी प्रकार प्रशासन में उच्च पद यूरोपियनों को मिलते हैं और माननीय सर मुहम्मद हबीबुल्ला व माननीय श्री एस० आर० दास को अप-वाद रूप में लिया गया है। मेरी सम्मति में यह स्थिति बदलनी चाहिए। हमें प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण और विधान-मंडल की कार्रवाई का हिन्दुस्तानीकरण करना चाहिए। फिर यह शिकायत भी की जाती है कि जनता नये सुधारों और विधान-मण्डलों के प्रति उदासीन है। इसका एक कारण यह भी है कि जनता विधान-मण्डल की कार्रवाई नहीं समझ सकती। इस सदन की दर्शक दीर्घा में या तो वे लोग आते हैं, जो अंग्रेजी समझते हैं या वे, जो सदस्यों के खूबसूरत चेहरे और सदन की शान-शौकत देखना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई समझने के लिए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी तब तक यही शिकायत रही, जब तक हिन्दुस्तानी को नहीं अपना लिया गया। १९१९ तक कांग्रेस अधिवेशन में बहुत सीमित संख्या में प्रतिनिधिगण आते थे। दर्शकगण भी बहुत कम संख्या में आते थे; किन्तु जब से कांग्रेस ने अपनी कार्रवाई हिन्दुस्तानी में चलानी शुरू की, तब से एक महान् अन्तर आ गया। मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन उन्होंने इस सदन में यह नीति अपना ली, दर्शक दीर्घाएं खचाखच भरी नजर आयेगी और लोग इसकी कार्रवाई में असली रुचि लेंगे।

इस दिशा में सदन के सामने अगली कठिनाई हिन्दुस्तानी की सकेत-लिपि (शार्टहैंड) की आयेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी की सकेतलिपि बहुत पूर्ण और सरल है। कोई व्यक्ति अंग्रेजी की सकेत लिपि ४ मास से कम में नहीं सीख सकता जबकि हिन्दुस्तानी की २ मास में पूरी तरह सीखी जा सकती है। इस प्रणाली

की जांच १९२१ में तब हुई, जब अहमदाबाद कांग्रेस में सारी कार्रवाई इसी ढंग से ठीक-ठीक अंकित की गयी। जिस दिन सरकार ने सदन में हिन्दुस्तानी भाषण को प्रोत्साहन दिया, ऐसे लोग स्वतः मिल जायेंगे, जो हिन्दुस्तानी सकेत-लिपि में सारी कार्रवाई अंकित कर सकें।

अन्त में मैं सरकार से एक अपील करना चाहूँगा। सरकार की यह घोषित नीति है कि अन्ततः वह एक भारतीय राष्ट्र को जन्म देकर उसे स्वराज्य प्रदान करना चाहती है। श्रीमन् मुझे यह कहने की आज्ञा दीजिये कि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा चिह्न है। सौभाग्य से हमारे पास एक ऐसी भाषा है, जो हमारी राष्ट्र-भाषा और जनभाषा बन सकती है। जर्मनी में हम क्या देखते हैं? फ्रेकफर्ट की सन्धि तक जर्मनी कई भाषाओं में विभाजित था—हाई जर्मन, लो जर्मन और अन्य अनेक बोलियाँ, किन्तु जब से उसने एक भाषा अपनाई, वह एक महान् राष्ट्र बन गया। सरकार यहाँ हिन्दुस्तानी अपनाये और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहा भी एक भारतीय राष्ट्र अल्पकाल में निर्मित हो जायेगा। स्वराज की मांग पर हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है, किन्तु हिन्दुस्तानी के प्रश्न पर सौभाग्य से दोनों एकमत है। सिख भी हमारे साथ हैं। उनकी कई धार्मिक पुस्तकें और यहा तक कि ग्रन्थ साहब भी हिन्दुस्तानी में लिखा गया था। इस प्रकार भारत में रहने वाली सभी जातियाँ, चाहे वे हिन्दू हों या मुस्लिम, सिख हों अथवा जैन, हिन्दुस्तानी के प्रश्न पर एकमत है। अतः सरकार मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी यह घोषणा प्रकाशित करे कि वह एक भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं, श्रीमन्, अपना प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।”

(बहस के उपरान्त उत्तर में गोविन्ददास का भाषण)

“अध्यक्ष महोदय, माननीय सर उमरहयातखां और माननीय श्री दास ने मेरे प्रस्ताव के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। मैं खुद भी यह प्रस्ताव कर्नल नवाब सर उमरहयातखां के शब्दों में पेश कर सकता था, किन्तु मुझे भय है कि यह सरकार को तब और भी अधिक अव्यावहारिक लगता। प्रस्ताव में इतनी विनम्र भाषा के प्रयोग के बाद भी जब मेरे माननीय मित्र श्री दास को इस पर आपत्ति है, तो यदि मैं सरकार से सदस्यों को अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में बोलने के लिए बाध्य करने की मांग करता, तब श्री दास क्या कहते? जो बात यह अब कह रहे हैं, उसे मैं भी कह सकता था और शायद अधिक जोर के साथ कहता, किन्तु काश कि मैं व्यावहारिकता का ध्यान रखते हुए ऐसा न कर सका।



मेरे माननीय मित्र श्री दास ने कहा है कि हमें इस प्रश्न को व्यावहारिकता की दृष्टि से देखना चाहिए। वह मेरी भावना की सराहना करते हुए स्वीकार करते हैं कि देश में एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वह यह भी स्वीकार करते हैं कि अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा कदापि नहीं हो सकती, यद्यपि अपने लम्बे भाषण में उन्होंने यह बात नहीं कही। वह जानते हैं कि १५० वर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य की लम्बी अवधि में जब अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, तो यह अब कैसे बन सकती है। वह अंग्रेजी के मामले में भी यही “व्यावहारिक” कठिनाई अनुभव करते हैं और मुझसे तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, जब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी नहीं समझ जाता। हमने १५० वर्ष तक प्रतीक्षा की है। कुछ भारतीय ऐसे भी हैं, जो कहते हैं कि हिन्दुस्तानी या हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती और केवल अंग्रेजी ही यह दर्जा ले सकती है। अंग्रेजी का काफी प्रसार हो जायेगा, तो सरकार यह अनुमति भी नहीं देगी कि हम अपनी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग करें; अतः मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर जनभावनाओं का आदर करें। मैं केवल यह चाहता हूँ कि सदन में जो सदस्य हिन्दी में बोलना चाहें, यद्यपि वह अंग्रेजी जानता हो या न भी जानता हो, उसे हिन्दी में बोलने की अनुमति दी जाय। मैं किसी माननीय सदस्य को हिन्दी में बोलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता। मैं केवल सरकार से हिन्दी के लिए समानता का दर्जा चाहता हूँ और कुछ नहीं, और जब इतना विनम्र प्रस्ताव, इतना महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव, जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाला प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, और सरकार इसका विरोध करती है, तो मैं स्वाभाविक रूप से क्षुब्ध हो जाता हूँ।

श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र श्री दास के तर्क स्वीकार करने में असमर्थ हूँ और अपना प्रस्ताव सदन की सम्मति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।”

### मतदान

पक्ष में—१२

विपक्ष में—२२

जिन्होंने पक्ष में मत दिये उनमें तीन मुस्लिम सदस्य, तीन बंगाली सदस्य और तीन दक्षिण भारतीय थे। उस समय की कौंसिल आफ स्टेट में नामजद सरकारी और गैरसरकारी सदस्यों की संख्या काफी होती थी; अतः विपक्ष में जिन २२ सदस्यों ने मत दिया, उनमें १४ तो अंग्रेज ही थे। शेष आठ में से अधिकांश नामजद थे। यह एक भाग्य की विडम्बना थी कि इन नामजद सदस्यों में हिन्दी के प्रसिद्ध

मिश्र-बन्धुओं के पडित श्यामबिहारी मिश्र को भी नामजद सदस्य होने के कारण इस प्रस्ताव के विपक्ष में मत देना पड़ा था। इस प्रकार यद्यपि यह प्रस्ताव अस्वीकृत तो हो गया ; परन्तु यथार्थ में यह स्वीकृत माना जाना चाहिए।

नोट—उपर्युक्त दोनों भाषण मूल में अंग्रेजी में हैं, क्योंकि उस समय नियम था कि जो सदस्य अंग्रेजी जानते हैं, उन्हें केवल केन्द्रीय विधान सभाओं में ही नहीं, प्रांतीय विधान सभाओं में भी अपने भाषण अंग्रेजी में देने चाहिए।

## कौन भाषा में संविधान-सभा की कार्यवाही चलेगी

२३ दिसम्बर, १९४६

श्री सेठ गोविन्ददास—मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूँ—

“मैं चाहता हूँ कि दूसरी पक्ति से ‘आर इंगलिश’ शब्द हटा दिया जाय। बाद में जहाँ नियम यह कहता है कि शर्त यह है कि अध्यक्ष उन सदस्यों को, जो इन दोनों भाषाओं (हिन्दी या अंग्रेजी) से अपरिचित हैं, इस परिषद् में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देगे, यहाँ ‘मदर टंग’ के बाद ‘आर इंगलिश’ रखा जाये।

इस समय जैसा कि नियम है उसके अनुसार हम लोग हिन्दी, उर्दू यानी हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में यहाँ बोल सकते हैं; लेकिन हमने देखा कि ९ तारीख के बाद जब से हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, हिन्दुस्तानी के लिए कोई बधन न रहने पर भी हम लोगो की यहाँ जितनी कार्रवाई हुई है, वह ज्यादातर अंग्रेजी में ही हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब यह परिषद् स्वतन्त्र भारत का विधान बनाने जा रही है, और यदि अंग्रेजी को ही अपनी राष्ट्रभाषा मानकर वह काम करना चाहती है, तो यह एक बड़े दुःख की बात है। अंग्रेजी कभी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। मैं यह कहना चाहता हूँ, अपने मद्रासी भाइयों से, कि अगर २५ वर्षों के बाद, महात्माजी के प्रयत्नों के बाद, उतनी कोशिश के बाद भी और कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद भी अगर वह हिन्दुस्तानी नहीं समझते हैं, तो यह उनका दोष है, हमारा नहीं। और जब यह दोष उनका है, तो इसके लिए जो कठिनाई उनके सामने उपस्थित है, उन्हें उसे मजूर करना पड़ेगा। यदि कुछ मद्रासी भाई हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते और इसके लिए हमारी विधान परिषद् में, जिसे सत्ता-सम्पन्न सभा कहा जा सकता है और जो स्वतन्त्र भारत का विधान बनाने के लिए बैठी है, अंग्रेजी का दौर-दौरा रहता है, तो यह हमारी वरदास्त के बाहर है। आप जानते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जो सैद्धान्तिक बातें हैं, उनके लिये हर किसी को अपने विचार आगे रखने को तैयार रहना चाहिए और उसी के आधार पर मैंने अपनी बातें कही हैं। मेरा विश्वास है कि मेरी इस तरमीम को, जो अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं और हिन्दुस्तानी नहीं जानते, उनको अंग्रेजी में बोलने की आजादी हो,

आप मजूर करेंगे। इस तरसीम के बाद यहाँ जो कार्यवाही होगी, वह, मैं आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तानी भाषा में होगी, न कि अंग्रेजी में।

हमारे नरम दल के भाई अंग्रेजी को ही अपनी राष्ट्रभाषा मानते थे और यदि मानते नहीं थे, तो कम-से-कम बनाना चाहते थे; लेकिन हमने देखा कि इतने वर्षों के बाद भी हिन्दुस्तान में कितने लोग अंग्रेजी पढ़ सके। अंग्रेजी आज कितने लोग समझ सकते हैं। हमें इतिहास से मालूम होता है कि विजेता जिन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उन पर वह अपनी भाषा लादना चाहता है। आयरलैण्ड के इतिहास में, इंग्लैंड के इतिहास में, हंगरी के इतिहास में अनेक जगह हमें यह देखने को मिलता है। जिन देशों पर विदेशियों ने अपनी भाषा लादनी चाही, उन्होंने बराबर अपनी भाषा के लिये युद्ध किये और आखिर में विजय प्राप्त की। जहाँ तक आयरलैंड की गैलिक भाषा का सम्बन्ध है, वह करीब-करीब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी लड़ाई की और आखिर में आयरलैंड की जीत रही।

हिन्दुस्तानी को व्यवहार में लाने के लिए तीन कठिनाइयाँ पेश की जाती हैं। पहली बात यह कही जाती है कि हम को ऐसे वैज्ञानिक शब्द नहीं मिलते, जिनसे हमारी कुल कार्यवाही हिन्दुस्तानी में हो सके। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने उस्मानिया युनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा दृष्टान्त मौजूद है, जहाँ पर सारी पढ़ाई का माध्यम हिन्दुस्तानी है। हिन्दुस्तानी में वैज्ञानिक शब्दों को ढालने की उन्होंने कोशिश की, उसके लिए विशेषज्ञ रखे। मैं यह नहीं चाहता कि जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते, उनको जबरदस्ती हिन्दुस्तानी में बोलने को कहा जाय। इसीलिए मदन टंग के बाद मैंने अंग्रेजी शब्द जोड़ दिया है। जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते, उनको आजादी होगी कि वे अंग्रेजी में बोलें। तीसरी कठिनाई यह कही जाती है कि बहुत-से लोग हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो हिन्दुस्तानी न समझते हों। उनकी सख्या अँगुली पर गिनी जा सकती है। जो कठिनाई आज हमारे सामने लाई जाती है, वह कांग्रेस के सामने भी लायी जाती थी, पर हमने देखा कि महात्मा गांधी के प्रयत्नों के बाद आज कांग्रेस में हिन्दुस्तानी में ही भाषण होते हैं। वहाँ पर जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते, वही अंग्रेजी में भाषण देते हैं। यहाँ भी यही होना चाहिए। ९ तारीख से अब तक जो कार्यवाही विधान-परिषद् ने की है, उसे देखते हुए यह मालूम होता है कि यहाँ पर अंग्रेजी का ही दौरदौरा रहेगा।

आज से २० वर्ष पहले जब मैं कौंसिल आफ स्टेट का मेम्बर था, मैंने इस सम्बन्ध में वहाँ भी एक प्रस्ताव रखा था। उस वक्त सर गोपाल स्वामी, जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ मौजूद थे और उनको याद होगा कि उस समय कितनी बहस हुई थी।

उस बहस में मैंने आयरलैण्ड के एक कवि का उद्धरण पढ़ा था, मैं अपने मद्रासी भाइयों के लाभ के लिए इस कथन को पढ़ना चाहता हूँ। वह कथन अंग्रेजी में इस प्रकार है—

“The Nation without a mother-tongue cannot be called a nation The defence of one’s mother-tongue is a more powerful barrier against the intransigent of foreigners than even the national barriers of rivers and mountains.”

## संविधान मूल में राष्ट्रभाषा में बने

१९ अगस्त, १९४७

श्री सेठ गोविन्ददास—सभापतिजी, एक बहुत बड़ा मसला अभी तक तय नहीं हुआ और वह यह है कि हमारी भाषा क्या रहेगी। आपने यह कहा था कि जो विधान हम तैयार करेंगे, वह मूल में हमारी राष्ट्रीय भाषा में होगा और उसका अनुवाद चाहे तो अंग्रेजी में हो सकता है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ, जो कमेटी बनाई जा रही है, वह कमेटी, हमारी कौन-सी भाषा रहेगी, इस पर भी विचार करेगी या नहीं? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि जो बिल या मसविदा हम तैयार कर रहे हैं, वह जैसा आपने उस समय कहा था, वह मूल में हमारी भाषा में होगा या मूल में अंग्रेजी में होगा? मैं यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि इन विषयों पर भी इस समय निर्णय हो जाना चाहिए और मूल में जो हमारा मसविदा हो, वह हमारी राष्ट्रीय भाषा में होना चाहिए। उसका अंग्रेजी अनुवाद हो सकता है। साथ ही हमारी कौन-सी भाषा रहेगी, यह भी इस समय निर्णय हो जाना चाहिए।

## डा० अम्बेडकर के प्रस्ताव के समर्थन में

५ नवम्बर, १९४८

अध्यक्ष महोदय, मैं डा० अम्बेडकर द्वारा रखे गये प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनके द्वारा कही गयी प्रत्येक बात से सहमत हूँ; वरन् इसके विपरीत मेरी सम्मति में उनका भाषण उनके द्वारा रखे गये शानदार प्रस्ताव के उपयुक्त नहीं। उन्होंने कई विवादास्पद प्रश्न उठा दिये हैं और अच्छा होता, यदि वे उनका जिक्र भी न करते। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह समर्थन मैं किसी उत्साह से नहीं कर रहा

हूँ, जिसकी इस समर्थन में आवश्यकता है। यह प्रस्ताव और सारा संविधान सदन के सामने एक विदेशी भाषा में रखा गया है। कल इस विषय पर काफी बहस हुई, अतः मैं इस सबध में अधिक नहीं कहूँगा। फिर भी मुझे इस बात पर खेद है कि हमने अपनी राष्ट्रभाषा का प्रश्न अभी तक तय नहीं किया। श्रीमन् यदि हम इस सम्बन्ध में कल निश्चय कर लेते, तो आपको यह आश्वासन देने की जरूरत नहीं पड़ती कि यह संविधान सदन के सामने राष्ट्रभाषा स्वीकृत होनेवाली भाषा में प्रस्तुत किया जायेगा और अब तक स्वीकृत धाराओं को भी पुनः उसी भाषा में स्वीकार कराया जायेगा। सम्भवतः आपको याद होगा कि आपने इस प्रकार का एक आश्वासन दिया था और इस पर मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि संविधान का मूल प्रारूप राष्ट्रभाषा में होगा। एक विदेशी भाषा में संविधान स्वीकार करना, हमारे लिए न केवल लज्जा का विषय है, वरन् इससे भविष्य में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी और हमारे देश पर अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा।

ब्रिटिश शासन-काल में भी हमारे देश ने कई ऐसे विद्वानों को जन्म दिया, जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए प० सुधाकर द्विवेदी का नाम लिया जा सकता है। आजकल मौलाना अबुलकलाम आजाद हैं और उन्हें भी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञाता नहीं माना जा सकता। यदि हमने स्वतन्त्र भारत में भी, उसकी अपनी राष्ट्रभाषा होते हुए भी, उसका संविधान अंग्रेजी में तैयार किया, तो हम सदा के लिए कम-से-कम सवैधानिक मामलों में ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर हो जायेंगे, जो अंग्रेजी के विशेषज्ञ हैं, अतः मैं फिर आपसे अपील करूँगा कि हमारा मूल संविधान हिन्दी में होना चाहिए।

फिर यह संविधान अपूर्ण भी है। बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें इसमें सम्मिलित नहीं। निस्संदेह द्वितीय अध्याय में धारा ९९ में यह तो कहा गया है कि “संसद् में कार्रवाई हिन्दी या अंग्रेजी में चला करेगी,” किन्तु इसमें राष्ट्रभाषा के नाम का कोई जिक्र नहीं। हम धारा ९९ में संशोधन करके यह कमी पूर्ण तो कर सकते हैं, किन्तु फिर भी यह तब तक संभव नहीं, जब तक हम स्पष्ट रूप से यह घोषित नहीं कर देते कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन-सी है। केवल यह कह देना कि संसद् की कार्रवाई अमुक भाषा में चलेगी, पर्याप्त नहीं है। हमें स्पष्ट रूप से घोषणा करनी होगी कि हमारी राष्ट्रभाषा यह है। हमें अपनी राष्ट्रलिपि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार स्पष्ट घोषणा करनी होगी। इन दोनों ही मामलों में हमारा संविधान अभी तक अवूरा है।

सम्भवतः आप को यह तथ्य भी विदित होगा कि आयरिश संविधान में वहाँ के राष्ट्रध्वज का भी उल्लेख है। यद्यपि हमने एक प्रस्ताव द्वारा तिरंगे को अपना

राष्ट्रध्वज स्वीकार कर लिया है; किन्तु संविधान के इस प्रारूप में इसका कोई उल्लेख नहीं। यह कमी अवश्य दूर होनी चाहिए।

हमारा संविधान राष्ट्रगीत के प्रश्न पर भी मौन है। हमारे प्रधान मंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कई अवसरों पर यह घोषणा कर चुके हैं कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय संविधान-सभा करेगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे संविधान में भी हमारे राष्ट्रगीत की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं उन सभी मामलों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके सम्बन्ध में संविधान के वर्तमान प्रारूप में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी। मेरी सम्मति में हिन्दी ही ऐसी एकमात्र भाषा है, जो इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। मैं समझता हूँ इस सदन में बहुत ही कम सदस्य ऐसे होंगे, जिनकी राय में अंग्रेजी को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। हिन्दी और हिन्दुस्तानी का विवाद भी अब समाप्त हो चुका है। धारा १९ में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि अब ससद् की कार्यवाही “हिन्दी अथवा अंग्रेजी” में चलेगी। मैं इस बात पर भी सहमत हूँ कि आगामी कुछ वर्षों में ससद् की कार्यवाही में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। हमें किसी पर कोई चीज लादना नहीं है। किन्तु, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि होनी चाहिए।

संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। मेरा मत है कि यूनियन जैक की भाँति हमें अपने राष्ट्रध्वज को भी कोई सुन्दर नाम देना चाहिए। इसे ‘सुदर्शन’ नाम दिया जा सकता है। सुदर्शन उस वस्तु को कहते हैं, जो देखने में सुन्दर हो। प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सदन में राष्ट्रध्वज सम्बन्धी प्रस्ताव रखते हुए अपने भाषण में कहा था कि यह देखने में बहुत सुन्दर है। फिर इसमें एक चक्र भी है। भगवान विष्णु के चक्र का नाम सुदर्शन चक्र था; अतः इस ध्वज का नाम ‘सुदर्शन’ रखना अत्यधिक उपयुक्त होगा।

जहाँ तक राष्ट्रगान का प्रश्न है, मेरी सम्मति में ‘वन्देमातरम्’ हमारा राष्ट्रगीत हो सकता है। हमारे स्वतन्त्रता सघर्ष का इतिहास वन्देमातरम् से जुड़ा है। यदि यह कहा जाये कि इसका स्वर वाद्ययन्त्रों के अनुकूल नहीं, तो यह कठिनाई वाद्य विशेषज्ञों के प्रयास से दूर हो सकती है। महाकवि सूरदास और मीराबाई के पद एक नहीं अनेक स्वरों में गाये जाते हैं; अतः यह सोचना गलत होगा कि वन्देमातरम् वाद्य के लिए उपयुक्त नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कवि सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर का आदर न करता हो; उनका गीत “जनगणमन” सन् १९११ में स्वर्गीय सम्राट् जार्ज पंचम की भारत यात्रा के अवसर पर रचा गया था। यह भारतमाता के प्रति न होकर स्वर्गीय सम्राट् के प्रति है। इसकी

हर भावना 'भारत भाग्य विधाता' अर्थात् सम्राट् के साथ सम्बन्धित है, जो हमारे गणराज्य के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः केवल "वन्देमातरम्" ही हमारे राष्ट्र-गान के लिए उपयुक्त होगा।

यह सविधान अधूरा तो है ही, इसमें कुछ संशोधनों की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हमारे देश को इसमें 'इण्डिया' का नाम दिया गया है। विदेशों के लिए तो यह ठीक है; किन्तु यदि हमें यहाँ कोई जनसभा आयोजित करनी हो, तो क्या उसमें हम अपनी जनता को 'इण्डियन' कहकर सम्बोधित करेंगे। जब हम अपने देश का सविधान अपनी ही राष्ट्रभाषा में बनाना चाहते हैं और जब हम एक धर्म-निरपेक्ष राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तब इसे 'इण्डिया' 'हिन्दुस्तान' का नाम देना उपयुक्त न होगा। मेरी सम्मति में इस देश का प्राचीन नाम 'भारत' ही इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा।

एक और बात की भी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। हमारा देश कृषिप्रधान है; अतः हमें कृषि के लिए उपयोगी सब वस्तुओं की रक्षा करनी होगी। इस दृष्टि से गाय की रक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। गोरक्षा का प्रश्न हमारी संस्कृति के साथ भगवान् कृष्ण के समय से जुड़ चुका है। हमारे लिए यह न केवल एक धार्मिक और आर्थिक, बल्कि एक सांस्कृतिक समस्या भी है। जिस प्रकार हमने अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया है, उसी प्रकार गोवध को भी अपराध घोषित कर सकते हैं। हमें अपने संविधान में ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हम अपने इतिहास में देखते हैं कि चाहे हिन्दू-युग हो अथवा मुस्लिम-युग, इस देश में केवल वही शासक सफल और लोकप्रिय हो सके हैं, जिन्होंने गोवध कानूनन निषिद्ध कर दिया था। इतिहास में इसके प्रमाण उपलब्ध हैं कि कई मुस्लिम शासकों ने ऐसा किया। गोवध-निषेध के लिए वित्तीय काम का भी बहाना लिया जा सकता है; किन्तु मेरा विश्वास है कि यदि हम गोरक्षा के नाम पर कर भी लगा दें; तो जनता इसे प्रसन्नतापूर्वक अदा करेगी। वित्तीय कठिनाइयों का बहाना ब्रिटिश शासनकाल में लिया जाता था; किन्तु मैं आशा करता हूँ कि अब गोरक्षा के मामले में इस बहाने की आड़ नहीं ली जायेगी।

हमें अपने संविधान पर हर दृष्टि से विचार करना है और इसे हर प्रकार से पूर्ण बनाना है। हमारा देश कोई नया नहीं है, यह एक प्राचीन राष्ट्र है, इसका एक लम्बा इतिहास और समृद्ध संस्कृति है। हमें अपने सविधान का निर्माण इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। हम मुस्लिम या किसी भी अल्पसंख्या को कठिनाई में नहीं डालना चाहते; किन्तु हम उन व्यक्तियों की कभी खुशामद नहीं करेंगे, जो हमारे सामने द्विराष्ट्र का सिद्धान्त रखते हैं। मैं यह



स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक दृष्टि से केवल एक संस्कृति ही इस देश में रह सकती है। जिस संविधान को हम स्वीकृत करें, वह हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए और हमारी राष्ट्रभाषा में ही होना चाहिए।

हमें शताब्दियों के बाद अपना संविधान बनाने का अवसर मिला है ; अतः हमें ऐसा संविधान बनाना चाहिए, जिससे हमारी मातृभूमि के गौरव में वृद्धि हो।

## कारों की संख्या-तस्तियों पर हिन्दी अंक

१० जून, १९४९

सेठ गोविन्ददास—सभापतिजी, आप आज की कार्यवाही प्रारम्भ करें, इससे पहले मैं आपका ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के ९ तारीख के अंक की ओर दिलाता हूँ, जिसमें कि उन्होंने मोटर प्लेट्स के जिस प्रश्न को मैंने यहाँ उठाया था, उस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस ने जो कुछ होम डिपार्टमेंट को लिखा है, उसका जिक्र किया है। वे लिखते हैं.—

“पता लगा है कि गृहमंत्रालय का ध्यान १९४९ के भारतीय मोटर वेहीकल्स अधिनियम १९४९ की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसके अनुसार संख्या-तस्तियों पर गाड़ी की संख्या अंग्रेजी अक्षरों तथा अकों में होनी चाहिए। पत्र में आगे चलकर यह लिखा है कि भारतीय मोटर वेहीकल्स अधिनियम समस्त देश में लागू है और दिल्ली प्रशासन को इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है।”

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संयुक्त प्रान्त में और मेरे मध्य प्रान्त में भी इसी कानून के अनुसार सब कार्यवाही होती है। इतने पर भी वहाँ की मोटरों के नम्बर, मिनिस्ट्रो की मोटरों तक के नम्बर, हिन्दी में हैं और यह भी आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के नियमों के मुताबिक पार्लियामेंट में जो भाषण होते हैं, वे भी अंग्रेजी में होने चाहिए, पर हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर श्री मावलकर साहब ने अनेक बार यह कहा है कि वर्तमान परिस्थिति जब बदल गई है, तब इस प्रकार के नियमों को लागू क्यों किया जाय। पार्लियामेंट में बराबर हिन्दी में भाषण होते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो दलील है, वह कामनसेन्स और वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल है और बड़ी बेहूदी दलील है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई खास परिस्थिति उत्पन्न होने न पाये ; इसलिए इस सम्बन्ध में आपको कुछ-न-कुछ करने की कृपा करनी चाहिए।

## राष्ट्रभाषा के प्रश्न का निर्णय

३० जुलाई, १९४९

सेठ गोविन्ददास—सभापतिजी, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब से हम लोग यहाँ आये हैं, तब से राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें सुन रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रभाषा का सवाल पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया जायगा। आपने बार-बार इस बात को कहा था कि हम केवल राष्ट्रभाषा का प्रश्न ही यहाँ हल न करेंगे, बल्कि हम अपना विधान भी अपनी भाषा में बनायेंगे। अब यह अन्तिम अधिवेशन है और मुझे इस बात का पता लगा है कि जो कमेटी आपने विधान के अनुवाद के सम्बन्ध में नियुक्त की थी, उसने उन धाराओं का हमारी भाषा में अनुवाद कर लिया है, जो हम यहाँ पास कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन अफवाहों का खडन कर यह निश्चय कर दें कि राष्ट्रभाषा का सवाल हम अपनी पार्लियामेंट पर न छोड़कर इस विधान-परिषद् में निश्चित करेंगे, क्योंकि उसके बिना मेरा अपना मत है कि सारा विधान ही अधूरा रहता है। इसी के साथ मैं यह चाहता हूँ कि आप तीन विषयों के लिए—हमारी राष्ट्रभाषा कौन-सी होगी, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या होगा और हमारे देश का क्या नाम होगा, निर्णय करने की तारीख़ मुकर्रर कर दीजिए, जिससे लोगों को मालूम हो जाये कि अमुक तारीख़ों पर यह सवाल लिये जायेंगे।

## राजभाषा की धाराओं पर

१२ सितम्बर, १९४९

सेठ गोविन्ददास—सभापतिजी, आज के दिन को मैं अपने जीवन के दिनों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। आज जो कुछ हो रहा है, उससे मुझे हर्ष भी कम नहीं है। मैं आपको भी इस बात के लिये धन्यवाद देता हूँ कि मैंने समय-समय पर इस विषय को अनेक रूपों में आपके सामने उपस्थित किया और आपने मेरी बातें सुनी। आपके पहले इस विधान-परिषद् के प्रथम दिवस, जब आप के ही प्रान्त के श्री सच्चिदानन्दसिंह हमारे सभापति थे, उस दिन भी मैंने इस विषय को उठाया था। उसके पश्चात् मैं इस विधान-परिषद् के सदस्यों को इस सम्बन्ध में बहुत कष्ट देता रहा हूँ। इस विधान-परिषद् में घूम-घूम कर इस हाल में मीलों चल कर और उनके घरों पर जाकर, उनके प्रान्तों में जाकर इस विषय पर मैं इस विधान-परिषद्

के सदस्यों से अनुनय-विनय करता रहा हूँ और मुझे इस बात पर भी बड़ा हर्ष है कि हमारे प्रधान मन्त्रीजी के शब्दों में ९५ प्रतिशत बातों पर हम लोगो का एकमत भी हो गया है ; परन्तु एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि जिन विषयों पर हमारा मतभेद है, उन विषयों में भी हमें शान्ति से हल करना चाहिए। यदि हम ऐसे विषयों पर मत भी ले, मत-विभाजन भी कराये, तो भी उससे किसी प्रकार की कटुता नहीं आने देनी चाहिए। हम लोगो ने प्रजातन्त्र को स्वीकार किया है और प्रजातन्त्र में बहुमत से ही सारे काम चल सकते हैं। यदि किसी विषय पर मतभेद होता है, तो उसका निर्णय केवल बहुमत से ही हो सकता है और बहुमत जो भी निर्णय करे, उसे अल्पमत वालों को सिर झुका कर स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी प्रकार की कटुता के आप ने भी यही अपील की थी। अभी श्री गोपाल-स्वामी आयरगजी ने भी यही अपील की और मैं भी यही अपील करना चाहता हूँ।

मैं अपने दक्षिण भारत में माननीय सदस्यों और जिन प्रान्तों में हिन्दी भाषा नहीं बोली जाती, उन प्रान्तों के सब माननीय सदस्यों का अत्यन्त अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने कम-से-कम एक बात स्वीकार कर ली और वह बात यह है कि चाहे आप उसे राष्ट्रभाषा कहे, चाहे आप उसे राज्य-भाषा कहे, वह हिन्दी ही हो सकती है और उसकी लिपि देवनागरी, जैसा कि मैंने अभी कहा था, हमारे प्रधान मन्त्रीजी के शब्दों में भाषा का विषय ९५ प्रतिशत हल हो गया है। जो पाँच प्रतिशत बाकी है, उसमें कुछ सैद्धान्तिक बातें हैं। उन सिद्धान्त की बातों को यदि हमारे दक्षिण भारत के माननीय सदस्य और दूसरे प्रान्तों के सदस्य स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें हमें भी वैसी ही स्वतन्त्रता देनी चाहिए कि हम भी अपने सिद्धान्तों पर स्थित रहें और बिना किसी प्रकार की कटुता आये हम ऐसी बातों को बहुमत से निपटा लें।

अकों का प्रश्न लीजिये। अको का एक प्रश्न है, जो यहाँ पर भी सभी लोगों के हृदयों में एक क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्षोभ की क्या आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान गत दो या तीन वर्षों की घटनाओं की ओर ले जाना चाहता हूँ। जब पहले-पहल मैंने भाषा और लिपि का प्रश्न उनके सामने रखा, तब अको का प्रश्न उन्होंने नहीं उठाया था। आज यह प्रश्न जितने महत्त्व का हमारे दक्षिण भारत के बन्धुओं को दाँखता है, उस समय उन्होंने इसे उस दृष्टि से नहीं देखा था। मैं उनकी स्मरण-शक्ति को ताजा करने के लिये उस फारमूला को यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, जिस पर उन्होंने बहुत बड़ी सख्या में हस्ताक्षर किये थे। वह फारमूला मैं यहाँ पढ़ता हूँ, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में।

“हम लोग इस बात के पक्ष में हैं कि भारत के विधान में यह रखा जाये कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि हिन्दी और देवनागरी होगी। राष्ट्र सघ पार्लियामेन्ट में सब काम हिन्दी और देवनागरी अक्षरों के द्वारा अथवा उस समय तक के लिये जो सघ पार्लियामेन्ट निश्चित करे, अंग्रेजी में होगी।”

अंग्रेजी में वह इस प्रकार है:—

“We support the view that the Union Constitution should lay down that the national language and character shall be Hindi and Devanagari respectively, that in the Federal parliament business shall be transacted in Hindi written in Devanagari character or, for such period as the Federal parliament decides in English.”

काजी सैयद करीमुद्दीन (मध्यप्रान्त और बरार मुस्लिम)—एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्, सभा में यह कौन-सा लेख पढ़ा जा रहा है?

सेठ गोविन्ददास—यह वह डाकूमेन्ट है, जिस पर यहाँ के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे और जो फारमूला भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने स्वीकार किया था।

इस फारमूले पर साधारण सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे। हमारे मद्रास के श्री गोपालस्वामी आयगर ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। डा० पट्टाभि सीतारमैया ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। श्री प्रोफेसर रंगा, श्री अल्लेसन, श्री थिरूमल राव, श्री अनंत शयनम आयगर, श्री काला वेकट राव के इस पर हस्ताक्षर हैं।

श्री काला वेकटाराव—मद्रास (जनरल) मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? मेरे प्रति जो निर्देश है, उसे मैं नहीं समझता हूँ।

सेठ गोविन्ददास—मैंने जिस फारमूला को अभी पढ़ा है, उस पर आपने हस्ताक्षर किये हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय आपने देवनागरी को स्वीकार किया था, उस समय आपने देवनागरी के अकों को भी उसके साथ स्वीकार किया था, अन्यथा आप उस समय भी यह कहते कि इसमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स की बात रक्खी जानी चाहिए।

इसमें हमारे बम्बई के बन्धुओं के हस्ताक्षर हैं। श्री निर्जलिगप्पा, श्री जेधे, श्री पाटस्कर, श्री गुप्ते इत्यादि के।

हमारे बंगाल के बन्धुओं के भी इस पर हस्ताक्षर हैं—श्री मैत्र, श्री मजूमदार श्री गुहा, श्री सुरेशमोहन घोष और दूसरे सज्जन।

उडीसा के श्री विश्वनाथदास, श्री बी० दास, श्री लक्ष्मीनारायण साहु, श्री युधिष्ठिरसिंह, आसाम के श्री रोहिणीकुमार, श्री चालिहा ने भी इस पर हस्ताक्षर किये हैं। हिन्दी भाषा-भाषी सभी सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर हैं।

तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह न्यूमरल्स का जो सवाल उठा, वह सवाल बहुत पीछे और हाल का ही उठा हुआ है और इस सवाल को उस समय किसी ने महत्त्व नहीं दिया था।

मैं यह नहीं कहता कि आज इस विषय को उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। अवश्य है। मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि जब वे स्वयं किसी समय देवनागरी लिपि को, जिस रूप में वह है, उस रूप में स्वीकार करना चाहते थे, तो उनको उसके अको को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अक लिपि के अन्दर होते हैं, लिपि के बाहर नहीं होते। और उस समय जब वे इस बात को स्वीकार कर रहे थे, तो आज बिना किसी रोष के, बिना किसी क्रोध के और बिना किसी शोभ के उन्हें कम-से-कम हमें अपने मत पर स्थित रहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन्होंने यदि अपना मत बदल दिया है और वह विरोध में वोट करना चाहते हैं, तो करें, परन्तु हम यदि अपने पुराने मत पर स्थित हैं, तो उन्हें हमारे प्रति किसी रोष की भावना को नहीं रखना चाहिए।

अब दूसरी बातों को हम ले। श्रीयुत आयगर साहब ने जो धारा यहाँ पर पेश की है, उसमें उन्होंने यद्यपि हिन्दी और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया है, पर उसी के साथ उस धारा को ध्यानपूर्वक देखने से यह प्रयत्न दिखाई देता है कि वह समय दूर रखा जा रहा है, जब कि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले सके। इस विधान-परिषद् में दो प्रकार के माननीय सदस्य दिखते हैं—एक वे हैं, जो हिन्दी और देवनागरी लिपि को स्वीकार करते हैं, परन्तु उसे दूर-से दूर टालना चाहते हैं। दूसरे वे लोग हैं, जो अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को जल्दी-से-जल्दी ले आना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में कांग्रेस की कार्यकारिणी का जो प्रस्ताव है, उसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने कहा है कि हमको धीरे-धीरे इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि १५ वर्ष में अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ले ले और १५ वर्ष में या उसके पश्चात् इस देश में अंग्रेजी का स्थान न रहे; पर जो भाषण श्रीयुत गोपाल स्वामी आर्यगरजी ने आज दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि १५ वर्ष के बाद भी एक लम्बे समय तक हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान नहीं लेने देना चाहिए, कम-से-कम हम लोगों का यह मत नहीं है यह मैं कह देना चाहता हूँ। मेरी स्पष्ट राय है कि यदि अंग्रेजी को देश से जाना है, तो वह जल्दी-से-जल्दी जाय। यदि हम १५ वर्ष

का समय स्वीकार करते हैं, तो यह मतलब नहीं है कि उससे पहले हिन्दी अंग्रेजी का कोई भी स्थान नहीं ले। आप जानते हैं, इस भवन के सारे सदस्य जानते हैं कि पहले हमारा यह मत था कि अंग्रेजी का स्थान हिन्दी कितने समय में ले, इस विषय को पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाये। जो फारमूला मैंने अभी पढ़ा, उसे, जो हिन्दी भाषा-भाषी नहीं हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया था। फिर हम पाँच वर्ष पर आये। उस समय हमने सोचा था कि पाँच वर्ष में यदि हम प्रयत्न करेंगे, तो हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्र-भाषा कान्फ्रेंस हुआ। यद्यपि उसको हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बुलाया था, पर उसमें किस प्रकार के महानुभाव आये थे, इस पर विचार कीजिये।

मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कान्फ्रेंस इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुआ। उसमें बंगाल से डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी और श्री सजनीकात दास, जो कि बंगीय साहित्य-परिषद् के मंत्री हैं, आये थे। उसमें करनाटक से भी श्रीयुत एस० कृष्ण शर्मा आये थे, जो कन्नड़ साहित्य-परिषद् के मंत्री हैं। उस में मलयालम के महाकवि बलातोल पधारे थे, जिनका मलयालम-साहित्य में वही स्थान है, जो बंगीय साहित्य में रवीन्द्र बाबू का था। मलयालम के श्री कुशान-राज भी उसमें आये थे। मराठी के महामहोपाध्याय श्री कानेजी उसमें नहीं आ सके; उन्होंने उसके लिये अपना मत भेजा था। उड़ीसा से भी आर्तवर्लभ महन्ती आये थे। तमिल के श्री नीलकण्ठ शास्त्री और डाक्टर राघवनजी आये थे। तेलगू के श्री सोमय्याजी आये थे और श्री विश्वनाथ सत्यनारायणजी पधारे थे। इस प्रकार इस परिषद् को यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बुलाया था; पर इसमें अन्य भाषाओं के बड़े-बड़े विद्वानों ने भाग लिया था और उन्होंने यह तय किया कि अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को दस वर्ष में लेना चाहिए। तो पाँच वर्ष से हम दस वर्ष पर आ गये और हमने यह स्वीकार किया कि धीरे-धीरे दस वर्ष में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले ले। उसके पश्चात् जब हमारे दक्षिण भारत के बन्धुओं ने कहा कि दस वर्ष का समय कम मालूम होता है और यह पन्द्रह वर्ष होना चाहिए, तो हमने १५ वर्ष स्वीकार कर लिया। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करके हमने उन पर कोई उपकार किया है। उपकार तो उनका हम मानते हैं और उनके अनुगृहीत हैं कि उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि स्वीकार किया, पर हम यह अवश्य कहना चाहते हैं कि उनके सुभीते के लिये हमने स्वीकार किया कि दस वर्ष के स्थान पर १५ वर्ष कर दिये जायें, तो हमें आपत्ति नहीं। हम इस बात को जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में पाँच या दस या पन्द्रह वर्ष कोई चीज हो सकते हैं; परन्तु देश के जीवन में यह समय बहुत बड़ा समय नहीं है।

इसलिये हमने दस वर्ष के स्थान पर १५ वर्ष को स्वीकार किया। सवाल यह है कि हम १५ वर्ष में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाना चाहते हैं, या पन्द्रह वर्ष में भी नहीं। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत दिया है। जो राष्ट्र-भाषा कन्वेन्शन हुआ, उसने भी इस विषय में साफ तौर पर कहा है। फिर आज श्री गोपालस्वामी आयरजी यह कहते हैं कि वह तो १५ वर्ष के बाद भी एक बड़े लम्बे समय को देखते हैं, जिस समय कि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले सकेगी। मैं बड़े अदब के साथ उनसे यह कहन चाहता हूँ कि कम-से-कम हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। यह हमारा स्पष्ट मत है।

तीसरा विषय जिस पर मैंने सुधार पेश किया है, वह यह है कि जिन प्रान्तों में हिन्दी को स्वीकार कर लिया गया है और जिन प्रान्तों की अदालतों में आज हिन्दी चल रही है, वहाँ पर हम क्यों अंग्रेजी को थोपना चाहते हैं। आप सशुक्त प्रान्त को ही लीजिये। वहाँ पर सारे बिलों के मसविदे, सारे प्रस्ताव, सारे प्रश्न हिन्दी में ही होते हैं। अब जो आयरजी की धारा यहाँ पेश हो रही है, वह अंग्रेजी में हो, यह तो मामले को आगे न बढ़ा कर पीछे हटाना हुआ। इसको हम भला कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि जिन प्रान्तों में अभी भी हिन्दी में काम चल रहा है, वहाँ भी अंग्रेजी को लादा जाये। जहाँ कचहरियों में अभी भी हिन्दी में काम चल रहा है, वहाँ भी अंग्रेजी को लादा जाये। यह तीसरा विषय है, जिस में हम बहुत मतभेद रखते हैं, अपने दक्षिण भारत के बन्धुओं से।

अब मुझे कुछ अन्य बातें कहनी हैं। हम हिन्दी का पक्ष लेने वालों पर एक आक्षेप होने वाला है कि हम इस विषय को साम्प्रदायिकता की दृष्टि से देखते हैं। यह आक्षेप हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने हम पर किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम लोगों का सम्बन्ध है, हम इस विषय को साम्प्रदायिकता की दृष्टि से जरा भी नहीं देखते। हम इस विषय को राष्ट्रीय दृष्टि से देखते हैं। मैं अपने सम्बन्ध में आपसे कह सकता हूँ कि ३० वर्ष के सार्वजनिक जीवन में मैं आज तक किसी भी साम्प्रदायिक सस्था का सदस्य नहीं रहा हूँ। यह बात मौलाना अबुल-कलाम साहब जानते हैं कि जब सन् २१ में खिलाफत का आन्दोलन चला था, तो मैं स्वयं सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी का सदस्य था। दूसरे लोगों को आप ले लीजिये। जैसे टडनजी है और दूसरे लोग, जो आज हिन्दी के आन्दोलन में किसी प्रकार का भाग ले रहे हैं, क्या कभी उनका किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिक सस्था से सम्बन्ध रहा है।

अपने सम्बन्ध में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली दो बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक जमाना था कि जब हमारे जबलपुर नगर में हिन्दी मस-

लमानो के दंगे हुआ करते थे। उस समय हमारे यहाँ एक मस्जिद तोड़ दी गई। उस मस्जिद को मैंने वहाँ अपने धन से बनवा दिया। हमारे प्रान्त के खंडवा नगर मे कुछ लाख रुपया लगा कर मेरी माता के नाम पर मेरे पिताजी ने एक धर्मशाला बनवाई है। इस धर्मशाला मे लक्ष्मीनारायण के मन्दिर की स्थापना की गई है। इस मन्दिर की प्रतिष्ठा विनोबा भावेजी ने की। इस मन्दिर मे लक्ष्मीनारायण की मूर्ति के साथ सब धर्मों के ग्रन्थों की भी स्थापना की गई है। वहाँ कुरान की स्थापना की गई है, वाइबिल की स्थापना की गई है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की स्थापना की गई है, जैन धर्म के ग्रन्थों की स्थापना की गई है, सिख धर्म और पारसी धर्म के ग्रन्थ भी वहाँ स्थापित है। सब धर्मों के ग्रन्थों की वहाँ पर इज्जत के साथ स्थापना की गई है। हिन्दी-आन्दोलन करने वालों को साम्प्रदायिक कहना, बड़ा भारी अन्याय है। उर्दू भाषा केवल मुसलमानों की ही अकेली भाषा है, यह मैं नहीं कहता। मैं यह मानता हूँ कि उर्दू भाषा मे इस देश के बड़े-बड़े हिन्दू विद्वानो ने, कवियो ने भी रचना की है। मगर मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता कि उर्दू भाषा अधिकतर देश के बाहर की चीजो को देखती है। आप उर्दू के साहित्य को अच्छी तरह देख सकते है। साहित्य का मुझे थोडा-बहुत ज्ञान है। आप उर्दू-साहित्य को देखेंगे, तो आप को कही भी हिमालय का वर्णन नहीं मिलेगा। आपको उसकी जगह कोहकाफ का वर्णन मिलेगा। हमारे देश की कोयल को आप कभी उसके साहित्य मे नहीं पायेंगे। आपको सिर्फ बुलबुल का वर्णन मिलेगा। भीम और अर्जुन की जगह पर आपको रुस्तम का वर्णन मिलेगा, जिसका इस देश से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम पर साम्प्रदायिकता का जो आक्षेप हो रहा है, वह बिल्कुल गलत है। मैं आपसे यह बात उर्दू के किसी द्वेष की वजह से नहीं कह रहा हूँ। हम उर्दू से प्रेम रखते है और बराबर उससे हमारा प्रेम रहेगा। मगर मैं यह अवश्य कहूँगा कि हिन्दी के समर्थक साम्प्रदायिक नहीं, जो उर्दू का समर्थन करते है वे साम्प्रदायिक है।

हमाशा देश सेक्यूलर स्टेट है और हम सब लोग इसको स्वीकार करते है। हम सब धर्म वालों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। हम किसी धर्म के बीच मे रोड़ा अटकाना नहीं चाहते, पर हम इस बात को मानते है कि सेक्यूलर स्टेट होते हुए भी हमारे देश मे दो संस्कृति नहीं है।

चीन में भी मुसलमान रहते हैं, रूस मे भी मुसलमान रहते है, मगर चीन और रूस के मुसलमानो और वहाँ के अन्य धर्मावलम्बियों मे कोई भेद नहीं है। वहाँ के निवासियों के नाम भी हम देखें, तो हमे कोई अन्तर मालूम नहीं पडता। उनकी पोशाक, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति एक ही है। यह बात सत्य है कि सेक्यू-



लर स्टेट को हमने मान लिया है। मगर हमने इसका यह अर्थ तो कभी नहीं समझा कि सेक्युलर स्टेट मानना अनेक सस्कृतियाँ मानना है। यह एक पुराना देश है और इसका इतिहास पुराना है। देश में हजारों वर्षों से एक ही सस्कृति चली आई है और वह परम्परा अभी तक कायम है। इस परम्परा को रखने के लिये और इस बात का खडन करने के लिये हमारी दो सस्कृतिया हैं, हम इस देश में एक भाषा और एक लिपि रखना चाहते हैं।

प्रान्तीय भाषाओं से हमारा कोई द्वेष नहीं है। प्रान्तीय भाषाओं की तरक्की वगैर केन्द्रीय भाषा की भी उन्नति नहीं हो सकती। यह बात मैं अपने मित्रों को खुश करने के लिये नहीं कर रहा हूँ। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में सभापति के नाते मैंने जो भाषण मेरठ में दिया था, उस वक्त भी मैंने यह बात साफ कर दी थी कि हर प्रान्तीय भाषा की भी उन्नति होनी चाहिए और अपने-अपने प्रान्त में उसका सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। वहाँ की शिक्षा का माध्यम, वहाँ की अदालतों की भाषा, वहाँ की असेम्बली की भाषा, प्रान्तीय भाषा हो। प्रान्तीय भाषा के सिवाय प्रान्तों में रहने वाली अन्य जनता की भाषा को उस प्रान्त में मान्य न किया जाये, यह भी मैं नहीं कहता, पर जिस प्रकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव में कहा और स्वीकार किया है कि अगर किसी प्रान्त में २० प्रतिशत व्यक्ति इस बात की इच्छा करें कि अमुक भाषा उस प्रान्त में स्वीकार की जाये, तभी यह हो। अगर एक प्रतिशत, दो प्रतिशत व्यक्ति इस बात की माँग करें कि उनके प्रान्त में दूसरी भाषा भी चले, तो उनके प्रान्त के विकास में बाधा डालना होगा; इसलिये मैंने एक और संशोधन भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी प्रान्त में २० प्रतिशत व्यक्ति यह माँग करें कि अमुक भाषा वहाँ और स्वीकार की जाये, तो जैसा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने एक प्रस्ताव में मान लिया है, वहाँ पर यह बात की जा सकती है। अंग्रेजी का स्थान हिन्दी जल्दी-से-जल्दी ले ले, यह हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके लिये मैंने अपने संशोधन में जो बात कही है, वह यह है कि एक कमीशन स्थापित हो, एक पार्लियामेन्टरी कमेटी स्थापित की जाये, एक प्रकार की दो चीजें न हो, बल्कि एक ही चीज हो, यानी पार्लियामेन्टरी कमेटी। पार्लियामेन्टरी कमेटी को यह काम सौंप दिया जाय कि वह १५ वर्ष के अन्दर धीरे-धीरे हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर किस प्रकार ला सकती है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्र भारत कैसा होगा इसकी भी हमने कल्पना की थी, इस देश की जनता ने भी कल्पना की थी। वह कल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि हम भाषा के प्रश्न को हल न कर

ले। स्वराज्य का अर्थ इस देश के लोग तभी समझेंगे, जबकि भाषा का प्रश्न पूरी तरह से हल हो जायेगा।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिन्दी भाषा को इस देश के सभी निवासी राष्ट्रभाषा के रूप में, राज्यभाषा के रूप में, स्वीकार करने के लिये तैयार है। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि भाषा के विषय में किसी प्रकार की कटुता न आने पाये। जहाँ तक हिन्दी का सवाल है, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी आशीर्वाद प्राप्त है। और आज नहीं, यह आशीर्वाद उसे १८ वर्ष पहले प्राप्त हो चुका था। इस सम्बन्ध में उन्होंने १८ वर्ष पहले जो एक पत्र लिखा था, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ—

“कोलम्बो १६-५-३१

मुझे बहुत खेद है कि मैं इस समय मदुरा नहीं आ सकता। मैं चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ और तमिलनाडु प्रान्त के भाइयों से मिलूँ और अगर उनकी कुछ सेवा कर सकूँ, तो वह कल्लूँ। खासकर मैं हिन्दी-सम्मेलन में हिस्सा लेना पसन्द करता। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होना तो पूरी तौर से तय हो गया है और कांग्रेस का कार्य भी अब बहुत-कुछ हिन्दी में होता है। यह बहुत खुशी की बात है कि तमिलनाडु-प्रान्त में हिन्दी का प्रचार खूब हो रहा है। इस शुभकार्य में मैं खुशी से सहायता देता, लेकिन मजबूरी से नहीं आ सकता।

मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी-सम्मेलन सफलता से होगा और उसके कारण हिन्दी-प्रचार और भी बढ़ेगा।

—जवाहरलाल नेहरू”

यह पंडितजी ने १८ वर्ष पहले लिखा था और मुझे इस बात को देखकर हर्ष होता है कि १८ वर्ष पहले उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, उसको आज हम पूरा करने के लिये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।

## राज-भाषा विधेयक पर

२३ अप्रैल, १९६३

डा० गोविन्ददास—उपाध्यक्ष महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय ने जाते हुए एक बात कही थी कि यह मामला बड़ा नाजुक है। मैं उन से ..

Shri S. Kandappan (Tiruchengode) : Sir, I want to make one request.

डा० गोविन्ददास—जी नहीं, मैं अपनी भाषा में बोलूंगा।

Mr Deputy-Speaker : Order, order. He is not yielding.

डा० गोविन्ददास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्षों तक यहाँ पर ...

Shri S. Kandappan : Sir, we are discussing a very important Bill, on which point I think even Dr. Govind Das will agree. We have to make one request to him. We will not be able to follow his speech here. Even if he prefers to deliver his speech in Hindi, at least he can give us a translation of it in English so that we are able to follow what he says.

Mr. Deputy-Speaker : It is left to Dr. Govind Das. Both Hindi and English can be used here for speeches.

Shri Thirumala Rao (Kakinada) : Sir, may I make one appeal to you. Dr. Govind Das is going to advance arguments on behalf of Hindi, and they are mainly addressed to the non-Hindi-speaking areas. He is one of the leaders of the movement. I think all Members in this House including the Members from the South are to fully understand the weight of his arguments. I would, therefore, request him to speak in English (*Interruption*).

डा० गोविन्ददास—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि मैं बीसो वर्षों तक यहाँ पर अंग्रेजी में बोलता रहा हूँ, और उस के बाद मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने देश में अपनी भाषा में बोलूंगा और विदेशों में अंग्रेजी में बोलूंगा ; इसलिए अपनी

प्रतिज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अन्त में जो बातें मैं यहां कह रहा हूँ, उनको अंग्रेजी में भी कह दूंगा।

मैं कह रहा था, आप से, कि अध्यक्ष जी एक बात कह कर गये हैं कि यह मामला बड़ा नाजुक है। इसमें कोई सदेह नहीं है। मेरे लिए यह इसलिये और भी नाजुक हो जाता है कि जिन पंडित जवाहरलालजी के नेतृत्व में मैंने पिछले ४३ वर्ष तक काम किया, सार्वजनिक क्षेत्र में, जिन श्री लालबहादुरजी के साथ-साथ मैं न जाने कितने वर्षों तक काम करता रहा हूँ, उनके विरोध में शायद मुझे यहां कुछ कहना पड़ेगा।

शास्त्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि इस मामले में सदस्यों की स्ट्राग व्यूज है। बिल्कुल ठीक है। इस सम्बन्ध में बड़ा बुनियादी मतभेद है, और मैं उनमें से एक हूँ। मैंने ५० वर्ष तक, अपनी सारी जिन्दगी में, यह काम किया है, जिसके विरुद्ध जाना मेरे लिए, जीवन के इस सन्ध्या-काल में, सम्भव नहीं है; लेकिन मैं इतना पंडितजी और शास्त्रीजी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस विधेयक का विरोध करते हुए भी, उनके मतों का विरोध करते हुए भी, उनके प्रति मेरी वैसी ही श्रद्धा है, वैसा ही विश्वास है, जैसा कि अब तक रहा है, और भविष्य में भी वैसा ही रहने वाला है। मैं जीवन भर कांग्रेसवादी रहा हूँ, और चाहे आज मैं इस विधेयक के विरुद्ध होऊँ, लेकिन इसके बाद भी मैं कांग्रेस में ही रहने वाला हूँ, किसी दूसरी सस्था में जानेवाला नहीं हूँ।

अभी यहां कुछ लोगो ने कहा कि हिन्दी कभी केन्द्र में आनेवाली नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं, वे हिन्दी के ही विरोधी नहीं हैं, मैं तो कहूंगा कि भारत का विभाजन चाहते हैं और स्वयं अपनी भाषा के विरुद्ध हैं। कुछ उनमें ऐसे भी हैं, जो इस देश में निवास करते हैं और उनकी दृष्टि अभी भी इंग्लैंड की तरफ है।

शास्त्रीजी ने उदारता की बात कही। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आज एक लम्बा भाषण देने वाला हूँ, क्योंकि यह मेरा विषय रहा है, लेकिन मैं उनको इस बात का आश्वासन देता हूँ, कि आरम्भ से अन्त तक वे उसमें कटुता का एक शब्द कही नहीं पायेंगे।

मानव-समाज में जब कभी भी कोई बड़ी बात हुई है, तब उसके लिए वातावरण तैयार किया गया है। हमारे देश की आधुनिक स्वतन्त्रता का भी यही इतिहास है। हमारे देश का वर्तमान वायु-मंडल तैयार किया था राष्ट्रपिता ने, जिन्होंने इस नये भारत का निर्माण किया है; और उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कहा था, यदि मैं यहां उसे पढ़ दूँ, तो कोई अनुचित बात न होगी। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज जो कुछ मैं कहूंगा, वह अपनी ओर से बहुत कम होगा,

जो कुछ मैं यहां पर कहूँगा, वह यहा के महापुरुषों की ओर से ही कहूँगा। गांधीजी ने सन् १९१८ में कहा था, जब कि देश का नेतृत्व उनके हाथ में आ रहा था—

“यह भाषा का विषय बड़ा भारी और बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। यदि सब नेता सब काम छोड़कर केवल इसी विषय पर लगे रहे, तो बस है। यदि हम लोग भाषा के प्रश्न को गौण समझे, या उधर से मन हटा लेंगे, तो इस समय लोगो में जो प्रवृत्ति चल रही है, लोगो के हृदयों में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वह निष्फल हो जायेगा। भाषा माता के समान है। माता पर जो प्रेम होना चाहिए, वह हम लोगो में नहीं है।—हम अंग्रेजी के मोह में फसे हैं। हमारी प्रजा अज्ञान में डूबी है। हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय सभाओं में, कांग्रेस में, प्रान्तीय सभाओं में और अन्य सभा-समाज और सम्मेलनों में अंग्रेजी का एक भी शब्द सुनाई न पड़े। हम अंग्रेजी का व्यवहार बिल्कुल त्याग दे।”

यह हमारे राष्ट्रपिता ने सन् १९१८ में कहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि भारत को सच्चा भारत रहना है, तो वह भारतीय भाषाओं के बिना नहीं रह सकता। यह प्रश्न हिन्दी का नहीं है। यह बहुत गलत कहा जाता है कि हिन्दी वाले यह चाहते हैं और हिन्दी वाले वह चाहते हैं। यह प्रश्न भारतीय भाषाओं का है। एक ओर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ हैं, और दूसरी ओर अंग्रेजी है। अंग्रेजी केवल भाषा के रूप में यहा नहीं है। अंग्रेजी के साथ सारी अंग्रेजियत बंधी हुई है। उसके साथ अंग्रेजी संस्कार बंधे हुए हैं, अंग्रेजी संस्कृति बंधी हुई है और अंग्रेजी सम्यता बंधी हुई है। भारतीय भाषाओं के साथ भारतीयता है; इसलिये यदि हमें इस देश को सच्चा भारत बनाना है, तो मैं कहूँगा कि ऐसा हम अंग्रेजी द्वारा किसी प्रकार भी नहीं कर सकते। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कोई संघर्ष नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, जब हिन्दी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं के संघर्ष की बात कही जाती है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की एक ही संस्कृति है। वे सब एक ही संस्कृति से निकली हैं। शब्द-भंडार भी उन सब का एक है। उत्तर की भाषाएँ तो संस्कृत से निकली हैं, दक्षिण की भाषाओं में प्रचुर परिमाण में संस्कृत की शब्दावली है।

एक माननीय सदस्य—वर्णमाला भी एक है।

डा० गोविन्ददास—फिर एक भाषा बढ़ती है, तो सारी अन्य भाषाएँ भी बढ़ती हैं। मैं आपको एक दृष्टांत दूँगा। केन्द्रीय सरकार इस समय शब्दावली बना रही है। उस शब्दावली को कुछ थोड़े हेर-फेर के साथ सब राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार, जब एक भाषा बढ़ती है, तब अन्य भाषाएँ भी बढ़ती हैं।

फिर भाषा प्रयोगशाला में नहीं बढ़ती। भाषा बढ़ती है तब, जब वह व्यवहार के क्षेत्र में आती है। प्रयोगशालाओं में कभी दुनिया में भाषा नहीं बढ़ी। मैं इतिहास का एक छोटा-सा विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने भाषाओं का इतिहास पढ़ा है, और क्योंकि यह मेरा विषय रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भाषा प्रयोगशाला में नहीं बढ़ी, भाषा बढ़ी है व्यवहार में। फिर प्रांतीय भाषाओं की बढ़ती भी केन्द्र में हिन्दी की बढ़ती से होगी। अगर केन्द्र में अंग्रेजी में सब कुछ चला, तो अन्य भारतीय भाषाएँ नहीं बढ़ सकती। प्रांतीय भाषाओं का भी विकास नहीं हो सकता। फिर तो सारे प्रांत अंग्रेजी की ओर देखेंगे। इस सम्बन्ध में भी राष्ट्र-पिता का ही एक कथन सुनिए—

“अंग्रेजी को प्रांतीय भाषाओं का या हिन्दी का स्थान नहीं देना चाहिए। अगर अंग्रेजी ने यहाँ लोगों की भाषाओं को निकाल न दिया होता, तो प्रांतीय भाषाएँ आज आश्चर्यजनक रूप में समृद्ध होती। अगर इंग्लैंड फ्रेंच भाषा को अपने राष्ट्रीय काम-काज की भाषा मान लेता, तो आज हमें अंग्रेजी का साहित्य इतना समृद्ध न मिलता। नार्मन विजय के बाद वहाँ फ्रेंच भाषा का ही जोर था, लेकिन उसके बाद लोक-प्रवाह विशुद्ध अंग्रेजी के पक्ष में हो गया। अंग्रेजी साहित्य को आज हम जिस महान् रूप में देखते हैं, वह उसी का फल है।”

सविधान-सभा में जब भाषा विषयक विवाद चल रहा था, उस समय एक प्रश्न उठा कि आठवें शिड्यूल में हम अंग्रेजी को भी स्थान दें। उस समय जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, उस को भी आप सुन लीजिए। हमारे प्रधान मंत्री-जी ने स्पष्ट रूप में कहा था—

“There is an insidious move on the part of some to include English as one of the languages of the Eighth Schedule. This is obviously a wrong thing to do, as English is not an Indian language, though it is acquired and owned as mother tongue by some Indians like the Anglo-Indian community. It should be enough if we recognise the need of learning English, or a modern European language. It would be absurd, therefore, and unwarranted too, to include English as an Indian language in the Schedule. In this move to include English is to by-pass the basic principles of the replacement of English by India's national language. It will be wholly in contravention of the

spirit and contents of the Constitution and the modern history of our people during the last half a century.”

यह हमारे प्रधान मंत्रीजी का कथन है और किसी का कथन नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता की हम रक्षा कब कर सकते हैं? स्वतंत्रता की रक्षा अंग्रेजी के दौर-दौरे से होनेवाली नहीं है। स्वतंत्रता की रक्षा तब होगी, जब उस स्वतंत्रता को, उस स्वराज्य को यहां के लोग अपनी स्वतंत्रता और अपना स्वराज्य मानेंगे। इस सम्बन्ध में भी आप राष्ट्रपिता का कथन सुनिए। उन्होंने कहा था—

“अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो, तो निस्सन्देह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी ; लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वालों, करोड़ों निरक्षरों, निरक्षर बहनों और दलित व अन्त्यजों का हो और इन सब के लिए होने वाला हो, तो हिन्दी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है।”

स्वतंत्रता के साथ चार प्रमुख बातें आती हैं, जो हमें देखनी हैं। पहली बात है भारतीय एकता, दूसरी बात है भारत में समाजवादी समाज की रचना, तीसरी बात है भारत में प्रजातन्त्र की सफलता और चौथी बात है भारत की आर्थिक उन्नति। हम एक-एक बात को ले लें। क्या भारतीय एकता अंग्रेजी से रह सकती है? बार-बार यह कहा जाता है कि यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा है कि भारत की एकता बनी रहे। यह कैसी एकता है? आप देखें कि अंग्रेजी के द्वारा कैसे एकता रहेगी? अंग्रेजी भाषा ने यहां के पढ़े-लिखे लोगों में और यहां की जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई खोद दी है। एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। जब तक हम उस खाई को पाट नहीं देंगे और जब तक हम उस दीवार को ढहा नहीं देंगे, तब तक भारतीय एकता नहीं कायम रह सकती। आज क्या हाल है, आप देखें कि जितना काम हो रहा है, जितना भारत की एकता का प्रयत्न हो रहा है, वह सब-का-सब एक छोटे-से तबके की ओर से, एक छोटे-से तबके द्वारा हो रहा है, जो कि अंग्रेजी भाषा का प्रेमी है। इसमें बहुत कम हिस्सा यहां की आम जनता का है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कोई भी विदेशी भाषा काम नहीं दे सकती ; इसीलिए हमने संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया था ; क्योंकि वह यहां के ४२ प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है, और देश के कुछ छोटे-छोटे क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी समूचे देश में समझी जाती है।

इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी का भी एक कथन सुनिए—

“यह बात नहीं कि मैं भाषा के पीछे दीवाना हो गया हूँ। . . . फिर भी मैं

भाषा पर इतना जोर इसलिए देता हूँ कि राष्ट्रीय एकता हासिल करने का यह एक बहुत जबरदस्त साधन है। और जितना दृढ़ इसका आधार होगा, उतनी ही प्रशस्त हमारी एकता होगी।”

आज यह खेद का विषय है कि गांधीजी की इन बातों को हम भूल गये हैं। अब जब एकता नहीं लाई जा सकती, तब फिर समाजवाद इससे कैसे लाया जा सकता है? जब अंग्रेजी भाषा को लोग समझते नहीं हैं, तब समाजवाद की स्थापना अंग्रेजी के द्वारा कैसे होगी, यह समझ में नहीं आता है। फिर जो प्रजातंत्र के चलने की बात है, वह तो अंग्रेजी द्वारा चलना संभव ही नहीं है, क्योंकि इस देश के ९८ फी सदी लोग अंग्रेजी नहीं जानते। अगर हमको प्रजातंत्र चलाना है, अगर हमारे यहाँ बालिग मताधिकार है, तो उस भाषा में प्रजातंत्र चल सकता है, जो कि इस देश की भाषा हो, या इस देश की मातृभाषाएं हो। अंग्रेजी के द्वारा इस देश में प्रजातंत्र नहीं चल सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी केन्द्रीय सरकार के कामों में, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में, और हमारी अन्य दूसरी बातों में, यहाँ की जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है।

फिर चौथी बात रही, आर्थिक उन्नति की। यह आर्थिक उन्नति, बिना विज्ञान की उन्नति के नहीं हो सकती। और विज्ञान की उन्नति के लिए हमें वैज्ञानिक चाहिए। अभी शिक्षा-मंत्रालय के अनुदानों पर बोलते हुए मैंने निवेदन किया था कि हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० कोठारी इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं। डा० कोठारी ने जो कहा था, इस अवसर पर मैं उसको उद्धृत नहीं करना चाहता; क्योंकि थोड़े ही दिन पहले मैं उसको कर चुका हूँ। हमारे वैज्ञानिक तीव्र गति से तभी तैयार हो सकते हैं, जब उन्हें वैज्ञानिक शिक्षा हिन्दी और हमारी अन्य भारतीय भाषाओं के द्वारा मिले।

इस सम्बन्ध में भी महात्मा गांधी का मत है—

“यह कभी नहीं हो सकता कि हजारों लोग अंग्रेजी भाषा को अपना माध्यम बनाये, और यह अगर मुमकिन हो, तो भी चाहने लायक तो कतई नहीं। इसकी सीखीसादी वजह यह है कि अंग्रेजी के जरिए मिलने वाला उच्च और पारिभाषिक ज्ञान, आम लोगों तक नहीं पहुँच सकता। यह तो तभी हो सकता है कि जब इस ज्ञान का प्रसार, ऊपर के दरजेवालों में भी किसी देशी भाषा के द्वारा हो।”

जब संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया और हिन्दी के साथ शेष तेरह भाषाओं को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया, तब हिन्दी के प्रति और हमारी अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति लोगों के मन में कितने उत्साह और जागृति



की लहर उठी थी। लोग हिन्दी और भारतीय भाषाओं की ओर झुके थे ; लेकिन जब से यह चर्चा चलने लगी कि फिर से अंग्रेजी यहाँ हमेशा के लिए चलने वाली है, तब से यह जोश, जो हमारी जनता में हिन्दी के राज-भाषा और सारी भारतीय भाषाओं के राष्ट्रभाषा होने पर हुआ था, वह ठंडा होकर खत्म हो रहा है। फिर से लोग अंग्रेजी की ओर मुड़ रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी इसलिए पढ़ाते हैं कि इस गरीब देश में सरकारी नौकरियाँ अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को ही मिलती हैं। छोटी-से-छोटी नौकरी भी बिना अंग्रेजी के ज्ञान के नहीं मिल सकती, तब अगर लोग अंग्रेजी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें लोगों का दोष नहीं है ; बल्कि यह हमारा दोष है।

यह कहना गलत है कि अकेले अहिन्दी भाषा-भाषी लोग हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। हिन्दी के प्रचलन का, हिन्दी को केन्द्र में चलाये जाने का विरोध केवल अहिन्दी भाषा-भाषी लोग ही नहीं ; वरन् हिन्दी भाषा-भाषी भी कर रहे हैं। और यह विरोध कौन लोग कर रहे हैं। यह विरोधी वही दो प्रतिशत लोग कर रहे हैं, जिनके हाथ में सारी राजसत्ता है, जिनके हाथ में देश का सारा काम-काज है, जो आज भी अपना आधिपत्य इस अंग्रेजी के द्वारा इस देश में बनाये रखना चाहते हैं। वे हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचलन नहीं होने देना चाहते ; क्योंकि उनका स्वार्थ अंग्रेजी से सघता है ; इसलिए यह कहना कि केवल अहिन्दी भाषा-भाषी विरोध कर रहे हैं, यह बात सही नहीं है। अहिन्दी भाषा-भाषी भी कर रहे हैं और हिन्दी भाषा-भाषी भी कर रहे हैं। वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका स्वार्थ अंग्रेजी से सघता है। फिर यह बात भी गलत है कि सारे हिन्दी भाषा-भाषी प्रायः हिन्दी के विरोधी हैं। दक्षिण में मद्रास को छोड़ कर केरल, मैसूर और आन्ध्र हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। पूर्व में बंगाल को छोड़ कर असम और उड़ीसा हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। केवल बंगाल और तमिलनाडु तक ही यह विरोध केन्द्रित है। पहले मैं बंगाल को लेता हूँ। यह आवाज पहले-महल बंगाल से उठी थी कि भारतवर्ष में एक भाषा की ज़रूरत है और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। केवल बंगाल भाषा के ही नहीं ; वरन् हमारे भारत के एक महान् साहित्यकार श्री बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने हिन्दी के विषय में अपने एक भाषण में कहा था—

“अंग्रेजी के विषय में लोगों की जो कुछ भावना हो, पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिन्दी के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। हिन्दी की पुस्तकें

लिख कर और हिन्दी बोल कर भारत के अधिकांश भाग को निश्चय ही लाभ हो सकता है। यदि हम देश में बंगला और अंग्रेजी जानने वालों की संख्या का पता चलाये, तो साफ प्रकट हो जायगा कि वह कितनी न्यून है। जो सज्जन हिन्दी भाषा द्वारा भारत में एकता पैदा करना चाहते हैं, वे निश्चय ही भारतवन्धु हैं। हम सब को संगठित होकर इस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए।

न्यायमूर्ति श्री शारदाचरण मित्र तो देवनागरी लिपि के इतने प्रेमी थे कि उन्होंने “देवनागरी” नामक मासिक-पत्र निकाला, जिसमें समस्त भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि में छपता था। सारे भारत की भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि में निकालने का प्रयत्न किया था। अब फिर से वह त्रैमासिक पत्र सप्तद्वीप हिन्दी-परिषद् द्वारा निकला है। उन्होंने उस समय हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में कहा था—

“हिन्दी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। कलकत्ते की “एक लिपि विस्तार-परिषद्” समस्त भारतवर्ष में एक नागरी लिपि का प्रचार करने में तन मन से लगी हुई है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि मेरे दफ्तर की भाषा हिन्दी है। इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा, जिस दिन मैं हिन्दी स्वच्छन्दता के साथ बोलने लगूंगा और प्लेटफार्म के ऊपर खड़ा होकर हिन्दी में वक्तृता दूंगा। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा। जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ-साथ हिन्दी में वार्तालाप करूँगा।”

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस बारे में क्या कहा था उसे भी सुन लीजिए—

“सबसे पहले मैं एक गलत-फहमी दूर कर देना चाहता हूँ, कितने ही सज्जनों का खयाल है कि बंगाली लोग या तो हिन्दी के विरोधी होते हैं, या उस के प्रति उपेक्षा करते हैं। यह बात भ्रमपूर्ण है और इसका खंडन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं व्यर्थ अभिमान नहीं करना चाहता ; पर इतना तो अवश्य कहूँगा कि हिन्दी साहित्य के लिये जितना कार्य बंगालियों ने किया है, उतना हिन्दी भाषी प्रांत को छोड़ कर और किसी प्रांत के निवासियों ने शायद ही किया हो। . . . मैं इस बात को मानता हूँ कि बंगाली लोग अपनी मातृभाषा से अत्यन्त प्रेम करते हैं और यह कोई अपराध नहीं है। शायद हम में से कुछ ऐसे आदमी भी हैं, जिन्हें इस बात का डर है कि हिन्दी वाले हमारी मातृभाषा बंगला को छुड़ा कर उसके स्थान पर हिन्दी रखवाना चाहते हैं, यह भ्रम भी निराधार है। हिन्दी-प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि जो काम आज अंग्रेजी से लिया जाता है, वह आगे चल कर हिन्दी से लिया जाय।” . . . .

“प्रातीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिन्दी-प्रचार से मिलेगी, उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती। अपनी-अपनी प्रातीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिये, उस में कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिन्दी को ही मिला है। . . . यदि हम लोगो ने तन-मन-धन से प्रयत्न न किया, तो वह दिन दूर नहीं है, जब भारत स्वाधीन होगा और उस की राष्ट्रभाषा होगी हिन्दी।”

यह हमारे नेताजी का कहना था। जैसा मैंने कहा—यह कहा जाता है कि तमिलनाडु इसके खिलाफ है। इसके लिए मैं बतलाना चाहता हूँ कि सन् १९५८ में तमिलनाडु में “दि लैंग्वेज कन्वेन्शन” नाम से एक परिषद् हुई थी। उस परिषद् के स्वागताध्यक्ष श्री के० भाष्यम् और उस परिषद् के अध्यक्ष भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री के० सन्तानम् थे, जो कि आजकल हमारी राज्य सभा के सदस्य हैं। श्री भाष्यम् ने अपने भाषण में कहा था—

“The danger is pointed out that imposition of Hindi will lead to disruption of the country. Is this correct? On the other hand, if Hindi is progressively introduced in the Union administration and communication between the States is also in Hindi it is possible to express in Hindi mass feeling of the inhabitants of the region to the inhabitants in another region in a much more effective way than English.”

और श्री सन्तानम् ने अपने भाषण में क्या कहा था, वह भी सुनिये—

“Hindi has functioned for the past many decades as the lingua franca of India at the mass level. Even the British Government recognised this fact by making it the lingua franca of the Indian military forces. Under Mahatma Gandhi's leadership, intense propaganda for Hindi has been carried on for the past 40 years and thousands of boys and girls in non-Hindi States have been educated in Hindi to a level similar to the S. S. L. C.”

“The Hindi taught in the school will be continually nourished by the Hindi spoken in the bazaar and the Hindi heard in the Cinema, the radio and other places. On the other hand

no English will be heard anywhere except in select gatherings of professors and scholars ”

इसके बाद आप शेष अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के सम्बन्ध में कुछ बातें सुन लीजिए। कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले ही—कर्नाटक दक्षिण में है—एक आल-कर्नाटक हिन्दी कन्वेंशन हुआ। जिसके अध्यक्ष थे बंगलोर के भूतपूर्व मेयर, श्री आर० अनन्त रामन्, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० और जिस का उद्घाटन किया मैसूर लेजिस्लेटिव कौंसिल के चेयरमैन, श्री जी० बी० हल्लीकेरो, ने। वहाँ पर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसको सुन लीजिए—

“Although Hindi has been the declared official language of the Indian Union, provision has been made for the continued use of English in the form of an official language until 1965. But now there is a move to amend the Constitution so as to retain and raise English to the status of an Associate Official language, it is said, as a result of extraordinary pressure from a section of the Non-Hindi speaking public. The Karnataka Hindi Convention views this with concern. The Convention is of the opinion that to give place in the Constitution an official status to a foreign language is below the self-respect of any nation and a hindrance to the healthy growth of the official language as well as the regional languages.

×

×

×

Therefore, this Convention earnestly urges upon the Government to give up their efforts to make English an associate official language for an unspecified period.”

इसी प्रकार कटक में एक सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पद्मश्री श्री आर्त्त-वल्लभ महान्ति, एम० ए०। उस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया—

“यह सम्मेलन अंग्रेजी भाषा शिक्षा का विरोध न करते हुए भी अंग्रेजी भाषा को अनिर्दिष्ट काल के लिए हिन्दी के साथ सहयोगी या अतिरिक्त भाषा के रूप में ग्रहण करने का एकान्त विरोधी है। यदि अंग्रेजी को अतिरिक्त भाषा के रूप में ग्रहण करने का प्रयोजन हो, तो इसे केवल १९६५ से और पांच वर्ष अर्थात् १९७० तक ही रखा जा सकता है।”

इस विषय में स्वामी विचित्रानन्द दास, एडवोकेट ने अपना यह सशोधन

पेश किया था, कि पांच वर्ष के स्थान पर दस वर्ष रखा जाये, किन्तु उपस्थित साहित्यिको मे से किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया।

हाल ही मे विहार राष्ट्रभाषा परिषद् का एक अधिवेशन हुआ, जिसके सभा-पति श्री अनन्तशयनम् आर्यगर थे, जो आध्र के रहने वाले है, तेलुगु-भाषा-भाषी है। वह बहुत दिनों तक हमारे स्पीकर थे। उन्होंने अपने अभिभाषण मे कहा—

“हिन्दी भाषा की समृद्धि से अप्रत्यक्ष रूप मे उत्तर भारत की सभी अन्य भगिनी-भाषाओ की समृद्धि होगी और दक्षिणी भाषाओ की भी इससे समृद्धि होगी, क्योंकि उन के काम-काज की भाषा हिन्दी ही होगी।” आगे चल कर उन्होंने कहा—

“हिन्दी के प्रति भारत के किसी कोने मे वास्तविक घृणा नहीं है और सामान्य रूप से सभी मानते है कि इस का प्रसार अवश्य होना चाहिए एव यह पूर्ण रूप से राष्ट्र के काम-काज की भाषा बने। ऊपर से जो विरोध कुछ ओर से देखने मे आता है, उस का कारण यह है कि हिन्दी-साहित्य को अधिकाधिक समृद्ध करने के पूर्व अंग्रेजी से हिन्दी पर उतर आने का हठ अथवा खीचा-तानी हो रही है।”

अभी दक्षिण के एक विद्वान् और मैसूर विश्वविद्यालय के अवकाश-प्राप्त प्रोफेसर श्री चन्द्रहासन दिल्ली पधारे थे। उन्होंने एक वक्तव्य मे कहा—

“अगर अंग्रेजी को जबरदस्ती लादा जा सकता है, तो क्या कारण है कि हिन्दी को नहीं लादा जा सकता, जब कि बात ऐसी नहीं है। हिन्दी तो भारत की भाषा है, भारत की अधिक जनसंख्या द्वारा समझी और बोली जानेवाली भाषा है। संविधान मे जब १९६५ के बाद हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रयोग करने की व्यवस्था कर दी गई, तो अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हिन्दी को राजभाषा नहीं बनने दिया जायगा। . . . द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम हिन्दी का विरोध करता है; पर वह तो भारत की अखंडता का भी विरोधी है। वह तो अलग द्रविड़स्तान चाहता है। उसे देश की एकता मे विश्वास नहीं है।”

गाडगिल साहब महाराष्ट्रीय है, हिन्दी भाषा-भाषी नहीं है। वे बहुत समय तक इस सदन के सदस्य थे और पंजाब के राज्यपाल भी रहे है। उन्होंने अपने एक भाषण मे कहा है—

“हिन्दी एक सघटित करने वाली शक्ति है। जन-साधारण को एक विशाल जीवन की तरफ ले जाने का मार्ग है। . . . वह अब किसी एक प्रदेश

की न होने की वजह से सारे देश की होगी और सारे देश का बौद्धिक और व्यवहारी जीवन समृद्ध करेगी। हिन्दी का प्रचार-कार्य एक वाङ्मयज्ञ है।”  
उपाध्यक्ष महोदय—अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करे।

डा० गोविन्ददास—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो दृष्टिकोण है, उस को कोई आपके सामने नहीं रखेगा और कम-से-कम कांग्रेस वाले तो नहीं रखेंगे, इसलिए मुझे अपनी बात कहने के लिए कुछ समय और दिया जाये।

गुजरात विद्यापीठ के उपकुलपति, श्री देसाई ने अपने एक लेख में कहा है—

“दुख तो यह है कि यह भी कहा जाता है कि हिन्दी तैयार नहीं है, या पूरी तरह विकसित नहीं है। स्वभाषा का ऐसा अपमान करते हुए शर्म आनी चाहिए और कभी कोई भाषा बिना उस का उपयोग किये कहीं विकसित हुई देखी है? इसलिए सरकार को प्रामाणिकता से हिन्दी के उपयोग के लिए पूरा मौका देना चाहिए। अभी तक कानून से ऐसा नहीं किया गया है। इस बाधा को दूर करने की जरूरत है। इसके बजाय हिन्दी कभी आ ही न सके, ऐसा कानूनी कदम उठाया जा रहा है।”

वे आगे कहते हैं—

“ऊपर की विचारणा से उल्टा यह दिखाई देता है कि अंग्रेजी को सह-भाषा के रूप में ग्रहण करना। यह किसी तरह का उपाय ही नहीं है। इससे तो भाषाकीय अघेर और कारबार में अराजकता ही पैदा होगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा वैसे भी देश की जनसंख्या के एक प्रतिशत तक पहुँची है और वह भी उसे ठीक तरह से नहीं आती। और प्रजा गति देखते हुए इसके बारे में हर साल शिथिलता ही बढ़ेगी। उसके चिह्न सर्वत्र नजर आते हैं। इस वजह से शिक्षा और राज-व्यवस्था दोनों में सुधार नहीं हो रहा है। प्रजा चीखती रहती है, मगर कोई सुनता ही नहीं। स्वराज्य की नौकरशाही, अंग्रेजीशाही बन चकी है। यह भी निभ नहीं सकेगी, क्योंकि माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए अंग्रेजी ही उसे (नौकरशाही को) कम आती जायगी।”

मेरे पास और भी बहुत से उद्धरण हैं, लेकिन चूँकि आप कहते हैं कि वक्त नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बम्बई, पूना आदि के अनेक लोगों ने हिन्दी को शीघ्र ही केन्द्र की राजभाषा के स्थान पर प्रस्थापित करने का अनुरोध किया है। उनमें से कुछ नाम ये हैं—श्री विमलशंकर ना० शास्त्री, श्री कान्तिलाल एम० जानी, श्री रतिलाल र० जोशी, श्री मधुसूदन एम० देसाई, श्री कोकिला र० पटेल, श्री नन्दकिशोर ओझा, श्री इन्दिरा र० पारेख, श्री विपिन-

चन्द्र वादवे, श्री किशोरीलाल वशिष्ठ आदि। ऐसे कितने ही लोग हैं, जिन्होंने यह कहा है कि अंग्रेजी सहभाषा के रूप में हमेशा के लिए, अनिश्चित काल के लिए मुकर्रर न की जाये।

मैं इन उद्धरणों को पढ़ना समाप्त करता हूँ—अन्त में केवल अंग्रेजी के दो उद्धरण पढ़कर सुनाऊँगा। आयरलैंड के विख्यात कवि, थामस डेविस कहते हैं—

“A nation without a mother-tongue cannot be called a nation. The defence of one's mother tongue is more essential than the defence of the boundaries of one's motherland, because the mother tongue is a more powerful barrier against the intrusion of foreigners than even the natural barriers of rivers and mountains”.

यह कहा जाता है कि हमारी भाषाएँ सक्षम नहीं हैं ; लेकिन अंग्रेजी के एक प्रमुख विद्वान् श्री क्रस्ट कहते हैं—

“Indian vernaculars are magnificent vehicles of speech and capable of expressing any human conception and being the vehicle of the highest scientific education.”

अन्त में मैं आप से यह कहूँगा कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस सकट-कालीन परिस्थिति में इस विधेयक को क्यों लाया जा रहा है। अभी १९६५ तक बराबर अंग्रेजी चल सकती थी ; इसलिए मैं इसका इस वक्त लाया जाना किसी प्रकार भी उचित नहीं समझता। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने हिन्दी के लिए कोई काम नहीं किया है। उस ने कुछ काम किया है, लेकिन यदि गत बारह वर्षों के एक युग में उसने सविधान की भावना के अनुसार उचित काम किया होता, तो आज इस विधेयक की आवश्यकता न होती। देश के प्रचंड बहुमत के विरोध में सरकार यह विधेयक ला रही है। इस देश के ९८ फीसदी लोग अंग्रेजी नहीं जानते और दो फीसदी अंग्रेजी जानने वालों के लिए ९८ फीसदी लोगों के ऊपर अंग्रेजी लादी जा रही है।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, इससे स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकेगी, इससे एकता की स्थापना नहीं हो सकेगी, इससे समाजवाद की रचना नहीं होगी, इससे हमारी आर्थिक उन्नति नहीं होगी, इससे इस प्रकार के कोई भी काम हो जायें यह सम्भव नहीं है। और प्रजातंत्र तो इसके द्वारा चल ही नहीं सकता है। विधेयक के द्वारा अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी लादी जा रही है। मुझे भय है कि गत बारह वर्षों में हिन्दी को चलाने के लिए जिस प्रकार कोई योग्य कार्य नहीं

हुआ, यदि यह विधेयक इसी तरह से स्वीकृत हुआ, इसमें कोई समय न रखा गया—दस वर्ष, पाच वर्ष या कोई भी अवधि निर्धारित न की गई—तो उसी प्रकार इस विधेयक के स्वीकृत होने के बाद भी कोई व्यावहारिक कार्य नहीं हो सकेगा। जो कुछ पिछले बारह वर्षों में हुआ है, वही भविष्य में होने वाला है और पंद्रह बीस वर्षों के बाद हमारे सामने वही परिस्थिति आयेगी, जो कि आज हमारे सामने है।

हिन्दी को चलाने के विषय में सरकार ने कभी कोई आयोजना नहीं बनाई। जो आयोग मुकर्रर हुआ, वह भी कोई आयोजना नहीं बना सका और इसी प्रकार ससद् की कमेटी भी कोई आयोजना नहीं बना सकी। हमारी पचवर्षीय योजनाओं में भी हिन्दी चलाने की कोई आयोजना नहीं बनी। बिना कोई आयोजना बनाये इस प्रकार के विधेयक को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो यह मानता हूँ कि आज भी सारा काम-काज हिन्दी में चल सकता है। मैं यह भी मानता हूँ कि हम ने गलती की कि जिस दिन से सविधान लागू किया, उसी दिन से सब काम हिन्दी में नहीं चलाया। आयरलैंड में उस के स्वतंत्र होने के बाद, दूसरे दिन से ही गैलिक में जब काम चल सकता है, इजराईल में उसके स्वतंत्र होने के बाद सब काम हिब्रू में चल सकता है, जो कि दोनों मृत भाषाएँ थी, तो हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ जो कि मृत भाषाएँ नहीं हैं, इनके द्वारा उस दिन से सारा काम चल सकता था और आज भी मैं समझता हूँ कि चल सकता है।

जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया है, मुझे दुःख है कि जिनके नेतृत्व में—पंडितजी के—मैंने आज तक अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, शास्त्रीजी मेरे साथी रहे हैं, उन के द्वारा लाये गये विधेयक का मुझे विरोध करना पड़ रहा है। तीन बार उन के मत से मुझे अपना विरोध करना पड़ा है। एक बार उस वक्त, जब कि सविधान सभा में अकों का प्रश्न आया था ; दूसरी बार उस वक्त, जब कि गो-वध-बन्दी सम्बन्धी मेरे विधेयक का सरकार ने विरोध किया था और तीसरी बार यह है। लेकिन, यह मेरी अंतरात्मा का प्रश्न है। यह वह प्रश्न है, जिस को सुलझाते-सुलझाते और जिसके लिए काम करते-करते पचास वर्ष का अपना सारा जीवन मैंने व्यतीत किया है और जिस प्रश्न को स्वराज्य के बाद मैं सब से महत्वपूर्ण प्रश्न समझता हूँ ; इसलिए अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करने के लिए, इस जीवन के संध्याकाल में, मैं बाध्य हूँ। मेरी निगाहों में पंडितजी इतने उदार हैं, शास्त्रीजी इतने उदार हैं कि वे मुझे गलत नहीं समझेगे और मेरा जो इस सम्बन्ध में मत है, उस का आदर करेंगे।

मुझे बड़े दुःख के साथ इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है।



## राज्य-भाषा विधेयक के अंतिम वाचन पर

२७ अप्रैल, १९६३

डा० गोविन्ददास—अध्यक्षजी, श्री एन्थनी साहब ने इस विधेयक का विरोध किया अपनी दृष्टि से, मैं इसका विरोध करता हूँ अपनी दृष्टि से। यह आश्चर्य की बात है। अंग्रेजी में एक कहावत है।—

“Two extremes meet.”

यह कभी-कभी सत्य हो जाता है।

जब मैं इसका विरोध करता हूँ, उस समय मुझे अत्यधिक दुःख होता है। मैंने उस दिन भी कहा था, और आज फिर कहता हूँ कि जिन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में मैंने सारी जिन्दगी काम किया, जिन श्री लालबहादुरजी शास्त्री के साथ मैं वर्षों काम करता रहा, उन के मतों के विरुद्ध आज मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि यह मेरी अन्त-रात्मा और मेरी कान्सेन्स का सवाल है। इस के पहले दो बार ऐसे मौके आये थे— एक तब, जब सविधान सभा में अकों का प्रश्न आया, और दूसरा तब, जब गो-वध-बंदी सम्बन्धी मेरा विधेयक यहां पर आया।

अभी श्री रंगा साहब ने कुछ कहा। मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि सविधान सभा के अवसर पर वह पहले व्यक्ति थे, जिनके पास मैं गया था और उन्होंने सब से पहले इस बात पर हस्ताक्षर किये थे कि इस देश की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी होगी। आज उनकी एक बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि जब यहां पर अंग्रेजी राज्य था, उस समय अंग्रेजी विदेशी भाषा थी, लेकिन आज वह विदेशी भाषा नहीं रही। अजीब तर्क है। मेरी समझ में नहीं आया कि अंग्रेजों के रहते यदि वह विदेशी भाषा थी, तो आज वह स्वदेशी भाषा कैसे हो गई? अजीब बात है।

जहां तक द्रविड़ मनेत्र कड़घम के सदस्यों का सम्बन्ध है और जहां तक एन्थनी साहब का सम्बन्ध है, एक भारत का विभाजन चाहते हैं और दूसरे आज भी भारत में रहते हुए इंग्लिस्तान की ओर देखते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे कुछ नहीं कहना है; लेकिन जो हृदय में राष्ट्रीय विचार रखते हैं, उनसे मैं आज फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जब तक अंग्रेजी का चलन इस देश में रहेगा, तब तक भारत

सच्चा भारत नहीं हो सकता, तब तक यहां की जनता स्वतंत्रता और स्वराज्य के अर्थ को नहीं समझ सकती, तब तक इस देश में सच्ची एकता नहीं हो सकती, क्योंकि जो दो फीसदी लोग अंग्रेजी जानते हैं और जो १८ फीसदी लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उनके बीच एक खाई खुदी हुई है, एक दीवार खड़ी हुई है। जब तक वह खाई न पट जायगी, जब तक वह दीवार न ढह जायगी, तब तक इस देश में सच्ची एकता नहीं हो सकती।

जो विधेयक इस देश में एकता लाने का प्रयत्न करने के लिए लाया गया है, मेरा नम्र निवेदन है—इसमें मतभेद हो सकता है—वह एकता को भग करने के लिए सब से बड़ा साधन है। इससे न जनता स्वराज्य का अर्थ समझ सकती है, न इस से देश में एकता हो सकती है, न इससे आर्थिक उन्नति हो सकती है, क्योंकि तीव्र गति से वैज्ञानिक तैयार नहीं हो सकते। न उससे प्रजातंत्र चल सकता है, इसलिए बड़े भारी हृदय से, बड़े दुःख के साथ, हृदय के ऊपर, अपनी छाती पर पत्थर रखकर मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है।

## बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् नवम् वार्षिकोत्सव पटना

### अध्यक्षीय भाषण

२८ मार्च, १९६०

देवियो और सज्जनो,

सर्वप्रथम मेरा यह कर्तव्य है कि प्राचीन और वर्तमान बिहार की पुण्यभूमि को नमन करूँ, जिस भूमि पर महाराजा विदेह, जगज्जननी महारानी सीता, तीर्थंकर महावीर स्वामी, भगवान् बुद्ध, सम्राट् चन्द्रगुप्त और सम्राट् अशोक ने जन्म लिया।

आपने इस अधिवेशन का सभापति बनाकर मेरा जो सम्मान किया है, उसके प्रति आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरा विचार है कि आपने मुझे यह सम्मान केवल इस कारण प्रदान नहीं किया है कि मैं हिन्दी-साहित्य की कुछ सेवा कर सका हूँ, वरन् इसलिए भी दिया है कि मेरा सतत प्रयास रहा है कि हिन्दी को अपना उचित स्थान राजकाज और प्रशासन-क्षेत्र में भी मिले। आज हम जिन परिस्थितियों में यहाँ समवेत हुए हैं, उनमें इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम सब मिल कर हिन्दी को अपना उचित स्थान दिलाने के लिये और भी अधिक प्रयास करें।

### अपने ही राज्य में अपनी भाषा की याचना एक विडम्बना

यह बात लगती तो कुछ अजीब-सी है कि हमे अपने देश में इस बात का प्रयास करना पड़े कि देशवासियों की भाषा राज्यभाषा भी हो। यदि देश पर विदेशी राज्य होता, तो ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता सम्भवतः समझ में आ सकती थी; किन्तु इतिहास की यह कैसी विडम्बना है कि जो देश विदेशियों के चंगुल से लगभग बारह वर्ष पूर्व मुक्त हुआ था, उस देश में भी हम को इस बात के लिए परिश्रम और प्रयास करना पड़े कि जनता की भाषा राज्यभाषा हो। जिस जाति की भाषा पूर्णतः अविकसित हो, जिस की अपनी संस्कृति और सम्यता न हो, जिसकी अपनी ऐतिहासिक परम्पराएँ और गौरवगाथा न हो, और जो बर्बरता की स्थिति से या तो निकली ही न हो, या कुछ समय पूर्व ही निकली हो, उस जाति के लिए सम्भवतः अपनी भाषा में अपना राजकाज चलाने के लिए प्रयास करना पड़े; किन्तु हमारे देश का इतिहास हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सम्यता ससार के किसी भी देश से यदि अधिक

पुरानी नहीं तो कम पुरानी नहीं है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र न था और न हो सकता था, जिसमें हमारी जाति ने उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त न की हो और अमूल्य विचार मानव-जगत् के सामने न रखे हो। क्या दर्शन, क्या विज्ञान, क्या काव्य, सभी क्षेत्रों में भारत ने ऐसे सूक्ष्म और चमत्कारिक विचार रखे कि आज भी सारे सभ्य जगत् पर उनकी छाप है और सारा सभ्य जगत् उसका ऋणी। ये सब सत्य हमारे पूर्वजों ने इस देग की भाषा या भाषाओं द्वारा ही व्यक्त किये थे। समझता हूँ कि इन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी भाषा द्वारा इतने सूक्ष्म और गूढ़ विचार व्यक्त किये कि आज भी उनके पूर्ण रहस्य को समझने के लिए विद्वानों को परिश्रम करना पड़ता है। अपनी बात को मँजे हुए और बहुत ही थोड़े शब्दों में व्यक्त करने की परिपाटी हमारे यहाँ इतनी घर कर गई कि मात्रा के लाघव को भी विद्वान् पुत्रलाभ के समान मानते थे। आज सक्षेपाक्षरों की जो प्रणाली प्रचलित है, उससे भी अद्भुत् प्रणाली हमारे यहाँ दो सहस्र वर्षों पहले प्रचलित थी और प्रत्याहारों द्वारा पाणिनि ऋषि व्याकरण-जगत् में वह चमत्कार कर गये, जिसकी पुनरावृत्ति, अनेक शताब्दियों तक प्रयास करने पर भी, कोई देश या जाति नहीं कर सकी। इस प्रकार हमारे देश के विद्वान् गागर में सागर भरने में समर्थ थे और मैं यह मानता हूँ कि आज भी है। यह बात न केवल संस्कृत के लिए ठीक है, वरन् हमारी अन्य भाषाओं के लिए भी उतनी ही ठीक है। कबीर ने हिन्दी में जितने उदात्त ; किन्तु सूक्ष्म दार्शनिक विचार अपनी सूक्तियों में रखे हैं, वैसे संभवतः उतने थोड़े शब्दों में अन्यत्र कहीं भी न मिलेंगे। मैं यह बात आपके समक्ष मिथ्या अभिमान या अतीत की गौरव-गाथा के लिए नहीं रख रहा; वरन् मैंने इनकी ओर संकेत केवल इसलिए किया है कि आप इस देश के अन्य वासी इस ऐतिहासिक विडम्बना पर विचार करें कि इतनी समृद्ध भाषाओं वाले देश में यह प्रयास क्यों करना पड़े कि देश की भाषा राजभाषा भी हो ; पर मैं इसे अपना दुर्भाग्य कहूँ, जनता का दुर्भाग्य कहूँ या अपनी भावी पीढ़ियों का दुर्भाग्य कहूँ कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो संभवतः सच्चे मन से या स्वार्थवश इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस देश की कोई भाषा राजद्वार में फटकने न पाये। अतः हम सबके लिए, जिन का जीवन-प्रयास और जीवन-लक्ष्य जनवाणी की सेवा करना रहा है, यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम पूरी लगन से इस प्रयास में लग जायें कि हमारे देश की भाषा और देश की भाषाओं का वह अपमान और निरादर अब अधिक दिनों तक न किया जा सके।

**हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों में भी अपनी भाषाओं का उपयोग**

इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान उन कुछ देशों की ओर खीचना चाहता हूँ, जो

अभी चार पाँच साल पहले ही स्वतन्त्र हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कम्बोज, लव प्रदेश, वियतनाम अभी कुछ वर्ष हुए स्वतन्त्र हुए थे। मेरा विश्वास है कि आप सब इस बात से भी परिचित हैं कि इन देशों के वासियों का इतिहास कम-से-कम इतना पुराना नहीं है, जितना कि हमारे देश का है। मैं यह भी समझता हूँ कि इन देशों की ससार को सांस्कृतिक देन हमारे देश की अपेक्षा कहीं कम रही। इन की भाषा और इनकी लिपि भी हमारे देश की भाषा और लिपि की अपेक्षा कम उन्नत थी। किन्तु, इन देशों ने इतने अल्पकाल में ही अपना सारा राजकाज अपनी भाषाओं में करना आरम्भ कर दिया है। वहाँ भी फ्रांस ने फ्रांसीसी भाषा को अपने राज्यकाल में प्रशासन, विधि और शिक्षा का माध्यम बना रखा था। वहाँ का शिक्षित वर्ग भी फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करने में अम्यस्त था, किन्तु यह सब होते हुए भी वहाँ के नये शासकों ने एक दिन भी यह नहीं कहा कि फ्रांसीसी भाषा को ही प्रशासन, न्याय या शिक्षा का माध्यम बना रखा जाय या फ्रांसीसी भाषा के द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत् से सम्बन्ध स्थापित किया जाय या ज्ञान-सरोवर को केवल फ्रांसीसी भाषा की खिडकी द्वारा ही देखा जाय। मैं समझता हूँ कि ससार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो यह कहने की सामर्थ्य या दृष्टता रखता हो कि फ्रांसीसी भाषा ज्ञान या किसी अन्य क्षेत्र में अंग्रेजी से किसी प्रकार कम है। सच तो यह है कि आज भी लगभग सारे मध्यपूर्व और योरप के देशों में फ्रांसीसी भाषा राजनय की भाषा है और अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ बहुत थोड़ा है और अभी कुछ

वर्षों से किन्हीं-किन्हीं क्षेत्रों में आरम्भ हुआ है। किन्तु, ऐसी समृद्ध भाषा का भी मोह उन्हें अपनी देशभाषा को अपनी राजभाषा बनाने से एक मुहूर्त के लिए भी न रोक सका। चीन की बात मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। अभी हाल में उस देश का व्यवहार कुछ ऐसा रहा कि जिससे हमारे मन में कडावाहट पैदा हो गई है; किन्तु इस पर भी हमें यह सर्वदा स्मरण रखना चाहिए कि हम उसकी प्रगति और उस के प्रगति के कारणों को अपने ध्यान में रखें, क्योंकि यदि हमने ऐसा न किया, तो हम उन का उचित समय पर उचित प्रतिरोध करने में कभी सफल न होंगे। वे हमारे शत्रु हीं सही, किन्तु उनके बलाबल से हमें अपने को पूर्णतया परिचित रखना है और इस दृष्टि से मैं आपका ध्यान इस बात की ओर खींचता हूँ कि वहाँ भी एक क्षण के लिए यह प्रश्न किसी के मन में नहीं उठा कि वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से वहाँ शिक्षा का माध्यम योरप की ऐसी किसी भाषा को रखना चाहिए, जिसमें विज्ञान का भण्डार है। वहाँ भी सब प्रकार की शिक्षा-दीक्षा चीनी भाषा के द्वारा दी जाती है। उन्हें एक क्षण के लिए भी यह अनुभव नहीं हुआ कि इस कारण उनके देश में किसी प्रकार के यंत्रविदों, वास्तुकारों, वैज्ञानिकों की कमी रही हो।

### बड़े-से-बड़े भारतीयों की आँखों पर अंग्रेजी के मोह की पट्टी

पर, हमारे देश में ऐसे शिक्षाशास्त्री हैं, ऐसे प्रशासक हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे राजनायक हैं, जो यह माने बैठे हैं कि भारत की मुक्ति, भारत का भविष्य, भारत की समृद्धि अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी पर ही आधारित है। मैं नहीं जानता कि कभी उन्होंने इस बारे में सोचा भी है या नहीं कि जब अंग्रेज इस देश में नहीं आये थे, जब अंग्रेजी इस देश में नहीं आयी थी, तब इस देश के लोगो ने अपनी जीवनधारा कैसे चलायी थी, प्रकृति से कैसे संघर्ष किया था, राजनैतिक तंत्र कैसे स्थापित किये थे और भूमि एवं अन्तरिक्ष के अनेक सत्यो का कैसे पता चलाया था। क्या वे समझते हैं कि अंग्रेज के पहले हमारे देश के लोग मूक थे, उनकी अपनी वाणी न थी, अपनी प्रतिभा न थी। मैं यह नहीं कहता कि वे लोग राष्ट्रप्रेमी नहीं हैं, किन्तु उनका राष्ट्र-प्रेम कैसा है, यह मैं समझ नहीं पाता। उन्हें यह बात भी नहीं दिखती कि अंग्रेजी के बिना हम सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति न कर पायेगे, यह विचार हमारे सारे इतिहास का उपहास है, हमारी जाति के प्रति सारे विश्व में यह भावना पैदा करना है कि अंग्रेजी के पूर्व हमारा देश पूर्णतः असभ्य था, बर्बर था और केवल अंग्रेजो ने ही गोरे आदमी का भार वहन करके हमें सभ्य बनाया। मैकाले को मरे हुए लगभग एक शताब्दी हो गयी, किन्तु यदि वे आज जीवित होते, तो उन्हें कितनी प्रसन्नता हुई होती, जब वे यह देखते कि जो बात उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान के सम्बन्ध में अपनी शिक्षा माध्यम सम्बन्धी टिप्पणी में १८३३ में लिखी थी, उसी बात की पुष्टि असाक्षात् रूप में उनके इन मानस-मुत्रों द्वारा जिनकी चमड़ी भारतीय है, किन्तु जिन का मन, जिनकी संस्कृति, जिनका दृष्टिकोण मैकाले की भाषा द्वारा, मैकाले के विचारों द्वारा बना है, पुष्ट हो रही है। मैकाले ने अपनी इस टिप्पणी में लिखा था कि यदि समग्र भारतीय साहित्य और विज्ञान की पुस्तकें समुद्र में डाल दी जायँ, तो मानव जाति की कोई हानि न होगी। चाहे अंग्रेजी से मोह रखनेवाले भारतीय विज्ञान और साहित्य के प्रति इन्हीं शब्दों का प्रयोग न करते हो; किन्तु, इससे कुछ अन्य उनका तात्पर्य न तो है और न हो सकता है। नहीं तो वे यह क्यों सोचते या क्यों कहते कि इस देश की भाषा द्वारा हम प्रगति के प्रशस्त पथ पर अग्रसर न हो सकेगे, हमारे देश की एकता न रह सकेगी, हम प्रजातन्त्र के प्रयोग को सफल न बना सकेगे, हम अपने आर्थिक तन्त्र को शीघ्रातिशीघ्र समृद्ध न कर सकेगे, हम जगत् से अपना सम्बन्ध खो बैठेंगे, हम विज्ञान की अमृतदायिनी सरिता से वंचित हो जायेंगे। स्पष्टतः उनके मन में यह मोह है, यह धारणा है कि इन सब बातों का केवल एक सूत्र, केवल एक द्वार, एक माध्यम अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी है। पर, थोड़ा विचार करके देखिए कि इसमें कितना तथ्य है। क्या यह

बात ठीक है कि केवल अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही किसी जाति के नर-नारी प्रगति कर सकते हैं ? यदि यह बात ठीक होती, तो संभवतः इंग्लैण्ड में ऐसा एक भी आदमी न होता, जो ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में पारंगत न होता। यदि अंग्रेजी ही सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति का दूसरा नाम है, तो इंग्लैण्ड का हर वासी, जिसे अंग्रेजी अपने माँ के दूध के साथ मिलती है, वह किसी प्रकार विज्ञान से अपरिचित न होता, किन्तु, क्या ऐसा है ? इंग्लैण्ड ने विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति पिछले डेढ़ सौ वर्षों में की है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस प्रगति का कारण अंग्रेजी भाषा किसी प्रकार न थी।

### अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की शब्द-सृजन-शक्ति

इंग्लैण्ड में विज्ञान का प्रवेश 'लातनी' और यूनानी भाषा के द्वारा हुआ। यदि मैं भूलता नहीं, तो इंग्लैण्ड में रोजर बेकन ने अपना कार्य अधिकतर इन्हीं भाषाओं के ज्ञान के सहारे किया और उसके पश्चात् भी अनेक वर्षों तक इंग्लैण्ड के विद्वान् इन भाषाओं का सहारा अपनी विधि, अपनी शिक्षा, अपने विज्ञान के लिये लेते रहे। सच तो यह है कि आज भी अंग्रेजी में यह शक्ति नहीं कि वह नये-नये वैज्ञानिक तथ्यों के लिए अपने निज से शब्द दे सके। आज भी इंग्लैण्ड के वैज्ञानिक इन तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए 'लातनी' या 'यूनानी' भाषा का सहारा लेते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, कि जो लोग दुहाई देते हैं कि अंग्रेजी के बिना भारत अन्धकार के गर्भ में चला जायगा, उनमें से अनेक वनस्पतिशास्त्र के ऐसे एक भी शब्द को न समझ सकेंगे, जो उन विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त किये जाते हैं। वे सभी शब्द अंग्रेजी में यूनानी या लातनी भाषा से लिये हैं और मैं तो यह समझता हूँ कि सम्भवतः उन्हें निन्यानबे प्रतिशत अंग्रेजी भी समझ में आती हो। मैं नहीं जानता कि इस ओर अंग्रेजी के हिमायतियों की दृष्टि गयी है या नहीं कि अंग्रेजी भाषा में शब्दनिर्माण की शक्ति लगभग नहीं के बराबर है और उस दृष्टि से सम्यक् भाषाओं में उतनी दरिद्र भाषा संभवतः ससार में कोई न होगी। हिन्दी के सम्बन्ध में बहुधा इन लोगो द्वारा यह कहा जाता है कि वह दरिद्र भाषा है। हिन्दी ही क्यों, ये लोग सब भारतीय भाषाओं को दरिद्र भाषा मानते हैं, किन्तु मेरा यह निजी अनुभव है कि हिन्दी में नये शब्द निर्माण करने की नैसर्गिक शक्ति है। उदाहरणार्थ सस्कृत का एक शब्द चूर्ण कई वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए काम में लाया जाता था, किन्तु हिन्दी ने उसी आधार पर कई शब्द बना लिये। चून, चूना, चूर्ण ये तीन शब्द पृथक्-पृथक् वस्तुओं को व्यक्त करते हैं और इनका निर्माण हिन्दी ने अपनी शक्ति के आधार पर किया है। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण आपको हिन्दी भाषा में मिलेंगे।

इसलिये यह कहना कि हिन्दी दरिद्र भाषा है, पूर्णतः निराधार है। हाँ, जिन लोगों को हिंदी के 'अ' 'आ' का ज्ञान नहीं, जिन्होंने अपने जीवन का एक क्षण हिन्दी-साहित्य के अध्ययन में नहीं लगाया और जिन के मन में हिन्दी के प्रति अकारण ही विद्वेष और उपेक्षा का भाव है, और रहा है, यदि वे यह कहने लगे कि हिन्दी दरिद्र भाषा है, तो आश्चर्य की बात ही क्या। किन्तु, यदि शुद्ध भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी और हिन्दी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो यह पता चलेगा कि केवल भाषा की दृष्टि से कौन-सी भाषा बलशाली है और कौन-सी असहाय और दुर्बल। जो भी हो, इस सम्बन्ध में क्या एक क्षण के लिये भी शंका हो सकती है कि अंग्रेजी विज्ञान के लिए एकमात्र देववाणी नहीं है। यदि भगवान् ने यही विधान कर दिया होता कि अंग्रेजी ही विज्ञान की भाषा होगी, तो फिर क्या रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन या अन्य देश-वासी विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी ही प्रगति कर पाते। यह केवल उपहासास्पद बात है कि अंग्रेजी का प्रगति से कोई विशेष सम्बन्ध है। प्रगति तो केवल इस पर आश्रित है कि मनुष्य की यह भावना और विश्वास हो कि जो भूतकाल से मिला है, उस पर ही पूर्णतः आश्रित न रहकर, उस से ही सर्वथा बँधे न रह कर, जीवन को अधिक समृद्ध और आनन्दमय बनाने के लिए नये-नये प्रयोग किये जायँ, नई-नई दिशाएँ खोजी जायँ। यह धारणा क्या हम इस देश के वासियों में अपनी भाषा द्वारा नहीं फैला सकते? क्या यह विचार उनके मन में नहीं पैठा सकते? क्या इस सम्बन्ध में एक क्षण के लिए भी किसी प्रकार की शका होनी चाहिए? अतः मेरा निवेदन है कि अंग्रेजी के पक्ष में इस प्रकार का तर्क देना बड़ा असंगत और अत्यन्त उपहासास्पद है।

### भारत की एकता के लिए क्या अंग्रेजी आवश्यक है ?

ऐसी ही एक दलील यह है कि भारत की एकता का आधार और स्रोत अंग्रेजी है। यह कहा जाता है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और वहाँ के वासियों के लिए परस्पर विचार-विनिमय करना केवल अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही संभव है; अंग्रेजी जाननेवाले इन विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों के प्रत्येक नगर और नगरी में मिलते हैं, इस कारण अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करनेवाले के लिए भारत में किसी स्थान में कठिनाई नहीं होती; यह बात भारत की किसी अन्य भाषा के सम्बन्ध में लागू नहीं है, इसलिए आज जो सुविधा अंग्रेजी के द्वारा हमें प्राप्त है और जिस सुविधा के कारण एक दृष्टि से भारत की एकता बनी हुई है, उसे छोड़ देने में कोई विशेष तुक नजर नहीं आती। इसके अतिरिक्त इनका यह दावा भी है कि अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के कारण ही भारत में राष्ट्रीय भावना जागृत



हुई और भारत में लोग यह सोचने लगे कि हम किसी जाति-विशेष या प्रदेश-विशेष के न होकर सब भारत माता की सन्तान हैं ; अतः अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीयता की जननी है, पोषिका है , इसलिए यदि अंग्रेजी हमारे देश से हट गयी, तो परस्पर विचार-विनिमय के अभाव के कारण और राष्ट्रीय एकता के सूत्र अभाव के कारण हमारा राष्ट्र छोटी-छोटी इकाइयों में बँट जायगा। कुछ अंग्रेजी के पक्षपाती यह तर्क भी उपस्थित करते हैं कि अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है, जिसके पढ़ने और अध्ययन में हमारे देश के विभिन्न प्रदेश वालों को एक समान प्रयास करना पड़ता है, एक-सी ही कठिनाइयों से सघर्ष करना पड़ता है ; किन्तु, यदि भारत की कोई एक भाषा भारत की राजभाषा बन गई, तो अन्य प्रदेश वालों को उस भाषा को सीखने में जितनी कठिनाई होगी ; जितना प्रयास करना होगा, उतनी कठिनाई उस भाषा के बोलनेवालों को न उठानी पड़ेगी और इस प्रकार उस भाषा के बोलनेवालों को अन्य भाषा-भाषियों की अपेक्षा राजकीय जीवन में अधिक सुविधाएँ प्राप्त हो जायँगी और इस प्रकार अन्य प्रदेशवासियों के प्रति यह घोर अन्याय होगा। कहते हैं कि जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। अंग्रेजों का जादू इस सम्बन्ध में पूरा उतरता है। वे चले गये, किन्तु, जो मन्त्र वे फूँक गये थे, जो पट्टी वे पढ़ा गये थे, वह आज अपना पूरा प्रभाव दिखा रही है। इस बात को आप लोग न भूले होंगे कि अंग्रेज भारत में अपने राज्य के पक्ष में मुख्यतः यही तर्क देते थे कि भारत की एकता उसी राज्य की नींव पर आधारित है। उनके आने के पहले भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटा हुआ था, और उसकी जनता राष्ट्रीयता से सर्वथा अपरिचित थी। भारत में उसकी यह सर्वोक्ति थी कि जब तक भारत में हमारा राज्य है, तभी तक भारत में एकता है, यदि हम यहाँ से एक क्षण के लिए भी अपना प्रभुत्व हटा लेंगे, तो भारत के पुनः टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे और यहाँ परस्पर ऐसी मारकाट मच जायगी, ऐसा अनाचार और अत्याचार फैल जायगा कि किसी भी भारतीय कुमारी का सतीत्व बचा न रहेगा। उनका यह भी तर्क था कि इस देश के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, विभिन्न भाषा-भाषी और प्रादेशिक जातियों के अधिकारों की रक्षा वे निष्पक्ष भाव से करते हैं और सब को सम न्याय प्रदान करते हैं ; किन्तु, यदि वे चले गये, तो भारत का सम्प्रदाय-विशेष या जाति-विशेष या प्रदेश-विशेष दूसरे सम्प्रदायों, दूसरी जातियों और दूसरे प्रदेशों पर छा जायगा और उनको पैरो तले रौंद देगा। आप देखेंगे कि अंग्रेजों के इन्हीं तर्कों की पुनरावृत्ति आज हमारे अंग्रेजी के हिमायती इस सम्बन्ध में कर रहे हैं। अपने गौरागुरुओं की शिक्षा का कितनी कुशलता से वे पालन कर रहे हैं। किन्तु, यह सब तर्क शोथे हैं, निराधार हैं। थोड़े से विचार से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस सब स्वार्थ के पीछे उनका वैसा ही स्वार्थ है, जैसा कि अंग्रेजों का स्वार्थ उनके अपने राज्य

के समर्थन के पीछे था। अंग्रेजी के द्वारा इन लोगों के लिए यह सभव हो रहा है कि वे भारत की जनता के कंधे पर बैठकर भारत की जनता से उसी प्रकार परिश्रम करा कर जैसे कि अंग्रेज कराते थे, स्वयं सुख भोगें, गुलछरें उड़ाये। सिद्दबाद नाविक की कहानी में जिस प्रकार हम यह पढ़ते थे कि सिद्दबाद की गर्दन पर सवार होकर उसके गले को अपने पाँवों में कसकर और दबाकर उस व्यक्ति ने सिद्दबाद को दौड़ाया उससे परिश्रम कराया और स्वयं आनन्द भोगा, उसी प्रकार आज ये आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज से निकले श्यामवर्ण वाले; किन्तु, आगल चेतना और आत्मा वाले हमारे देश की जनता के कंधे पर कसकर आसन जमाये बैठे हैं और हर प्रकार से उसका शोषण कर रहे हैं तथा भोली भाली विभिन्न प्रदेशों की जनता को विमुख करने को इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं। नहीं तो क्या वे यह नहीं जानते कि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और इस एक प्रतिशत की एकता भारत की एकता नहीं कही जा सकती। क्या इस बात से इनमें से कोई भी इन्कार कर सकता है कि आज भी लाखों की संख्या में सुदूर दक्षिण में ग्रामवासी, जिन्हें अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता, उत्तर भारत के काशी, मथुरा, हरिद्वार और बदरीनाथ जैसे महान् तीर्थस्थानों में प्रतिवर्ष यात्रा के लिए आते हैं। क्या यह बात सत्य नहीं है कि उत्तर भारत के अनेक ग्रामवासी सुदूर रामेश्वरम् की यात्रा करने के लिए सहस्रों की संख्या में जाते हैं? क्या इन लोगों का काम अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता? क्या वे अपने सब धार्मिक संस्कार और जीवन के अन्य व्यापार अपनी यात्रा में हिन्दी के माध्यम द्वारा नहीं करते? क्या यह सत्य नहीं है कि भारत के प्रत्येक धार्मिक तीर्थ-स्थानों में हिन्दी जाननेवाले पढ़े नहीं मिलते या नहीं होते? तब फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत के विभिन्न प्रदेशवासियों के विचार-विनिमय का माध्यम केवल अंग्रेजी है। आसाम के चाय बागानों में, कलकत्ते के बड़े बाजार में, बम्बई की चौपाटी में और सुदूर दक्षिण में सर्वत्र ही हमें हिन्दी भाषा-भाषी श्रमिक कार्य करते मिलते हैं। हिन्दी भाषा-भाषी व्यापार करते मिलते हैं। हिन्दी भाषा-भाषी पंडे धार्मिक संस्कार करते मिलते हैं। सचमुच यह महत् आश्चर्य की बात होती, यदि ऐसा न होता। अंग्रेजी तो अभी कुल एक सौ वर्ष से ही इस देश में आयी थी। उससे पहले भी हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में विचार और वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था; अतः स्वाभाविक ही मध्यदेश की यह भाषा हिन्दी उस विचार-विनिमय की माध्यम बन गयी थी और बनी रही और बनी है और बनी रहेगी।

**अतीत और वर्तमान वर्ग-संघर्ष और विग्रह का कारण कौन**

अंग्रेजी वर्ग अधिक-से-अधिक यही कह सकता है कि उसकी अपनी एकता अंग्रेजी

के आधार पर है। यद्यपि इस सम्बन्ध में भी पूरी पूरी शका की जा सकती है। यदि वर्तमान भारतीय राजनैतिक कलह का वास्तविक कारण ढूँढा जाय, तो हमें यह पता चलेगा कि इस अंग्रेजी से मोह रखनेवाले ही व्यक्तियों में परस्पर सर्वाधिक द्वेष और स्पर्धा वर्तमान है। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत की राजनीति में जो विषवृक्षा बोया गया है, वह उन लोगों ने बोया या उन लोगों के माध्यम द्वारा बोया गया, जो इस बात के लिए लालायित थे कि अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा इस देश की जनता से दुहा जानेवाली सपत्ति में उनका भी कुछ साझा हो जाय। अंग्रेजी साम्राज्य के तन्त्र में छोटी-मोटी नौकरी पाने के लिए कौन लालायित था, वही तो जिन्होंने यह अंग्रेजी पढ़ ली थी। नौकरियाँ थोड़ी थी और अंग्रेजी पढ़े-लिखे अधिक। अतः इन अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों ने परस्पर एक दूसरे की जड़ काटने के लिए हर प्रकार के साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और भाषा-जाति विभेद पैदा किये और उन्हें तीव्रता से प्रसारित किया। क्या यह सत्य नहीं है कि पाकिस्तान के आंदोलन के जन्मदाता इसी अंग्रेजी वर्ग के कुछ लोग थे? उन्होंने भोलीभाली जनता को अपने स्वार्थ के लिए गुमराह किया और देश को टुकड़े-टुकड़े कर डाला। क्या यह सत्य नहीं है कि इसी अंग्रेजी वर्ग के कुछ लोगों ने अंग्रेजों की शह पर इस देश में उत्तर और दक्षिण का प्रश्न उठाया और उत्तरवासियों के विरुद्ध दक्षिण के कुछ प्रदेशों में एक प्रकार का जेहाद प्रारम्भ कर दिया। यदि ऐसा न होता, तो आश्चर्य की बात होती। जिन लोगों ने सर्वप्रथम अंग्रेजी पढ़नी आरम्भ की थी, उन लोगों ने उसका अध्ययन ज्ञानोपार्जन, विज्ञान और दर्शन के ज्ञान के लिए नहीं किया था; वरन् हमारे देश के पूज्य गुरुजनों के आदेश की अवहेलना कर अधिकांशतः इस प्रयोजन से आरम्भ किया था कि वे भी अंग्रेजी राज्य की लूट में कुछ हिस्सा पायें। हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हों, जिन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन अंग्रेजों की सफलता का रहस्य जानने के लिए आरम्भ किया हो; किन्तु, ऐसे लोगों की संख्या नगण्य थी। और, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अधिकांशतः ऐसे लोग स्वार्थरत थे, अपने ही निज मुख और समृद्धि की भावना से प्रेरित थे। भला वे लोग भारत की एकता की बात सोचें, यह तो महान् आश्चर्य की बात होगी।

### हम इन्हें दुभाषिया कहें या बहुरूपिया

यह बात आज भी है कि जो लोग अंग्रेजी की हिमायत करते हैं, उनमें से निन्यानवे प्रतिशत भारत की एकता की बात मन में नहीं रखते, वे केवल इस एकता की दुहाई अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये देते हैं। नहीं तो क्या यह प्रश्न उनके मन में नहीं उठता कि आज अंग्रेजी के कारण भारत की निन्यानवे प्रतिशत जनता और राज्य के बीच

खाई पैदा हो गई है और बढ़ती जा रही है। क्या उनको यह सोचने का समय नहीं मिलता कि अंग्रेजी के कारण आज भारत के नित्यानवे प्रतिशत नागरिक राज्य-दर-बार में प्रवेश नहीं कर पाते। उनकी सतान को कहीं कोई राज्यपद नहीं मिलता। मूक, निरीह, असहाय रहे आते हैं। उनके हृदय में यह भावना जागृत नहीं हो पाती कि यह राजतन्त्र, यह देश की संपत्ति, इस देश की विशाल भूमि, इसके नदी, पहाड़ सब उनके हैं, आज भी वे अकिंचन बने हुए हैं और यही समझते हैं कि उनके सिर पर बैठी सरकार उनकी भाग्य-विधाता है, वे स्वयं उनके संचालक नहीं। क्या भारत की एकता के लिए यह आवश्यक नहीं कि भारत के जन-जन के हृदय में यह विचार-धारा तरंगित होने लगे कि हम सबका भाग्य एक है, हम सब की संपत्ति एक है, हम सबका इतिहास एक है। मैं विनम्रता से पूछता हूँ कि क्या यह बात अंग्रेजी भाषा के द्वारा संभव हो सकती है? क्या यह स्पष्ट नहीं कि यदि अंग्रेजी के माध्यम द्वारा यह बात संभव होती, तो फिर हमारे ग्रामों में, हमारी साधारण जनता से ये लोग अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा वार्तालाप करते, अपने व्याख्यान अंग्रेजी में देते। मैं इस बात की चुनौती देता हूँ कि जो लोग अंग्रेजी के द्वारा भारत की एकता बनी रहने की बात कहते हैं, वे जरा साहस कर हमारे गाँवों में जाकर हमारी जनता से केवल अंग्रेजी में बोलें और अपने इस तर्क को चरितार्थ करें। पर, मैं जानता हूँ कि उनमें से एक में भी यह सामर्थ्य नहीं। इन्हें हम दुभाषिया कहे या बहुरूपिया? कैसा सहान् आश्चर्य है कि देश की एकता को छिन्न-भिन्न करनेवाले देश की एकता की दुहाई दें। देश की राष्ट्रीयता को तिलांजलि देने वाले, इस देश की वेशभूषा, खान-पान, आचार-विचार, रीति-रिवाज, इतिहास और संस्कृति का उपहास और तिरस्कार करने वाले व्यक्ति और पाश्चात्य, योरप एक विशिष्टतः इंग्लैंड को अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घर और देश माननेवाले व्यक्ति राष्ट्रीयता का यह बाना दिखाने के लिए सहन लें। इनकी राष्ट्रीयता का अर्थ इस देश को छोटा इंग्लैंड बनाना है और इसी-लिए यह स्वाभाविक है कि अपने स्वप्न के उस निर्माण के लिए ये लोग अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य समझे। किन्तु, यदि विचारपूर्वक हम सोचें, तो स्पष्ट पता चल जायगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति किसी भी जाति में उस समय होती है, जब वह आर्थिक विकास की उस स्थिति में पहुँच जाती है, जब कि केवल ग्राम, केवल नगर अथवा केवल जनपद के क्षेत्र में हों। उसका आर्थिक व्यापार सीमित नहीं रहता और नहीं रह सकता। उस समय इन छोटी इकाइयों की सीमा को लॉघकर अनेक नगरवासी, अनेक ग्रामवासी, अनेक जनपद-वासियों के हृदय परस्पर बिध जाते हैं और उन्हें यह दिखने लगता है कि हमारे हित दूसरे देशवासियों के हित से पृथक् हैं और परस्पर एक हैं। कभी-कभी राष्ट्रीय भावना की जागृति उस समय होती है

जब एक जाति का किसी विदेशी जाति से संघर्ष हो जाता है। हमारे देश में इस प्रकार की आर्थिक स्थिति यात्रिक और शक्ति-चालित उद्योग के विकास के कारण पैदा हुई और फैली है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, जिसकी पुष्टि आपको इटली, फ्रांस, जर्मनी-जैसे देशों में राष्ट्रीय भावना की जागृति के इतिहास से मिल जायगी। यह संसार विदित है कि आयरलैण्ड में राष्ट्रीय भावना का उद्रेक उस भाषा के पुनर्निर्माण से हुआ, जिसका अंग्रेजों ने बीज तक लगभग नष्ट कर दिया था। आयरलैण्ड के राष्ट्रीय नेता गैलिक भाषा के पुनर्निर्माता थे, पुनर्प्रतिष्ठाता थे। क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे देश में भी कांग्रेस का आंदोलन तब तक निष्प्राण था, जब तक वह केवल अंग्रेजी जाननेवाले वर्ग तक सीमित था और उसमें जीवन-ज्योति उसी समय जगी, जब पूज्य बापू ने हिन्दी को और भारतीय भाषाओं को उस आंदोलन का आधार बनाया और ग्राम-ग्राम में, नगर-नगर में भारतीय भाषाओं के माध्यम द्वारा स्वाधीनता की अलख जगा दी। भारतीय राष्ट्रीयता का इतिहास भारतीय जनसाधारण का इतिहास है। आज यदि अंग्रेजी जाननेवाला वर्ग इस महान् सृष्टि को हथिया लेना चाहता है, इसका गौरव अपना बना लेना चाहता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिसकी रंग-रंग में स्वार्थ बसा है, उससे और क्या आशा की जा सकती है? पर उसके लिए यह संभव नहीं कि वे इस बनी-बनाई राष्ट्रीयता को कायम रख सकें। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेजी का यदि आधिपत्य बना रहा, यदि उसने अपना शोषण कायम रखा, तो भारतीय जन-जीवन शोषक और शोषितों के परस्पर संघर्ष से खड-खड हो जायगा। कैसे अचम्भे की बात है कि ये लोग भी न्याय की बात करते हैं, पर ऐसा लगता है कि न्याय की इनकी अपनी विशेष परिभाषा है। संभवतः ये लोग इस बात को न्याय नहीं समझते कि भारत के प्रत्येक नर-नारी के लिए यह सुविधा प्राप्त हो कि वह इस देश के राजतन्त्र में सुगमता से प्रवेश कर सके, राज-काज के संचालन में भाग ले सके, राजपदों पर आसीन हो सके। यदि ये लोग इस बात को न्याय मानते, तो क्या यह न सोचते कि यह बात तब तक संभव न होगी, जब तक कि भारत का राजतन्त्र अंग्रेजी में लिपटा रहेगा। जैसा मैं अभी कह चुका हूँ कि भारत की नित्यानवे प्रतिशत जनता के लिये यह संभव नहीं है कि वह इस राजतन्त्र में किसी प्रकार से भाग ले सके और वह इसलिए संभव नहीं है कि वह अंग्रेजी नहीं जानती और इस राजतन्त्र के द्वार पर बड़े मोटे अक्षरों में लिखा है कि अंग्रेजी न जानने वालों के लिए यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। संभवतः इन लोगों की न्याय की परिभाषा वही है, जो साधारण दफ्तरी लोगों की होती है। दफ्तरों में काम करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि उसकी तरक्की हुई, तो न्याय हुआ और तरक्की न हुई, तो अन्याय; अर्थात् वहाँ निजी स्वार्थ का दूसरा नाम न्याय है। जब ये लोग न्याय की

बात करते हैं, तो वहाँ भी यही गध आती है—नौकरी में हमारी प्रगति रुक जायगी, हम नौकरी में उतने आगे नहीं बढ़ पायेंगे, जितने अन्य ; अर्थात् इनके निजी स्वार्थ का ही नाम न्याय है ; पर ये लोग इस बात को प्रदेश-प्रदेश के बीच न्याय का बाना पहना देते हैं, मानों कि इनके अपने प्रदेश में ये स्वयं अपनी साधारण जनता के प्रति न्याय कर रहे हों, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए लालायित हों। स्वयं अपने स्वार्थ पर डटे रह कर अपनी ही वैयक्तिक प्रगति को ध्यान में रखकर और अपनी जनता के प्रति पूर्ण अन्याय करते रह कर ये लोग न्याय की दुहाई दे, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है ? अंग्रेजी ही परस्पर इन प्रदेशों में नौकरी के सम्बन्ध में समता रख सकती है, इससे बड़ी अनर्गल बात और क्या हो सकती है ? क्या इन लोगों को यह नहीं दिखाई पड़ता कि इसी तर्क के आधार पर उन्हें एक दिन अंग्रेजों को भी वापस बुलाना पड़ेगा। यदि भारत में भारत की किसी भी भाषा के प्रयोग से अन्य प्रदेशों के प्रति अन्याय होगा, तो फिर क्या भारत के किसी प्रदेश के व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व जाने से इन लोगों को अन्य प्रदेशों के प्रति अन्याय न लगेगा और तब क्या ये लोग इस बात की दुहाई न देने लगे कि भारत का नेता भारतीय न होना चाहिए, वह तो इनके आगल गुरुओं में से एक होना चाहिए। मैं आप सब का ध्यान इस भयावह बात की ओर विशेष रूप से खींचना चाहता हूँ कि जो देशभाषा को विदेशी मान सकते हैं, वे देशभाषा को भी विदेशी मान सकते हैं और अपने भाई का गला काटने के लिए विदेशियों को भी आमन्त्रित कर सकते हैं।

### प्रजातन्त्र की सफलता क्या अंग्रेजी पर निर्भर है ?

न्याय शब्द का जिस प्रकार उल्टे अर्थ में ये लोग प्रयोग करते हैं, सम्भवतः उसी प्रकार इनके प्रजातन्त्र शब्द का अर्थ है। साधारणतः प्रजातन्त्र से यही बोध होता है कि प्रजा अपना शासन स्वयं करे। राज्यतन्त्र में उसका प्रमुख भाग हो। अपनी राजनैतिक समस्याओं पर वह स्वयं सोच-विचार कर अपनी नीति निर्धारित करे। स्पष्ट है, कि ऐसा राजनैतिक तन्त्र तभी स्थापित हो सकता है जब उसका सारा काम-काज जनता की अपनी भाषा में हो; अतः जब भी कोई देश साम्राज्य-वादिता के चंगुल से छूटकर स्वतन्त्र हुआ है, उसने तुरन्त अपना सारा काम-काज अपनी जनता की भाषा में करना आरम्भ कर दिया है। संसार के इतिहास में अन्यत्र ऐसा कोई उदाहरण न मिलेगा, जहाँ स्वतन्त्र देश अपनी भाषा में अपना राज-काज न चलाता हो। केवल हमारा ही अनोखा देश है कि जो स्वतन्त्र कहलाता है ; किन्तु जिसका राज-काज देश की भाषा में न होकर उस भाषा में होता है, जो हमारे पिछले शासकों की भाषा थी और जो हम पर उन्होंने अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रयोग

कर लादी थी। इससे भी अनुठी बात यह है कि यहाँ का राजतन्त्र प्रजातन्त्र कहलाता है, जब कि यहाँ निन्यानवे प्रतिशत जनता उस भाषा से सर्वथा अपरिचित है, जिस में यहाँ का सारा राज-काज शासक-वर्ग करता है। इस अनोखेपन पर गर्व करें या आँसू बहायें ? पर, कैसा आश्चर्य है कि यहाँ का अंग्रेजी जानने वाला वर्ग कहता है कि यदि अंग्रेजी भाषा न रखी गई, तो इस देश में प्रजातन्त्र का प्रयोग सफल न हो सकेगा। इन लोगों के अनुसार प्रजातन्त्र हमने इंग्लिस्तान से आयात किया है। इन लोगो का कहना है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली और संसदीय राजतन्त्र जगत् को इनके परम गुरु इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड की इस अपूर्व देन के हृदयतल में अंग्रेजी बसी हुई है। तत्सम्बन्धी सारा साहित्य अंग्रेजी भाषा में है। उसकी पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी भाषा में है। उसका विधि-विधान सब अंग्रेजी में है ; अतः यदि हमें इस प्रजातांत्रिक और संसदीय प्रणाली को सफल बनाना है, इसकी जड़ इस देश में मजबूत करनी है, तो हमें अंग्रेजी भी अपने यहाँ रखनी है और उसके माध्यम द्वारा अपना कामकाज चलाना है। मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं कि ये लोग समझे कि यह जगत् में जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ सुन्दर है, जो कुछ उपास्य है, वह सब इनके परम गुरु इंग्लैंड का है और इंग्लैंड में हैं ; किन्तु इस बात को समझने के लिए अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से इंग्लैंड का कुछ विशिष्ट सबध नहीं है। फ्रांस की राज्यक्रांति तक इंग्लैंड में केवल सामन्तों का राज्य था और वहाँ जनसाधारण को बालिग मताधिकार तो पिछले महायुद्ध के पश्चात् मिला। इसके विपरीत युग-युगान्तर से हमारे देश में अपने सामाजिक और सामूहिक मामलों की व्यवस्था ग्राम-पञ्चायतों के द्वारा करने की परिपाटी चली आ रही थी और हमारे देश के लोग उस परिपाटी के अभ्यस्त थे। मैं नहीं जानता कि अंग्रेजी-वर्ग के लोग उस पञ्चायत-प्रणाली को प्रजातांत्रिक प्रणाली मानने के लिए तैयार हैं या नहीं, समाज-शास्त्र के निष्पक्ष विद्यार्थी तो उस प्रणाली को प्रजातांत्रिक प्रणाली का आदि रूप सर्वदा स्वीकार करते रहे हैं। तथ्य तो यह है कि किसी देश की भी शासनप्रणाली उस देश के आदर्शों और भावनाओं के अनुसार होती है ; अतः हमारे देश में भी वर्तमान प्रणाली की सफलता, विफलता हमारे इतिहास, हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, हमारे आदर्शों और भावनाओं पर निर्भर करेगी, न कि अंग्रेजी पर। चाहे हम कैसी ही दृढ़ शृंखला से अपने को इंग्लैंड की चौखट से कसकर कितना ही क्यों न बाँध ले, चाहे हम “मे” की संसदीय प्रणाली की प्रसिद्ध पुस्तक के कितने ही परायण क्यों न करें, हमारे देश का राज-तन्त्र उस रूप में कार्य नहीं कर सकता, न ही कर सकेगा, जिस रूप में कि वह इंग्लैंड में कार्य करता रहा है ; अतः

इस बात में लेशमात्र तथ्य नहीं कि अंग्रेजी बनाये रखने से हम अपने इस तन्त्र को ठीक उसी ढर्रे पर चला सकेंगे, जैसे कि वह इंग्लैंड में चलता है। यह हमारा अपना है। इसका निर्माण हमारी सर्वप्रभुता-सम्पन्न जनता ने अपनी सविधान-सभा के द्वारा किया है। यह हमारे देश की समस्याओं को ध्यान में रख कर बना है और इसमें अनेक ऐसी बातें हैं, जो न तो इंग्लैंड में और न इंग्लैंड के किसी अधिराज्य पायी जाती हैं ; अतः इस बात का प्रयास करना कि यह पूर्णतया भारतीय राजतन्त्र में इंग्लैंड के राजतन्त्र के ही ढर्रे पर चले, इस तन्त्र का अपमान है और हमारे देश का और जनता का अपमान है। कम-से-कम इस आधार पर अंग्रेजी को रखने का समर्थन तो घाव पर नमक छिड़कने के समान है।

### देश के द्रुत आर्थिक विकास के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता एक भ्रम

सब से अनोखी बात जो अंग्रेजी के पक्षपाती उसके समर्थन में देते हैं, वह यह है कि हमारे द्रुत आर्थिक विकास के लिए अंग्रेजी की परम आवश्यकता है। कहा जाता है कि द्रुत आर्थिक विकास के लिए हमें अनेक इंजीनियर, शिल्पी और वैज्ञानिक चाहिए। हमारे पास इस समय सारा साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध है और भारतीय भाषाओं में वह साहित्य उपलब्ध नहीं है ; अतः हम पर्याप्त संख्या में इंजीनियर, वैज्ञानिक और शिल्पी इस अंग्रेजी साहित्य के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर सकते हैं। यदि हम थोड़ी राष्ट्रीय भावना से बँधे रहकर यह प्रयास करें कि हमारी देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा हम अपने विद्यार्थियों को इन विषयों की शिक्षा दें, तो हमें अनेक वर्ष व्यर्थ में यह साहित्य अपनी भाषाओं में तैयार करने के लिए खो देने पड़ेंगे और इस प्रकार हमारा आर्थिक विकास न हो पायेगा। जिस ढंग से यह बात कही जाती है, उससे ऐसा लगता है कि कम-से-कम यह तर्क तो अकाट्य है। किन्तु, है यह भी धोखेभरी बात। अब तक हम सब यही समझते रहे हैं और मानते रहे हैं कि शिक्षा का मूलमंत्र परिचित के आधार पर अपरिचित का बोध कराना है। इसी कारण ससार-भर के शिक्षाशास्त्री यह मानते हैं कि मातृभाषा के माध्यम द्वारा समय और शक्ति की पूर्ण मितव्ययिता के साथ और अत्यन्त तीव्र गति से बालक को शिक्षा दी जा सकती है ; अतः यह स्पष्ट है कि भारत में तीव्रातितीव्र गति से देश-वासियों को शिक्षित करने का माध्यम अंग्रेजी हरगिज नहीं हो सकती। केवल अंग्रेजी सीखने में ही हमारे विद्यार्थी को कम-से-कम दस वर्ष व्यतीत कर देने पड़ते हैं। इसके विपरीत उसे अच्छा कामचलाऊ ज्ञान एक-दो वर्ष में ही हो जाता है। स्पष्ट है, यदि हम देश में हर प्रकार की शिक्षा अपनी मातृभाषा द्वारा अपने युवकों को दें, तो वह लगभग आधे समय में उतना ज्ञानोपार्जन कर लेंगे, जितना आज वे



अंग्रेजी के माध्यम द्वारा करते हैं। हर विद्यार्थी के कम-से-कम पाँच छै वर्ष बच जायेंगे और हम यदि इन वर्षों को विद्यार्थियों की सख्या से गुणा कर दे, तो हमको पता चलेगा कि हम अपने देशवासियों के लाखों वर्ष इस प्रकार बचा लेंगे और जो समय इस प्रकार बचेगा, उसे देश के विभिन्न प्रकार के अधिकाधिक आर्थिक विकास में लगा सकेंगे। यह दलील कि हमारी भाषाओं में साहित्य नहीं है, कुछ महत्त्व नहीं रखती। यदि हमने उस धन और समय का, जो हम आज अंग्रेजी माध्यम के कारण व्यर्थ गवाँ रहे हैं, शतांश भी आवश्यक साहित्य के निर्माण के लिए लगाया होता, तो अब तक हमारे पास अपनी भाषाओं में बरसों पूर्व सब आवश्यक वैज्ञानिक और शिल्पिक साहित्य हो जाता। पर, हमारे अंग्रेजी वर्ग के लोगो ने ही हर प्रकार की बाधा खड़ी करके यह नहीं होने दिया। इस प्रकार के साहित्य का निर्माण तब होता है, जब उसके लिए माँग हो; किन्तु, जब अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही शिक्षा दी जाती रहे, तो अपनी भाषाओं में ऐसे साहित्य का निर्माण होने का प्रश्न पैदा हो ही कैसे सकता है। न तो कोई लेखक और न कोई प्रकाशक इस बात के लिए तैयार होगा कि वह अपना समय और धन उस साहित्य के तैयार करने और प्रकाशित करने में लगाये, जिसके माँग के सब द्वार यत्नपूर्वक पूर्णतः बन्द कर दिये गये हों।

### वैज्ञानिक उधार-खाता

हमारी भाषाओं में इस प्रकार का साहित्य पहले हो और तब वे शिक्षा का माध्यम बनाई जायें, यह बात किसी से यह कहने के समान है कि तैरना पहले सीख लो और पानी में पीछे धुसो। इस प्रश्न के एक पहलू और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू पर अब तक लोगो की दृष्टि नहीं गई है। विज्ञान का इतिहास हमें यह बताता है कि नये-नये वैज्ञानिक-तथ्यों की खोज और नये-नये यंत्रों का निर्माण विश्वविद्यालय से उपाधि-प्राप्त विद्यार्थियों ने इतना नहीं किया है, जितना कि उन लोगों ने किया है। जिन्हें कि जीवन में स्वयं की समस्याएँ स्वयं अपनी प्रतिभा से सुलझाना पड़ती हैं; अर्थात् श्रमिकों ने और शिल्पियों ने। हम यह समझे बैठे हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में जो पाठ पढाये जाते हैं, उन्हीं के सहारे इन विश्वविद्यालयों के स्नातक हमारी सब यांत्रिक और आर्थिक समस्याओं का हल कर देंगे। एक प्रकार से देखा जाय, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हम इसी भरोसे बैठे हैं कि पाश्चात्य जगत से मिले वैज्ञानिक उधार-खाते से हमारा उसी प्रकार काम चल जायगा, जिस प्रकार कि आर्थिक क्षेत्र में विदेशी धन के उधार खाते से हम चला रहे हैं; किन्तु भारत के भौगोलिक वातावरण से और भारत में प्राकृतिक परिस्थितियों से सघर्ष करने के लिये केवल पाश्चात्य जगत् की उधार से हमारा काम नहीं चलने का और यदि किसी सीमा तक चल भी जाय,

तो हम अपने देश को विज्ञान के उस स्तर तक नहीं ला सकेंगे, जिस स्तर तक कि अन्य देश अपनी नई-नई खोजों, नये-नये यंत्र-निर्माणों के द्वारा पहुँच गये हैं और आगे भी पहुँचेंगे। यदि हम वैज्ञानिक जगत् में दूसरों के समकक्ष बनना चाहते हैं, तो हमें स्वयं नई-नई वैज्ञानिक खोजें और नये-नये प्रकार के यंत्र-निर्माण करने होंगे और यह सब हम पाश्चात्य जगत् की जूठन से नहीं कर पायेंगे। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि हमारा प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक कृषक, प्रत्येक नर-नारी इस बात के लिए सचेष्ट हो जाय कि जो समस्याएँ उसके सामने आती हैं, उनके समाधान के लिए अहर्निश नई-नई युक्तियाँ सोचे, नये-नये यंत्र निकाले और इस प्रकार नये-नये वैज्ञानिक तथ्यों का पता चलाये। आवश्यकता नवनिर्माण अथवा उत्पत्ति की जननी है (Necessity is the mother of invention)। जब जीवन की चुनौती हम स्वीकार करते हैं, तभी हम नये सत्य खोज निकालते हैं, नये यंत्र, नई युक्तियाँ बना पाते हैं। स्पष्ट है कि हम अपने देश के निन्यानवे प्रतिशतवासियों को यह अवसर इस कारण प्रदान नहीं कर पा रहे हैं कि हम अंग्रेजी से चिपटे हुए हैं और अपने इस देश में यह भ्रम फैला रखा है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती, वह किसी प्रकार की वैज्ञानिक खोज या वैज्ञानिक निर्माण नहीं कर सकता। विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा पढ़ने के लिए अपने युवकों को मजबूर करके हमने उनकी प्रतिभा को तो कुण्ठित कर ही दिया है, उनको रट्टू मडूक बना ही दिया है, हमने साथ ही अपने देश के साधारण जन में भी असहायता की विचारशून्यता की प्रवृत्ति पैदा कर दी है और ज्ञान के स्रोत हर प्रकार से अवरुद्ध कर दिये हैं। हमारा आर्थिक तंत्र आज लँगड़ी चाल से चल रहा है, उसमें जनता के हृदय का स्पन्दन नहीं है, उसके पीछे जन-बल नहीं है, इस देश का महान् अपरिमित जन-बल नहीं है। सच तो यह है कि हमारा अंग्रेजी वर्ग अपने स्वार्थवश यह भूल बैठा है कि इस देश की कितनी हानि इस अंग्रेजी के कारण हो रही है। हम अनेक वर्षों तक अपनी राष्ट्रीय महासभा में यह बात अपने संकल्पों, अपने प्रस्तावों द्वारा कहते रहे हैं कि अंग्रेजी के कारण हमारे देश का महान् सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक महापतन हुआ है। जब हम यह बात कहते थे, तो हमारा आशय इतना ही न था कि हमारा पतन इस कारण हुआ कि इस देश में अंग्रेज राजतंत्र के प्रमुख पदों पर आसीन थे और वे उस तन्त्र को अपने स्वार्थ के लिए चलाते थे; वरन् हमारे मन में यह बात भी थी कि इस पतन का कारण वह भाषा भी है, जिसके द्वारा वह अपना शासन इस देश में चला रहे थे। अंग्रेजी भाषा के कारण हमारी अपने देश की भाषाएँ पंगु हो गईं। उनको वह दाना-पानी न मिला, जो उनके स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक था। अंग्रेजी के कारण हमारे जन-साधारण असहाय हो गये, क्योंकि राज-दरबार में जाने पर वे शासकों से अपनी भाषा में न तो बात

कर सकते थे और न शासकों की भाषा समझ सकते थे ; अतः उन्हें अपने जीवन की गाढ़ी कमाई शासकों के दलालों को इसलिये देनी पड़ी कि वे दलाल इनकी बात शासकों तक पहुँचा सके और शासकों के आदेश उन्हें समझा सकें। अंग्रेजी के कारण हमारे देश के शिल्पी, हमारे देश के महान् वास्तुकार दर-दर के भिखारी हो गये। जिन लोगों ने कोणार्क-जैसे मन्दिर का निर्माण किया था, उनके वैसे ही कुशल वंशज केवल इसलिए रक हो गये कि वे अंग्रेजी न जानते थे और अंग्रेजी साम्राज्य के राज-दरबार में केवल वे ही कुशल वास्तुकार माने जाते थे, जिन्होंने किसी अंग्रेजी वास्तु-विज्ञान के विद्यालय में शिक्षा पाई थी। अंग्रेजी ने हमें प्रगति-पथ पर तो क्या चलाया, हम से वह विज्ञान, वह शिल्प, वह कला भी बहुत कुछ छीन ली, जो हम अंग्रेजी राज-काल के पूर्व अर्जित कर पाये थे। आज भी हमारी अंग्रेजी से कितनी हानि हो रही है, इस पर जरा विचार कीजिए। अंग्रेजी के मोह के कारण हमारे सहस्रों विद्यार्थी इंग्लैंड, अमरीका के विद्यालयों में जाकर पढ़ते हैं और इस प्रकार देश का करोड़ों रुपया विदेशों में खर्च हो रहा है। हमारे यहाँ आज अंग्रेजी की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालयों में भी अनिवार्य कर दी गई है। परिणामतः हमें अपनी प्राथमिक कक्षाओं के लिए अंग्रेजी की पुस्तिकाएँ विदेशों से आयात करने के लिए संभवतः करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है ? वह कौन-सी बात है, जिसके लिए प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ानी आवश्यक समझी जा रही है और उसकी पढ़ाई पर घनराशि व्यय की जा रही है ? आखिर प्राथमिक कक्षाओं में इस अंग्रेजी पढ़ाई से हमारे भ्रामीण बालक को क्या लाभ होता है ? इसके अतिरिक्त हमारे देश में अंग्रेजी का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए एक विशेष संस्था हैदराबाद में कायम की गई है, जिस पर भी लाखों रुपया खर्च होगा। इस प्रकार जो धन सृजनात्मक कार्यों और आर्थिक उत्पादन के लिए काम में लाया जा सकता था, वह आज इस विफल प्रयास में खर्च किया जा रहा है कि इस देश को अंग्रेजी भाषा-भाषी बना दिया जाय और यहाँ की भाषाओं का अस्तित्व नष्ट हो जाय। कैसे मजे की बात है कि अंग्रेजी की पढ़ाई प्राथमिक कक्षाओं में तो अनिवार्य की जा रही है ; किन्तु जिस हिन्दी को हमारी प्रभुता-सम्पन्न सविधान-सभा ने सघ की भाषा विहित किया था, उसकी पढ़ाई कई प्रदेशों में अनिवार्य नहीं की गई है और यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वह उन प्रदेशों में प्रवेश न कर पाये। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के मन में यह कल्पना वर्तमान है कि अंग्रेजी को प्राथमिक करके इस देश के वासियों को वैसा ही अंग्रेजी का ज्ञान करा दिया जाय, जैसा कि अफ्रिका में नीग्रो लोगों को कराया गया और इस प्रकार उन्हें टूटी-फूटी अंग्रेजी में अपनी बात व्यक्त करने के योग्य बनाकर कह दिया जाय कि इस देश के अधिकतर वासी अंग्रेजी भाषा-भाषी हैं और इसीलिए

अंग्रेजी का ही यहाँ अक्षुण्ण साम्राज्य बना रहे। यद्यपि उनकी परिकल्पना कभी भी सफल नहीं हो सकती, किन्तु, फिर भी वे लोग मोहवश इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और किसी-न-किसी बहाने से देश के धन, समय और शक्ति का अपव्यय इस लक्ष्य-पूर्ति के लिए कर रहे हैं। किन्तु, स्पष्ट है कि इस प्रकार हमारे देश की महान् हानि हो रही है। अंग्रेजी के कारण हमारा नैतिक पतन भी कुछ कम नहीं हुआ है। हमारे देश में भ्रष्टाचार और युवकों में अनुशासनहीनता और उद्दण्डता भी बहुत कुछ इसी कारण फैली है कि अंग्रेजी देशों से आनेवाली कौमिक पढ़-पढ़कर हमारे विद्यार्थी कुछ ऐसी बातों की ओर आकृष्ट होते हैं, जो हमारी मर्यादाओं, हमारी परम्पराओं, हमारे आदर्शों के सर्वथा प्रतिकूल हैं। और इस प्रकार अनुशासन का आधार अर्थात् आदर्शों में आस्था और परम्पराओं के प्रति आदर नष्टप्राय होता जा रहा है। साथ ही अंग्रेजी के मोह के कारण हमारे देश में आज यह भावना घर करती जा रही है कि हमारी भाषाएँ पगु हैं और इस प्रकार हमारे देश में ऐसे वर्ग की सृष्टि हो रही है, जो अपनी जाति, अपनी भाषा और अपने देश का भद्दा परिहास करने से नहीं चूकता। आजकल इस वर्ग के लोग यत्र-तत्र भारतीय भाषाओं और विशेषतः हिन्दी का मजाक उड़ाते दिखते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द लेकर वह उसके लिए कोई मनमाना हिन्दी का लम्बा-चौड़ा पर्याय देकर और उस पर्याय के प्रति परिहास कर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हिन्दी-जैसी उपहासास्पद भाषा कोई हो ही नहीं सकती। उन लोगों के मन में संभवतः यह विचार उठता ही नहीं कि अपनी भाषा का परिहास अपनी जननी का परिहास है। भाषा हमारी माता के समान होती है, वह हमारे सांस्कृतिक शरीर की रचना करती है, उसका पोषण करती है, उसको अनुप्राणित करती है ; अतः अपनी भाषा पर कीचड़ उछालना अपनी माँ पर कीचड़ उछालना है। मैं ससार भर में घूमा हूँ ; पर मुझे एक भी ऐसा देश और जाति नहीं दिखाई दी, जिसके लोग अपनी भाषा का स्वयं अनादर तो क्या किसी अन्य से भी अनादर सहन कर सकें ; किन्तु, इस अंग्रेजी-मोह के कारण हमारे देश में ऐसे लोग हैं, जो इस बात से कभी नहीं हिचकिचाते कि वे अपनी भाषा का अनादर करें और उसकी खिल्ली उड़ाये। जब भी वे बोलते हैं, तभी वे अपनी भाषा का परिहास करते हैं और उसके लेखकों और उपासकों की खिल्ली उड़ाते हैं। उन्हें सम्भवतः यह ख्याल नहीं आता कि ऐसा करके वे अपने मुख पर ही कलक-कालिमा पोत रहे हैं और यदि आता भी है तो संभवतः अपने अंग्रेजी-प्रेम के कारण वे अपना काला मुँह करने के लिए भी तैयार हैं। इतना ही नहीं, इस अंग्रेजी के कारण हमारा देश एक प्रकार से इंग्लैंड का अनुवाद बनाया जा रहा है। वैसे ही अनुवाद, जैसा कि शेक्सपियर ने अपने एक नाटक में अपने एक पात्र का करके दिखाया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगो ने “मिड सॉमर

नाइट्स ड्रीम” नाटक पढा होगा। इसमें एक पात्र बाटम नामी है, जिसके सिर पर एक मसखरे वनदेव ने गधे का सिर रख दिया था। उसे देखकर उसका मित्र, सहसा कह उठता है—“Bottom Thou art Translated.”

### हमारी भाषाओं पर अक्षमता का आरोप

हमारे ये अंग्रेजी के उपासक यह माने बैठे हैं कि हमारे देश में जो कुछ अच्छाई आती है, वह सब अंग्रेजी-साहित्य के अनुवाद से आती है और इसीलिए वह समय-समय पर इस देश की भाषाओं के उपासकों को चुनौती देते रहते हैं कि इस अंग्रेजी शब्द का क्या देशी पर्याय है, या उस अंग्रेजी शब्द का क्या देशी पर्याय है, मानो कि हमें अंग्रेजी के पर्यायों के अतिरिक्त और कुछ काम रह नहीं गया है। वे बार-बार कहते हैं कि देशी भाषाओं में यह क्षमता नहीं कि वे अंग्रेजी शब्दों के विभिन्न ध्वनियों को व्यक्त कर सकें और इसीलिए उनमें यह क्षमता भी नहीं है कि वे अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध अमूल्य वैज्ञानिक, दार्शनिक और अन्य प्रकार की निधियों को यथावत व्यक्त कर सकें। इस बात का वह ढिंढोरा सारे जगत् में पीटते हैं कि भारतीय भाषाएँ पगु है, अक्षम हैं और इसलिए भारत में अंग्रेजी रखी जा रही है और रखी जायगी, पढ़ाई जा रही है और पढ़ायी जायगी। कैसा पतन है यह हमारा कि हम यह मान बैठे कि हम में अपनी कोई नैसर्गिक सृजन-शक्ति नहीं है, हम कोई मौलिक सृष्टि नहीं कर सकते, हम ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कुछ नहीं दे सकते। यह बात कि किसी विशेष अंग्रेजी शब्द की सब ध्वनियों को हम किसी एक भारतीय शब्द से व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, जिससे भारतीय भाषाओं को किसी प्रकार की अक्षमता लेशमात्र सिद्ध होती हो। हर शब्द के पीछे उस जाति का इतिहास होता है, उस भूमि का वातावरण होता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिस जाति और जिस देश में उस शब्द का प्रयोग होता रहा है। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द के पीछे इंग्लैंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ, इंगलिश जाति का इतिहास और वहाँ के सामाजिक सम्बन्ध और सस्थाएँ हैं; अतः भारतीय भाषाओं का तो प्रश्न ही क्या, ससार की किन्हीं अन्य भाषाओं में भी ऐसा कोई शब्द नहीं मिल सकता, जो उनकी सब ध्वनियों को यथावत व्यक्त कर सके। इसी प्रकार भारतीय भाषाओं के शब्दों के लिए भी अंग्रेजी में कभी ऐसे पर्याय नहीं मिल सकते, जो उनके शुद्ध स्वरूप और विभिन्न ध्वनियों को यथावत व्यक्त कर सकें। मैं पूछता हूँ कि क्या कोई अंग्रेजी का महारथी मुझे जलेबी, बालूसाई गुलाबजामुन, दहीबड़े, चाट जैसे हमारे साधारण शब्दों का ठीक-ठीक अंग्रेजी पर्याय बता सकता है? तब क्या यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा पगु है, अक्षम है और उसमें विचारों की अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं है। बात यह है कि जब भी एक

भाषा में निहित विचारों को और भावनाओं को दूसरी भाषाओं में अनूदित करने का अवसर आता है, तब यह संभव नहीं होता कि अनुवाद पूर्णतः मूल को ध्वनित कर सके। थोड़ा-बहुत अन्तर रह ही जाता है ; पर इस कारण किसी भाषा की अक्षमता की दुहाई नहीं पीटी जाने लगती। जो लोग माता के समान आदरणीय अपनी भाषा का उपहास और तिरस्कार करने पर तुले हुए हैं, वे भला यह कहने में क्या सकोच करेंगे कि हमारी भाषाएँ आधुनिक जगत् के योग्य नहीं हैं। इस सबध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आजकल हिन्दी का तिरस्कार करने के लिए बराबर यह कहा जाता है कि जो हिन्दी काम में लायी जा रही है, वह इतनी क्लिष्ट, इतनी दुरूह है और की जा रही है कि कोई उसे नहीं समझ सकता। मेरी यह मान्यता है कि यह बात उन लोगों द्वारा अधिकतर दुहराई जा रही है, जो हिन्दी के कभी समर्थक नहीं थे, जिन्होंने जीवन में हिन्दी कभी नहीं पढ़ी, जो हिन्दी से आज भी लगभग अपरिचित हैं, और जो यह समझते हैं कि वही भाषा सरल है, जो उनकी अपनी समझ में आ जाय ; अर्थात् जो स्वयं अपने को ही इस बात का मापदण्ड माने बैठे हैं कि कौन-सी भाषा दुरूह और कौन-सी भाषा सरल है। कम-से-कम जो लोग वैज्ञानिक दृष्टि से सब प्रश्नों पर विचार करने की दुहाई देते हैं, उन्हें यह तो सोचना चाहिए कि स्वयं अपने को ही और अपने ज्ञान को ही किसी प्रश्न के निर्णय के लिए मापदण्ड न मान लेना चाहिए। विज्ञान का यह पहला सिद्धांत है कि निजी व्यक्तित्व को ओझल करके प्रश्न पर विचार किया जाय , किन्तु हिन्दी का यह दुर्भाग्य है कि उसके विषय में विचार करते समय कुछ ऐसे महान् व्यक्ति भी, जो सब दृष्टि से परम पूज्य और आदरणीय हैं, इस विचार की इस वैज्ञानिक प्रणाली को भूल जाते हैं। आज जो हिन्दी लिखी जा रही है, वह वहाँ तक बोधगम्य और जनप्रिय है, इस बात का निर्णय तो इसी से हो जाता है कि हिन्दी के समाचार-पत्र, हिन्दी पुस्तकें, जनता में कितनी बिकती हैं, कितनी पढ़ी जाती हैं। स्मरण रहे कि ये हिन्दी की पुस्तकें या ये हिन्दी के समाचार-पत्र ऐसी परिस्थितियों में जनता द्वारा गृहीत किये जा रहे हैं, जो हिन्दी और अन्य देशी भाषाओं के सर्वथा प्रतिकूल कर दी गई हैं। आज हिन्दी और देशी भाषाओं को वैसे कोई सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं, जैसी अंग्रेजी के लिए उदारता से उपलब्ध की जा रही हैं। यह सभी को ज्ञात है और इस सम्बन्ध में लोक-सभा राज्य-सभा आदि में काफी प्रश्नोत्तर तथा भाषण हो चुके हैं कि हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों को सरकारी विज्ञापन उस प्रकार नहीं मिलते, जिस तरह अंग्रेजी पत्रों को मिलते हैं, चाहे इन भारतीय भाषाओं के पत्रों की ग्राहक संख्या अंग्रेजी पत्रों से अधिक ही क्यों न हो। विज्ञापन देने के संबंध में सरकार की इस नीति में तुरन्त परिवर्तन होना आवश्यक है। बिना इसके भारतीय भाषाओं के पत्रों का

स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता और न उसका आर्थिक ढाँचा सुधर सकता और न उसका सम्मान ही बढ़ सकता है। क्या सघ और क्या राज्य, सर्वत्र ही अंग्रेजी पढ़े-लिखे को ही शासन में पद मिलता है। जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं, वह सेवा-आयोगों द्वारा ली जानेवाली परीक्षाओं में कदापि सफल नहीं हो सकता। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जिन प्रदेशों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाएँ कर दी गई हैं, वहाँ के विद्यार्थी इन परीक्षाओं में अपने को पिछड़ा हुआ पाते हैं। इस प्रकार उन प्रदेशों को दब दिया जा रहा है, जिन्होंने भारतीय भाषाओं का आचल पकड़ा है। फिर इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि अनेक माता-पिता, जो अपनी सतान का भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं, इस बात की माँग करें कि अंग्रेजी पुनः शिक्षा का माध्यम बनाई जाय और अंग्रेजी का स्तर ऊँचा किया जाय। साथ ही इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि हमारे देश का अभिजात वर्ग इस का प्रयास करे कि उस के पुत्र-पुत्रियाँ अंग्रेजी या पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पा जायें। कुछ दिन हुए एक आंग्ल भारतीय नेता ने दम्भ के साथ कहा था कि मंत्री लोग भी आंग्ल भारतीय विद्यालयों में अपने बालकों को प्रविष्ट करने के लिए लालायित रहते हैं; पर जब हिन्दी और अन्य देशी भाषाओं के गले में फाँसी डाल दी गई है और उनका आसरा लेने वालों के लिए कोई भविष्य नहीं छोड़ा गया है, तब इस में क्या आश्चर्य कि अपने बालकों को उच्च आसन पर बैठालने के इच्छुक माता-पिता इन आंग्ल भारतीय विद्यालयों में उनका प्रवेश करना चाहें। इस पर भी देशी भाषाओं की पुस्तकें लाखों की संख्या में बिकती हैं और पढ़ी जाती हैं और पाठकों को कभी यह नहीं लगता कि उनकी भाषा उनकी समझ में नहीं आती।

### अंग्रेजी भक्तों की वैज्ञानिक शब्दावली का फार्मूला

मजे की बात यह है कि लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि हिन्दी अत्यन्त सरल बनाई जाय, उन्हीं लोगों ने यह फँसला भी कर दिया है कि जहाँ तक वैज्ञानिक शब्दावली का प्रश्न है, वह पूरी-की-पूरी अंग्रेजी भाषा से ज्यो-की-त्यो ले ली जाय। क्या यह बात उन्हें नहीं दिखती कि वह शब्दावली हमारे देशवासियों के लिए अत्यन्त दुरूह और क्लिष्ट होगी और यहाँ के ९९.९ प्रतिशत लोग उसे समझने में पूर्णतः असमर्थ होंगे। मैं इस संबंध में आपके समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। नीम जैसे सरल सुबोध और जनप्रिय शब्द के लिए अब हमारी वैज्ञानिक शब्दावली में *Azadirachta Indica* लिखा जायगा। मैं नहीं जानता कि आपसे कितने लोग और आप में से ही क्यो, इस देश में से कितने लोग इस शब्द को समझ पायेंगे। मैं तो यह भी कहता हूँ कि अंग्रेजी के हिमायतियों में से भी ९९ प्रतिशत इस को बोल न सकेंगे,

समझने का तो प्रश्न ही क्या। ऐसा ही दूसरा शब्द हल्दी है, जिसके लिए हमारी वैज्ञानिक शब्दावलियों में लिखा जायगा *Circuma Tonga* धनिये के लिए लिखा जायगा *Coriandrum Satibum* हींग के लिए लिखा जायगा *Ferula Asa Foetida* इसी प्रकार सोने को *Aurum* कहा जायगा, लोहे को *Eerrum* और सीसे को *Plumbum* कहा जायगा। मैंने कुछ अन्य शब्दों की एक सूची तैयार की है, जिसको यहाँ पढ़कर सुनाना आवश्यक नहीं है; किन्तु, इस भाषण की प्रतियों के साथ संलग्न है। इस सूची में तो कुछ ही शब्द दिये हुए हैं; किन्तु ऐसे ही लाखों शब्द, जिन्हें कोई नहीं समझ सकता, हिन्दी पर लादने का निश्चय किया जा चुका है। मैं यह पूछता हूँ कि सरलता का सिद्धान्त इस क्षेत्र में क्यों लोप हो गया? यदि यह कहा जाय कि वैज्ञानिक क्षेत्र में यह आवश्यक है कि शब्द बड़े निश्चित और सघे हुए हो और इसलिए कठिन शब्दों से नहीं बचा जा सकता, तो फिर यह कहना कि अन्य क्षेत्रों में सूक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए या भावों की चामत्कारिक अभिव्यक्तियों के लिए कठिन शब्द आवश्यक न होंगे, ठीक नहीं है। शब्दों का चयन विषय के अनुसार होता है और एक विषय वाले को दूसरे विषय के शब्द दुरुह लगा करते हैं। इसका एक बड़ा उत्तम उदाहरण अभी हाल में मिला है। संयुक्त राष्ट्र में वक्ताओं के भाषणों का तात्कालिक अनुवाद करने के लिए अत्यन्त योग्य अनुवादक और कई भाषाओं के ज्ञाता नियुक्त हैं। कुछ दिन हुए, एक वैज्ञानिक के सम्मेलन में इन अनुवादकों को वैज्ञानिकों के भाषणों का अनुवाद करने का काम सौंपा गया, किन्तु इनमें से एक भी उसे न कर पाया, क्योंकि जिन विषयों की चर्चा इस वैज्ञानिक सम्मेलन में थी, उन विषयों से ये अनुवादक परिचित न थे, अतः यदि हिन्दी की, अन्य भारतीय भाषाओं के विभिन्न विषयों सम्बन्धी शब्दावली, हमारे कुछ राजनीतिकों की समझ में न आये, तो उन्हें यह न समझना चाहिए कि जान-बूझकर कोई इन भाषाओं को दुरुह बना रहा है और कम-से-कम उन लोगों को तो इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार हो ही नहीं सकता, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में से किसी को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया है; अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि अंग्रेजी के भक्त हमारी भाषाओं का निरादर और अपमान करने से अब अलग रहे। यह हमारे देश का अपमान है, हमारी सांस्कृतिक जननी का अपमान है।

#### अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार अंग्रेजी—एक भ्रमजाल

ऐसे ही खेद की यह बात है कि अंग्रेजी के कारण हम में कुछ यह भावना पैदा हो गई है कि हम विदेशियों से कुछ हेय हैं और हम उनके समकक्ष तभी हो सकते हैं, जब हम उनकी भाषा में ही या अंग्रेजी के माध्यम द्वारा उनसे बात करें। मेरी



यह मान्यता है कि यही हेयता की भावना इस तर्क के पीछे है कि बाह्य जगत् से हमारा संपर्क केवल अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही हो सकता है। कहा यह जाता है कि आज संसार के विभिन्न देश एक दूसरे के अत्यन्त निकट आ गये हैं और इसलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति के लिए यह वांछनीय है कि सारे भू-मंडल से अपना संपर्क बनाये रखे। और जहाँ तक हमारे देश का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि यह संपर्क केवल अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही रखा जा सकता है, पर प्रश्न यह होता है कि हमारे लिए ही यह क्यों आवश्यक है कि हमारा बाह्य जगत् से सम्पर्क अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही हो ? यह बात फ्रांस, रूस, दक्षिण अमेरिका, चीन आदि के लिए आवश्यक क्यों नहीं है ? क्या इन देशों का बाह्य जगत् से सम्पर्क नहीं है ? क्या ये लोग संयुक्त राज्य मे केवल अंग्रेजी के द्वारा ही विचार-विनिमय करते हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि दक्षिणी अमरीका के राज्यो के प्रतिनिधि स्पेनिश भाषा के माध्यम द्वारा, रूस के प्रतिनिधि रूसी भाषा के द्वारा, फ्रांस के प्रतिनिधि फ्रांसीसी भाषा के द्वारा और चीन के प्रतिनिधि चीनी भाषा के द्वारा सब काम वहाँ करते हैं ? यदि वे लोग अपनी-अपनी भाषाओं के माध्यम द्वारा बाह्य जगत् से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं, तो फिर ऐसी कौन-सी बाधा है कि हम अपनी भाषा के माध्यम से बाह्य जगत् से सबध स्थापित न कर सके ? यह ठीक है कि आज संयुक्त राष्ट्र मे हिन्दी एक स्वीकृत भाषा नहीं है; किन्तु क्या इसका यह कारण नहीं है कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय हम परतन्त्र थे और अंग्रेजी के दास थे, अतः वहाँ हमारे संबंध में यह विचार ही पैदा न हुआ कि हमारी भी कोई माँग हो सकती है। चीन ने अपनी गरिमा रखने के लिए अपनी भाषा को वहाँ मान्य कराया ; किन्तु क्या स्वतन्त्र होने के पश्चात् हमने एक दिन भी यह प्रयास किया कि हमारी भाषा उस सगठन की एक स्वीकृत भाषा हो जाय ? पर हम करते ही कैसे, जब हम अपने देश मे ही अपनी भाषा को राज्यासन पर बैठालने को उत्सुक नहीं हैं। परिणाम यह हुआ है, कि विदेशी हमको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं और समझते हैं कि हम ऐसी बर्बर जाति के लोग हैं, जिनकी अपनी कोई भाषा नहीं। और जो अपने भूतपूर्व शासकों की भाषा के जूठन से काम चलाते हैं। कैसा पतन है यह उस देश का, जिसकी भाषा एक दिन सारे दक्षिण एशिया और अन्य देशों की विचार-विनिमय की भाषा थी। जिसमे अनेक देशों के विद्यार्थी उस भाषा का ज्ञान उपाजित करने को आते थे और जो देश सारे सम्य जगत् का सांस्कृतिक केन्द्र था। कैसा पतन है कि आज उस देश के वासी इस बात मे अपना गौरव समझते हैं कि उनकी सन्तान केवल अंग्रेजी बोल सकती है, इस देश की एक भाषा भी नहीं हमारी आत्मा का हनन इससे अधिक और क्या हो सकता है और यह सब इसलिए

हुआ है कि अंग्रेजी हम पर लादी गई। राजनीति-शास्त्र में एक सूत्र है कि यदि कोई जाति अन्य जाति पर अपना राज पूर्णतः जमाना चाहती है, तो उसे यह चाहिए कि वह विजित जाति की भाषा नष्ट कर दे। अंग्रेजों ने इस प्रयोजन से हम पर अंग्रेजी लादी थी। वे हमारी भारतीय आत्मा का हनन करना चाहते थे। वे इस में कुछ सीमा तक सफल हुए; किन्तु हमारी क्रांति ने उन्हें पूर्णतः सफल न होने दिया। पर, आज हमारी आत्मा की इस शत्रु को हम पर क्यों लादा जा रहा है?

**अंग्रेजी भाषा से मुझे कोई द्वेष नहीं, पर...**

मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मुझे अंग्रेजी भाषा से कोई विद्वेष नहीं है; किन्तु जो काँटा मेरे मन में चुभता है, वह यह है कि इस भाषा को हमारे देश में विषमता का, शोषण का, वर्ग-प्रभुत्व का साधन बनाया जा रहा है और इसका ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि जिससे हमारे देश की आत्मा का हनन हो। इस विषय में मेरा वही मत है, जो अंग्रेजों के सबंध में गांधीजी का था। वे सदा कहते थे कि उनकी अंग्रेज जाति से शत्रुता नहीं, अंग्रेजों से वे प्रेम करते हैं; परन्तु यह होते हुए भी अंग्रेजी राज्य इस देश पर अस्वाभाविक है, इस देश की समस्त पीड़ाओं का कारण है; इसलिये उसे जाना ही चाहिए, अंग्रेजी भाषा के संबंध में भी मेरी यही स्थिति है। यदि अंग्रेजी से ऐसे ही बरता जाय, जैसा कि अन्य विदेशी भाषाओं से बरता जाता है, तो मैं उसका स्वागत करूँगा। न तो मुझे और न किसी हिन्दी या भारतीय भाषा-प्रेमी को इस बात में कोई आपत्ति है, या हो सकती है कि जो लोग चाहें वे अंग्रेजी सीखें, चाहें फ्रांसीसी सीखें, चाहें चीनी सीखें। यदि कुछ लोग कई भाषाएँ सीखना चाहते हों, तो यह भी अच्छी बात होगी और इसके लिये प्रबन्ध होना चाहिये; किन्तु केवल इस दृष्टि से कि यहाँ अंग्रेजी लादी जाय, यह दलील देना कि कई भाषाओं का ज्ञान उपाजर्जन हर विद्यार्थी के लिए वांछनीय है, कुछ उचित बात नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आज इस वांछनीयता की दुहाई देते हैं, उनमें से कितने ने यह सोचा भी है, प्रयास करने का तो प्रश्न ही नहीं, कि वे इस देश की कुछ भाषाएँ सीख लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त उन्होंने कोई और भाषा सीखने का विचार तक नहीं किया और यहाँ तक कि जो भाषा उन्हें अपनी माता से मिलती थी, उसको भी उन्होंने भुला दिया और यह प्रयास किया कि उनकी सतान अंग्रेजी के अतिरिक्त न और कुछ जाने न बोले। अंग्रेजी के मोह में वे इतने पागल हैं कि इस विचार से कि पाँच छै वर्ष की अवस्था से हमारे देश के बालकों को वे अनिवार्यतः अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तर्क दे सकें, उन्होंने अंग्रेजी बोलने वाले देशों से विद्वान् बुला कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि छोटे बालकों

के लिए कई भाषाएँ सीख लेना बहुत आसान होता है और इसीलिए छोटी कक्षाओं में ही उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई करना आरम्भ कर दी है। पर प्रश्न यह होता है कि अंग्रेजी की ही क्यों? क्या इस देश की कई भाषाओं का ज्ञान कराना ठीक नहीं? पर ऐसी कोई योजना नहीं दिखाई पड़ती। कहा यह जाता है कि फ्रांस का राजकुल अपने मुकुट को आँखों पर धरे पहाड़ के कगार पर जा रहा था और खड्ड में गिर पड़ा एव विनष्ट हो गया। कही इतिहास यह न कहे कि भारत में अंग्रेजी-वर्ग इस अंग्रेजी मुकुट को आँखों पर धरे इसी प्रकार खड्ड में जा पड़ा। मेरा यह प्रयास है कि समय रहते हम सँभल जाये और इसी दृष्टि से मैं आप सब का आह्वान करता हूँ कि आप इस महाप्रयास में लग जायँ कि इस देश की भाषाएँ शीघ्रातिशीघ्र राज्य-क्षेत्र में अपना उचित स्थान पा जायँ।

### सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं का माध्यम

इस प्रयास के दो पहलू हैं। एक तो उन बाधाओं को हटाना, जो हमारी भाषाओं की प्रगति को अवरुद्ध कर रही है। मेरे विचार में सब से बड़ी बाधा तो यह है कि लोक-सेवा-आयोगों की परीक्षा का माध्यम आज सर्वत्र केवल अंग्रेजी है—यह उन प्रदेशों के प्रति घोर अन्याय है, जिन्होंने देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना लिया है। इन प्रदेशों के विद्यार्थी इन परीक्षाओं में पिछड़े रह जाते हैं और इसलिए इन प्रदेशों में भी यह प्रयास हो रहा है कि शिक्षा का माध्यम पुनः अंग्रेजी हो जाय। कम-से-कम विश्वविद्यालयों के शिक्षक इसी आधार पर यह तर्क देते हैं कि उच्च शिक्षा का माध्यम अभी अंग्रेजी ही रहना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे देशी भाषाओं के प्रति इस घोर अन्याय को अविलम्ब बन्द कर दें; इसलिए हिन्दी और अन्य देशी भाषाएँ इन परीक्षाओं का माध्यम स्वीकार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि हमारे देश की भाषाएँ इन परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची में भी सम्मिलित की जाये। यह कितनी भारी विडम्बना है कि इन परीक्षाओं के लिए योरप की प्रादेशिक भाषाएँ; अर्थात् फ्रेंच, जर्मन इटालियन इत्यादि-इत्यादि तो वैकल्पिक विषयों की सूची में हों; किन्तु इस देश की एक भी प्रादेशिक भाषा उस सूची में न हो। मानो हमारे राज-कर्मचारियों के लिए फ्रांसीसी या स्पेनिश सीखना तो बांछनीय है; किन्तु इस देश की एक भी प्रादेशिक भाषा जानना या सीखना बांछनीय नहीं है। अंग्रेजों ने तो इस देश की भाषाओं को इन परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषय इसलिए नहीं रक्खा था कि उनकी तुलना में यहाँ परीक्षार्थी अधिक सफलता प्राप्त न कर पाये और योरप की प्रादेशिक भाषाओं को इसलिये

रखा था कि अंग्रेजी परीक्षार्थी भारतीयों की अपेक्षा उन परीक्षाओं में अधिक सख्या में सफल हो सके, किन्तु आज किस सिद्धान्त पर भारतीय भाषाओं का यह बहिष्कार किया जा रहा है? इस बहिष्कार के कारण भी इन भाषाओं की प्रगति में बाधा पड़ रही है और यह अब अविलम्ब दूर होना चाहिए।

### उच्च न्यायालयों की भाषा

इसके अतिरिक्त आज हमारी भाषाओं के सामने यह बाधा भी है कि उनका प्रयोग उच्च न्यायालयों में नहीं हो सकता। हमारा आज जो सविधान है, उसमें यह एक उपबन्ध है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा केवल अंग्रेजी होगी। परिणामतः वहाँ व्यवसाय करने वाले सब लोग अंग्रेजी का ही प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। स्वभावतः सारे विधि-व्यवसायियों का हित इसी में हो जाता है कि वे देशी भाषाओं से कुछ विशेष वास्ता न रख कर अंग्रेजी से ही अपना वास्ता रखें। विधि के क्षेत्र से हमारी भाषाओं के इस बहिष्कार के कारण भी वे पनप नहीं पाती। कैसी अजीब बात है कि जिस देश के निन्यानवे प्रतिशत लोग अंग्रेजी का एक शब्द नहीं समझते, उनकी जीवन-व्यवस्था करने के लिए नियम और विधियाँ अंग्रेजी में ही बनायी जायँ। जो कारखानों में काम करते हैं और जिनके लिए अंग्रेजी 'करिया अक्षर भैस बराबर' है, उनके अधिकारों सबधी विधियाँ भी अंग्रेजी में बनायी जाये। परिणाम यह है कि विधियों से जो अधिकार हमारे जन-साधारण को मिले हुए हैं और जो दायित्व उन पर रखे हुए हैं, उनसे वे सर्वथा अपरिचित रह जाते हैं और कुछ मुट्ठी-भर अंग्रेजी पढ़े-लिखे हाथों की कठपुतली हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी न्याय-प्रणाली इस अंग्रेजी के कारण अत्यन्त खर्चीली और शिथिल गतिवाली हो गई है। जब कभी उच्च न्यायालय में कोई अपील जाती है, तब इस कारण कि उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, उस मुकद्दमे की पूरी कार्यवाही का उल्था अंग्रेजी में करना पड़ता है। इस उल्थे को पेपर बुक कहा जाता है और इस के तैयार करने में पर्याप्त धन और समय का खर्च होता है। कभी तो पेपर बुक पर हजारों रुपया खर्च बैठता है और वर्षों में वह तैयार होता है; किन्तु कैसे आश्चर्य की बात है कि न्याय-प्रणाली के इस दोष के प्रति विधि-आयोग ने सकेत तक नहीं किया है; क्योंकि अंग्रेजी का चश्मा उसकी आँखों पर भी चढ़ा हुआ था और वह अंग्रेजी से होने वाली इस हानि को देख ही नहीं सकता था। मैं समझता हूँ कि हमारी भाषाओं की इस बाधा को भी तुरन्त दूर कर देना चाहिए और इस बात की अनुमति चाहिए कि उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में देशी भाषाओं या हिन्दी का प्रयोग किया जा सके।

हमारी सविधान-सभा ने सर्वमत से हिन्दी को इस देश की राजभाषा स्वीकृत किया था। आज यत्र-तत्र इतर भाषा-भाषी कतिपय सज्जन हिन्दी का विरोध करते सुने जाते हैं। एक तो वे दक्षिण के चार राज्यों में से केवल तमिल भाषा-भाषी मद्रास के महानुभाव हैं और कुछ बंगाल के ; परन्तु यह विरोध रोटियों के कारण है और जिस मद्रास राज्य में यह विरोध दिख रहा है, वहाँ इस विरोध के साथ ही हिन्दी सीखने वालों की संख्या बढ़ी है। शेष भारत के किसी भी भाग में हिन्दी का कोई विरोध नहीं है। मैंने समूचे भारत के न जाने कितने दौरे किये हैं और करता भी रहता हूँ और यह बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूँ।

### साहित्य-सर्जन

दूसरा हमारे प्रयास का पहलू सर्जनात्मक हो—मैं इस संस्था को बधाई देता हूँ कि इसने इसके बारे में स्तुत्य कार्य किया है, किन्तु हम अब तक के कार्य से सतोष करके नहीं बैठ सकते। हमें इस देश की आत्मा की अभिव्यक्ति, अपने भाषाओं के माध्यम द्वारा ही हर प्रकार से करनी है। हमारे साहित्यकारों का यह धर्म है कि वे अपनी जीवनानुभूति अपनी भाषाओं के सुन्दरतम शब्दों में अभिव्यक्त करके इन भाषाओं के साहित्य-भंडार को परिपूर्ण कर दें। हमारा देश आज एक महत् यात्रा पर चल पड़ा है—ऐसी यात्रा पर, जो उस महामन्दिर में उपासना के लिए है, जिस के प्रसाद से हमारे देश के प्रत्येक नर-नारी का जीवन सब दृष्टियों से सम्पन्न, समृद्ध और आनन्दमय हो जायगा।

### आह्वान

पिछली शताब्दियों में अनेक कारणों से हमारा जीवन गतिहीन हो गया था और इस कारण हम अन्य जातियों से बहुत पिछड़ गये। हमें अब बड़े पग बढ़ा कर उनके समकक्ष आ जाना है और यह हम तब ही कर पायेंगे, जब हमारे प्रत्येक नागरिक के हृदय में वह ज्योति जग जाये कि उसके ही प्रयास पर उसका और हम सब का भविष्य निर्भर करता है। हमें उसे गतिमान बना देना है, गाँव-गाँव और नगर-नगर में हमें यह नवसदेश पहुँचा देना है। यह काम हमारे भाषा के साहित्यिकों का है, कवियों का है, कलाकारों का है और साथ ही हमारे दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का है। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप इस ज्योतिशिखा को लेकर, इस भाषा की अपार शक्ति को लेकर, ग्राम-ग्राम और नगर नगर में अलख जगाये। जन-मानस को आंदोलित कर दे, जिससे कि वे सब बाधाओं को हटा कर सब विदेशी जंजीरों को तोड़ कर अपना भाग्य-निर्माण करने के लिए और संसार की जातियों में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए द्रुतगति से अग्रसर हो सकें।

**अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,  
छत्तीसवां अधिवेशन, मेरठ  
अध्यक्षीय भाषण**

८ दिसम्बर १९४८

स्वागताध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधिगण, बहनो और भाइयो !

जिस स्थान पर आप परम पूज्य महात्मा गांधी, महामना मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद और अनेक दिग्गज विद्वान् तथा महान् हिन्दी प्रेमियों को आसीन कर चुके हैं, उस को आज मुझे देकर आपने अपनी महान् उदारता और परम अनुकम्पा का ही परिचय दिया है। इस प्रकार आपने अपनी गुण-ग्राहकता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यदि आपने यह किया होता, तब तो यहां कोई अन्य व्यक्ति ही विराजमान होता। आपकी इस उदारता और अनुकम्पा के बदले में रखे-सूखे धन्यवाद के अतिरिक्त मेरे पास देने को क्या रखा है? ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जिस विश्वास का आपने मुझे पात्र समझा है, उसके योग्य मैं हो सकूँ। अतएव, अब मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्राण श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन को प्रणाम कर इस कार्य के संचालन का प्रयत्न करता हूँ।

**श्रद्धांजलि**

महात्मा गांधी के निधन के पश्चात् इस सम्मेलन का यह प्रथम अधिवेशन हो रहा है। ससार में ऐसे महान् पुरुष शताब्दियों में आते हैं। इस देश में गौतमबुद्ध और ससार में ईसा के उपरान्त किसी ऐसे महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। इस देश के जीवन का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जिसे महात्माजी ने अपने व्यक्तित्व और कार्य से प्रभावित न किया हो। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का भी गांधीजी से निकट का सम्बन्ध रहा है। उधर इन्होंने अपना सम्बन्ध सम्मेलन से अवश्य तोड़ लिया था, परन्तु सम्मेलन को आज जो महत्व प्राप्त है, उस में गान्धीजी का कितना बड़ा हाथ था, यह किसी भी सम्मेलन-प्रेमी से छिपा नहीं है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते

हुए उन के इस वाक्य का स्मरण करते हैं—“भाई, मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। पूरी आजादी तो हमें अंग्रेजी की गुलामी छोड़ देने पर ही मिलेगी।”

हमारा ध्यान आज उन हिन्दी-प्रेमियों की ओर भी जाये बिना नहीं रहता, जिन से हमारा इस वर्ष वियोग हुआ है। उन में है—

श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान और बाबू रामधारीप्रसाद।

### सम्मेलन का कार्य

देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् हमारे इस सम्मेलन ने भी एक नये युग में प्रवेश किया है। सम्मेलन ने अब तक जो कार्य किया है, उस का सिंहावलोकन करना यहाँ उपयुक्त होगा। यह सिंहावलोकन तब तक सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता, जब तक कि सम्मेलन की स्थापना से पूर्व हिन्दी की दशा पर थोड़ा-सा विचार न कर लिया जाय।

सम्मेलन की स्थापना सन् १९१० में हुई। इसके पहले काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अतिरिक्त कदाचित् कोई ऐसी संस्था हिन्दी के क्षेत्र में काम नहीं करती थी, जो उल्लेखनीय हो। जिन क्षेत्रों में हिन्दी लोगों की मातृभाषा थी, वहाँ सन् १९१० में प्राथमिक शिक्षा हिन्दी में दी जाती थी। कालेजों की बात तो अलग रही, हाई स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो सकती है, इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी। पुराने काव्य-साहित्य को छोड़कर हिन्दी में बहुत थोड़े साहित्य का निर्माण हुआ था। उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए न उसमें ग्रन्थ उपलब्ध थे और न शिक्षक ही। विदेशी राज्य था और विदेशी भाषा में हमारे देश की सारी शिक्षा और परीक्षाएँ होनी थी। हाँ, यह अवश्य था कि देश के अधिक निवासियों की मातृभाषा हिन्दी थी और जिन की मातृभाषा हिन्दी न थी, वे भी (दक्षिण भारत के निवासियों को छोड़कर) हिन्दी समझ व बोल लेते थे। इस परिस्थिति में सम्मेलन ने अपना कार्य आरम्भ किया। सन् १९१४ में उस ने अपनी विशिष्ट परीक्षाएँ और उन के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किये। इसके लिए पाठ्य पुस्तकें बनने लगी। जो व्यक्ति पहले विद्यार्थियों के रूप में आये, वे ही आगे चलकर शिक्षक बने। पहले हिन्दी-क्षेत्र में ये परीक्षाएँ जनप्रिय हुई, और फिर अहिन्दी प्रान्तों में; यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक पहुँच गयी। आज इस देश का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जहाँ सम्मेलन के ‘विशारद’ और ‘साहित्यरत्न’ न हों।

ग्राम-उत्थान कार्यों में जिस प्रकार सरकार गांधीजी का अनुसरण करती थी और गांधीजी की ग्राम-सुधार की किसी योजना के बनने पर वह अपनी योजना

बना, उससे होड़ करने का प्रयत्न करती थी, उसी प्रकार हिन्दी में भी उच्च शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम सरकार ने सम्मेलन की परीक्षाओं के पश्चात् बनाये। विश्वविद्यालयों में हिन्दी की प्रतिष्ठा का आरम्भ यथार्थ में सम्मेलन की इन परीक्षाओं द्वारा ही हुआ।

शिक्षा और परीक्षाओं के अतिरिक्त हिन्दी के प्रति अहिन्दी प्रान्तों के विद्वानों और जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का भी महान् कार्य सम्मेलन ने ही किया। आज हिन्दी का राष्ट्रभाषा पद पर आसीन होना, एक स्वाभाविक-सी बात लगती है। इस का श्रेय सम्मेलन के प्रचार-कार्य को नहीं, तो और किसे है? हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जिन भावनाओं और जिन परिस्थितियों की आवश्यकता थी, उन का जागरण और निर्माण सम्मेलन ने ही किया। बिना सम्मेलन के इन प्रयत्नों के हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा और देवनागरी राष्ट्रलिपि हो सकती है, यह सोचा तक नहीं जा सकता था।

गत तीस वर्षों में हिन्दी में साहित्य-निर्माण की जो प्रगति रही, उस में भी सम्मेलन का कम हाथ नहीं रहा। सम्मेलन ने ही हिन्दी के स्तर को ऊँचा उठाया है। सम्मेलन की ओर से जो भिन्न-भिन्न पुरस्कार लेखकों को दिये जाते हैं, उन से साहित्य-सृजन में कम प्रोत्साहन नहीं मिलता। फिर सम्मेलन की ओर से भी अनेक महत्वपूर्ण और सुन्दर ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। सम्मेलन अधिक ग्रन्थों का प्रकाशन इसलिए न कर सका कि वह एक तो अन्य प्रकाशकों के साथ इस दिशा में प्रतिद्वन्द्विता करना नहीं चाहता था, वह केवल ऐसे शास्त्रीय ग्रन्थ ही प्रकाशित करने का इच्छुक था, जिन्हें दूसरे प्रकाशक प्रकाशित न कर सकते थे। दूसरे उसे मुद्रण आदि के सम्बन्ध में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसने अपने प्रेस का प्रबन्ध कर लिया है, परन्तु अब भी वह अन्य प्रकाशकों से प्रतिद्वन्द्विता न कर ऐसे ही शास्त्रीय ग्रन्थों को प्रकाशित करेगा, जिन्हें अन्य प्रकाशक प्रकाशित करने में असमर्थ रहेंगे।

जिस सग्रहालय की सम्मेलन ने स्थापना की है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं।

सबसे बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और उसकी विविध प्रांतीय शाखा-प्रशाखाओं का जैसा देश-व्यापी सगठन है, वैसा हिन्दी में न तो सम्मेलन की स्थापना से पूर्व कोई सगठन था और न आज है। यह भी स्मरण रहे कि सम्मेलन ने सारा कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों में किया है—इसे राजाश्रय प्राप्त न था, वरन् विदेशी सरकार ने सदा उस के कार्यों में बाधक होने का प्रयत्न किया। उस का सारा कार्य विदेशी राज्य के समय हुआ, जब अंग्रेजी का दौर-दौरा था।



### राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि

देश के स्वतन्त्र होने तक स्वतन्त्रता हमारा प्रथम लक्ष्य था। इस कार्य के सामने अन्य सारे कार्य गौण थे। देश के स्वतन्त्र होते ही स्वतन्त्र देश के विधान बनाने का प्रश्न हमारे सामने आया। विधान-परिषद् के निर्वाचन के पश्चात् विधान किस भाषा में बने तथा किस लिपि में लिखा जाय देश की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि कौन-सी हो, ये प्रश्न किसी-न-किसी रूप में विधान-परिषद् के सामने आते रहे हैं। यद्यपि इन का अन्तिम निर्णय अब तक नहीं हुआ ; पर मैं यह मानता हूँ कि बड़े-बड़े विरोधों के रहते हुए भी हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा और देवनागरी ही राष्ट्रलिपि घोषित होगी। एक बात और हो सकती है कि नागरी में लिखी जाने वाली 'भारती' हमारे देश की राष्ट्रभाषा निश्चित की जाय। यदि यह होता है, तो मैं इस का भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि भारत हमारे देश का प्राचीन नाम है। हिन्द और हिन्दुस्तान नाम तो उसे पीछे से मिला। हिन्द नाम के कारण भाषा का नाम भी हिन्दी हो गया। देश का नाम भारत और भारत देश की भाषा का नाम भारती, यह हमारी परम्परा और संस्कृति के अधिक अनुरूप है। हा, तो मैं आप से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का अब तक चाहे निर्णय न हुआ हो, पर हिन्दी या भारती ही हमारी राष्ट्रभाषा और नागरी ही राष्ट्रलिपि होगी। यदि और कुछ हुआ तो वह स्वाभाविक न होकर अस्वाभाविक होगा और कोई अस्वाभाविक बात स्थायी नहीं हो सकती।

अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा हो नहीं सकती। लगभग दो सौ वर्षों के अंग्रेजी राज्य के उपरान्त इस देश के कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं? हिन्दुस्तानी कोई भाषा है ही नहीं। उस का न कोई व्याकरण है, न साहित्य। जिस भाषा का अस्तित्व ही नहीं, वह राष्ट्रभाषा कैसे बनायी जा सकती? अंग्रेजी की 'कनसाइज आक्सफर्ड डिक्शनरी' में हिन्दुस्तानी को मुगल विजेताओं की भाषा कहा है। हिन्दुस्तानी कही जाने वाली भाषा में बाजारों में बोले जाने वाले शब्दों के अतिरिक्त वैज्ञानिक और शास्त्रीय शब्दों का न निर्माण हुआ है और न हो सकता है। साधारण पढ़ाई लिखाई भी या तो अंग्रेजी भाषा में हो सकती है या हिन्दी में या उर्दू में; हिन्दुस्तानी में नहीं। कुछ अकगणित, भूगोल और रेखागणित के शब्दों को ही लीजिए—

अंग्रेजी	हिन्दी	उर्दू
	अङ्कगणित	
Multiplieand	गुण्य	मज्जरब
Multiplier	गुणक	मज्जरबफी
Product	गुणनफल	हासिल-इ-जरब
Divisor	भाजक	मकसूम इलाह
Dividend	भाज्य	मकसूम
Quotient	भजनफल	खरफि-इ-किस्बत
L. C. M.	लघुत्तम समापवर्त्य	जुआजाफ इ-अकल
Decimal	दशमलव	आशारिया

भूगोल

North, South	उत्तर, दक्षिण	शुमल, जुनूब
East, West	पूर्व, पश्चिम	मशरिक, मगरिब
Isthmus	डमरूमध्य	खाकनाय
Continent	महाद्वीप	बर्ऐआजम
Archipelago	द्वीपसमुदाय	मजमूल उल जजायर

रेखागणित

Radius	त्रिज्या	निस्फकुतुर
Equilateral triangle	समत्रिबाहु त्रिभुज	मुसल्लस मुसाविलुल जिल
Diagonal	कर्ण	वतर
Right-angled		मुसल्लस
Isosceles triangle	समकोण समद्विबाहु त्रिभुज	मुसाविउस्सा कैन काय मुज्जाविया

झगडा हिन्दुस्तानी नाम का नहीं है, झगड़ा है हिन्दुस्तानी नाम में, जो अर्थ निहित हो गया है उस का। हिन्दुस्तानी का अर्थ वह भाषा है, जिस में इतने प्रतिशत शब्द संस्कृत, इतने फारसी, इतने अरबी के हों, फिर वह नागरी और अरबी लिपियों में लिखी जाने वाली भाषा है। कुछ महानुभावों का मत है कि भाषा का नाम हिन्दुस्तानी रखा जाय, पर वह एक ही लिपि नागरी में लिखी जाय; किन्तु भाषा केवल लिखने की न होकर बोलने की भी वस्तु है। यदि नागरी लिपि में

लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा घोषित हो, तो भी उस में कितने प्रतिशत शब्द किस भाषा के रहेंगे, यह प्रश्न उठेगा और रेडियो आदि में जहाँ भाषा लिखी न जाकर केवल बोली जाती है, सदा एक झगडा मचा रहेगा जैसा आज मचा है।

जो लोग हिन्दुस्तानी का विरोध करते हैं, वे किसी साम्प्रदायिक भावना से ऐसा करते हैं, यह मैं नहीं मानता, वरन् मैं तो यह कहता हूँ कि हिन्दुस्तानी का समर्थन न करने वाले उस का समर्थन साम्प्रदायिकता की भावना से करते हैं। जो देश में एक संस्कृति चाहते हैं, वे भला दो लिपियों में लिखी जाने वाली भाषा का समर्थन कैसे करेंगे ?

हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना इसलिए स्वाभाविक नहीं है कि वह अन्य प्रान्तीय भाषाओं से श्रेष्ठ है। हम अन्य प्रान्तीय भाषाओं को नीची और हिन्दी को उन से ऊँची नहीं मानते। हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना इसलिए स्वाभाविक है कि कुमायूँ से लेकर बस्तर तक और जैसलमेर से बिहार के पूर्वीय छोर के अन्तिम ग्राम तक हिन्दी ही लोगों की भाषा है। उसे इस देश की तीस करोड़ में से अठारह करोड़ जनता बोलती और बाइस करोड़ समझती है। संयुक्त प्रान्त, बिहार, महाकोशल, राजस्थान, मध्यभारत, विन्ध्य-प्रदेश, पूर्वी पंजाब, हिमांचल प्रदेश की भाषा हिन्दी है। दक्षिण भारत में भी उस का प्रचार अत्यन्त शीघ्रता से हो रहा है।

### राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाएँ

राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी हो जाने का कोई यह अर्थ न समझे कि हम भिन्न-भिन्न प्रांतों की प्रांतीय भाषाओं का गला घोटना चाहते हैं। विदेशी राज्य ने विदेशी भाषा को हमारे देश पर लादकर, उसी को हमारी शिक्षा का माध्यम, हमारी धारा-सभाओं और न्यायालयों की भाषा बनाकर, हम पर जो घोर अत्याचार किया था, ऐसी कोई बात करने की कल्पना तक हम नहीं कर सकते। जिन प्रांतों की भाषा हिन्दी नहीं है ; जैसे—बंगाल, आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिल, आन्ध्र, कर्नाटक, मलयालम आदि, उन प्रांतों में हम शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा को नहीं बनाना चाहते ; न वहाँ की धारा-सभाओं और न्यायालयों में हम हिन्दी को चलाना चाहते हैं। अहिन्दी प्रांतों की शिक्षा का माध्यम वहाँ की धारा-सभाओं और न्यायालयों की भाषा प्रान्तीय भाषा ही रहे। हा, केन्द्रीय तथा अन्तर्प्रान्तीय सारे कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही होने चाहिए और केन्द्रीय तथा अन्तर्प्रान्तीय सारे कार्य सुचारु रूप से चल सकें, इस के लिए समूचे भारत में राष्ट्रभाषा की शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए। हम इस बात के लिए भी प्रस्तुत हैं कि दक्षिण भारत तथा अहिन्दी प्रांतों के अपने भाइयों के सुविधार्थ

केन्द्र में भी हिन्दी के साथ-साथ कुछ समय के लिए अंग्रेजी का अस्तित्व रख लिया जाय। देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्रभाषा और प्रातीय भाषाओं दोनों का समान महत्व है, और दोनों की समान उन्नति आवश्यक है।

### राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी

अंग्रेजी भाषा से भी हमारी कोई शत्रुता नहीं। देश के बाहर की बातों के ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा लेना ही होगा। इन कार्यों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हम और किसी भाषा का आश्रय नहीं ले सकते।

### राष्ट्रभाषा और उर्दू

उर्दू और हिन्दी का कैसा सम्बन्ध रहेगा, इस पर भी कुछ कह देना आवश्यक जान पड़ता है। उर्दू भाषा से भी हमारा कोई द्वेष नहीं। हम उर्दू भाषा और उस के साहित्य का सम्मान करते हैं। वह इस देश में जन्मी और यही पनपी है। हम तो उसे हिन्दी की ही एक शैली मानते हैं, परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह जन्म लेने और पनपने वाली उर्दू भाषा का साहित्य, मुसलमानों को एक पृथक् समुदाय बनाये रखने में सहायता देता रहा है। उर्दू के साहित्य में हिमालय का वर्णन न होकर कोहकाफ का वर्णन होता है। वह साहित्य कोयल के स्थान पर बुलबुल को ही महत्त्व देता है। उस के वीर भीम, अर्जुन न होकर रस्तम आदि हैं। वह दधीचि और शिवि को छोड़ हातिम की उदारता का वर्णन करता है। हमारे मुसलमान भाइयों के मन में पार्थक्य की भावना है। भारतीय सस्कृति से अलग अपनी सस्कृति को रखने के विचार हैं। उस में सदा उर्दू और उसके साहित्य ने सहायता पहुँचायी है। पार्थक्य की इस भावना ने ही द्विराष्ट्र सिद्धान्त को जन्म दिया, जिस के कारण देश का विभाजन हो गया। भारत में रहने वाले मुसलमान भाई यदि अपने को अन्य भारतीयों से अलग मानेंगे, तो इस देश पर भविष्य में अनेक ऐसी आपत्तियाँ आ सकती हैं, जिन की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हिन्दू-धर्म ही सारे भारतीयों का धर्म नहीं है। दो धर्मों को मानने वाले भी एक कुटुम्ब में रहते हैं। पंजाब में एक ही कुटुम्ब में हिन्दू और सिख रहते हैं। राजस्थान में एक ही कुटुम्ब में वैष्णव और जैन रहते हैं। क्या ऐसी स्थिति नहीं आ सकती, जब एक ही कुटुम्ब में एक व्यक्ति हिन्दू और दूसरा मुसलमान रहे? हमारे पड़ोसी देश चीन और रूस में जब यह बात है, तब भारत में क्यों नहीं हो सकती? चीन और रूस में बौद्ध, ईसाई तथा मुसलमानों के धर्म पृथक्-पृथक् होने पर भी उन की सस्कृति पृथक्-पृथक् नहीं है। उन के नामों तक से इस बात का पता नहीं लगता

कि कौन किस धर्म को मानता है। हम चाहते हैं कि पार्थक्य की इस भावना को त्याग, मुसलमान भारतीय सस्कृति को अपनाकर इस देश के अन्य निवासियों में घुल-मिल जाये। वे भी हिंदी भाषा को अपना लें। महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, गुजरात, तमिल, आंध्र, कर्नाटक, मलयालम में रहने वाले मुसलमान इन प्रांतों की भाषाओं को ही बोलते और लिखते हैं। कुछ दिन पहले जब साम्प्रदायिकता का ऐसा दौर-दौरा नहीं था, तब इन प्रांतों के मुसलमानों में उर्दू का प्रचार न था, और हमारे हिंदी-भाषी मध्यप्रांत के मुसलमान हिंदी में ही सारे कार्य करते थे। अधिकांश उर्दू जानते तक न थे। प्राचीन समय में अनेक मुसलमानों ने हिंदी भाषा को अपनाकर, उस में उत्तम-से-उत्तम रचनाएँ की हैं। कबीर, जायसी, रहम, रसखान आदि का नाम हिंदी के इतिहास में सदा अमर रहेगा।

गत कुछ वर्षों से साम्प्रदायिकता के कारण उर्दू भाषा का एक विशेष प्रकार से प्रसार किया जा रहा है, जैसा मैंने अभी कहा। हम उर्दू के विरोधी नहीं हैं, पर जिस पार्थक्य की भावना से उर्दू का यह प्रसार हो रहा है, उस का कम-से-कम मैं घोर विरोधी हूँ।

### राष्ट्रभाषा का भावी स्वरूप

भाषा के नाम और लिपि के प्रश्न के साथ ही हमारी राष्ट्रभाषा कैसी हो, यह प्रश्न हमारे समाने है। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो सरल-से-सरल हो, जिसे सहज में सब लोग समझ सकें ; परन्तु जहाँ एक ओर भाषा की सरलता की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि हमारी भाषा में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग हो, जो सूक्ष्म अर्थ का भी यथातथ्य बोध करा सके। वैज्ञानिक और शास्त्रीय ग्रन्थों अथवा लेखों की भाषा बहुत सरल नहीं हो सकती। ललित साहित्य में भी कहानी, उपन्यास, नाटक की भाषा जितनी सरल हो सकती है, उतनी कविता की नहीं। यदि वैज्ञानिक और शास्त्रीय भाषा को हम सरल बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो भाषा में यथातथ्य बोध की शक्ति नहीं आ सकेगी। और यदि कविता में भी अत्यधिक सरलता लायी जायगी, तो भाषा-सौष्ठव नष्ट हो जायगा। हमारी भाषा में जो शब्द बाहरी भाषाओं के आ गये हैं, उन का बहिष्कार हमें नहीं करना है, वरन् हमें तो अन्य भाषाओं के और शब्द भी ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज जो अंग्रेजी भाषा इतनी उन्नत है, उस का प्रधान कारण यही है कि उसने अपने शब्द-कोश को अन्य भाषाओं के शब्दों से समृद्ध किया है। नारमन लोगो की जीन

के समय अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति थी और धीरे-धीरे उस की श्रीवृद्धि कैसे हुई, इसे हम देखें। हाल ही में आयरलैंड में गेलिक भाषा का किस प्रकार उत्थान हुआ, इस का अवलोकन करें ; परन्तु इसी के साथ अपनी भाषा के उद्गम और गठन को देखते हुए हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हम नये शब्दों के निर्माण में प्रधानतया संस्कृत से ही सहायता ले सकते हैं। तमिल के सदृश एक दो प्रातीय भाषाओं को छोड़ शेष हमारी सभी प्रान्तीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। संस्कृत से शब्द लेने पर हम अन्य प्रान्तीय भाषाओं के भी अधिक समीप रह सकेंगे।

संस्कृत की शब्द-सरिता भारतवर्ष की सभी साहित्यिक भाषाओं का पोषण करती है। उस की उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, अभिव्यजनाओं और सूक्तियों से भारत की प्रत्येक भाषा के ग्रन्थ ओतप्रोत हैं। वही भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। उस के शब्द प्रत्येक भाषा में इतने प्राचुर्य से प्रयुक्त हुए हैं कि कभी-कभी दो भारतीय भाषाओं में भेद करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए विश्व-विख्यात कवि-सम्राट् श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की “मानसी” नामक पुस्तक से “सूर-दासेर प्रार्थना” शीर्षक कविता लीजिए—

अपार भुवन, उदार गगन, श्यामल काननतल,  
वसन्त अति मुग्ध मूरति, स्वच्छ नदीर जल,  
विविधवरण सान्ध्यनीरद ग्रहतारामयी, निशि,  
विचित्र शोभा शस्य क्षेत्र प्रसारित दूर दिशि।  
सुनील गगने घनतर नील अति, दूर गिरिमाला,  
तारि परपारे रविर उदय कनक-किरण ज्वाला।  
चकित-तड़ित सघन वरषा पूर्ण इन्द्रधनु,  
शरत् आकाशे असीम विकास ज्योत्स्ना शुभ्रतनु।

इसे कौन कह सकता है कि यह हिन्दी कविता नहीं। तीन चार स्थलों पर बगला के प्रत्ययों और विभक्ति-चिन्हों को छोड़ कर केवल उत्तर ही नहीं, दक्षिण भारत भी इसे अपनी काव्य-सम्पत्ति कह सकता है।

पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र द्वारा लिखित हिन्दी के महाकाव्य ‘कृष्णायन’ की निम्नलिखित पंक्तियां लीजिए। इन्हें किसी भी भारतीय भाषा में अन्तर्भूत किया जा सकता है —

महिधर-शृंग शरीर विराटा,  
उत्तमांग, पथु, तुग ललाटा।

वक्ष शैलहिम-शिला विशाला,  
उत्थित वाम हस्त तरु शाला।  
कर दक्षिण षट-कोण भयकर,  
गदा उदग्र अशनि-प्रलयकर।

श्री सुमित्रानन्दन पंत की निम्नलिखित पक्तियों को कुछ ही विभक्तियों के परिवर्तन से प्रत्येक भारतीय समझ सकता है—

श्रवण गगन में गूँज रहे स्वर ॐ क्रतो स्मर कृत क्रतो स्मर !  
सृजन-हुताशन को हवि भस्वर बनी पुनः जीवन रज नश्वर !  
दृष्टि दिशा में ज्योति-मूर्त स्वर ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर,  
क्रतो स्मर कृत स्मर ;

—स्वर्णकिरण, पृष्ठ १४६।

गुजराती के आधुनिक कवि श्री नरसिंहराव भोलानाथ की “हृदय वीणा” शीर्षक कविता लीजिए—

सुन्दर शिव मंगलगुण गाऊँ ईश्वरा  
विभुवर भव भय हारक नमो महेश्वरा।  
मधुर कुसुम विशेष रमे गंध सुदरा,  
कौमुदी मुदप्रदा, उषा मनोहरा,  
मृदुलकण्ठ कोकिलरव श्रवणसुखकरा।

ये पक्तियाँ किसी भी भारतीय भाषा के कवि की हृदय-वीणा की झंकार हो सकती हैं।

सुदूर उड़ीसा प्रदेश की कविता भी इसी सांस्कृतिक और भाषा-ऐक्य की घोषणा करती है। उदाहरणार्थ—सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन राव की “भारत भावना” लीजिए—

एहि कि से पुण्य भूमि भुवन-विदित,  
सविस्तीर्ण रगभूमि आर्य-गौरवार ?  
एहि कि भारत, यार महिमा सगीत-  
गभीर-झंकारे पूर्ण दिग-दिगन्तर ?  
एहि कि से सुमनोज्ञ आशा-सरोवर,  
यार ज्ञानामृत-पाने कृतार्थ धरणी ?  
यार तेज विभासित देश-देशान्तर ?

दक्षिण में तमिल भाषी कहते हैं, उनकी भाषा में संस्कृत के शब्द नहीं। उन का यह कथन सर्वथा भ्रमपूर्ण है। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तमिल भाषा के सबसे बड़े कोश 'तमिल लैक्सीकन' पर दृष्टिपात करने से यह विदित हो जायगा कि तमिल की ५० प्रतिशत शब्दावली संस्कृत की है। महा शब्द से आरम्भ होने वाले शब्दों की ही संख्या आश्चर्यजनक है—

महाकच्छम्, महागदम् (=ज्वर), महागति, महाकन्द (=लशुन), महा-कपित्थ, महाखर्व, महाकवम् (=महाकवि), महाकल्पम्, माहहवम्, महाहासम् (=अट्टहास), महाकायम् (=हाथी), महाग्रीवम् (=ऊँट), महाच्छायम् (=बड़ का वृक्ष), महाज्वालम् (=यज्ञ की अग्नि) महासंधम् महाशखम्, महा-जम्बु, महाशयम् (=समुद्र) महाजनम्, महाशाखा, महासुखम्, महाश्वासरोगम्, महाश्वेतम्, महाशूरम्, महात्यागम्, महात्मा, महादन्त, (=हाथी), महाघनम् (=१ सोना २ कृषि), महाघातु (=सोना), महाद्रुम् (=पीपल), महातेजम् (=पारा), महानागम् महानिद्रा, (=मृत्यु), महानिधि, महानिम्बम्, महानीलम् आदि आदि।

केवल भारत ही नहीं, सिंहल, स्याम आदि देशों की भाषाएँ भी संस्कृत से अनुप्राणित हैं। उन की कविता, धार्मिक विचारधारा, प्रशासन की शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली आद्योपान्त संस्कृतमय हैं। हम सिंहली (लकानी भाषा) से भी सामान्य जीवन के कुछ शब्द उदाहरण के लिये लेगे। जहाँ पर भेद है, वहाँ अभिवारों में अर्थ दिया गया है। लोह (=घातु) गंगा (=नदी), वृक्या, (=भेड़िया), मध्यरात्रिय, विनाड़ी, (=मिनट), मोहोत (=मुहूर्त, सैकड़), वसंत, देवस्थानय (=ईसाई गिरजाघर), सज्ञाकणुव (साइनपोस्ट), पाठशालाव, नागरिकशालाव (=टाउनहाल) शरीरस्थिति (=स्वास्थ्य), शल्यवैद्य।

लका में सारे वैज्ञानिक शब्द संस्कृत से निर्मित किये जाते हैं —

तूर्यभाण्डय	पियानो
यन्त्रकारया	एजीनियर
मुद्राकणकारया	मुद्रक
रथचक्र	बाइसिकिल
रथचक्रसादना	बाइसिकिल बनाने वाला
गणन-पत्रय	बिल
आय-व्यय-लेखनय	औसत-पत्रक
सीमासहित समागम	लिमिटेड कम्पनी
धूमनाव	स्टीमर



उपद्रवारक्षक पत्रय

इश्योरेस पालिसी

दूरशब्दनयन्त्रय

टैलीफोन

लका मे ग्रन्थों के नाम भी संस्कृतमय है—

अरबी निशोल्लासव (Arabian Nights) सहस्र रजनी चरित्र, “आरोग्य दर्पण्य” लेखक गुणवर्धन, १९२१ मे प्रकाशित “देहलक्षण विधाव”, गुणवर्धन लिखत “धनोपायनक्रम” (१९१६), “गद्यविनिश्चय” (१९२७); रणसिंह रचित “गणित-शास्त्रय”, १९२६ मे मुद्रित “ज्योतिषकथोपकथनय” १९१४ मे प्रकाशित “महामारी रोग विभागय” आदि इसी शताब्दी की रचनाए है।

इसी प्रकार स्याम देश मे भी शब्दावली संस्कृतनिष्ठ है। कथा, कदाचार कदाहार (=हानिकर भोजन), कनिष्ठ भगिनी, कन्यकापति (=जामाता), कपटलेख आदि वहा के सामान्य शब्द है। प्रशासन सम्बन्धी शब्द लीजिए—

कर्म जलप्रदान	सिचाई विभाग
कर्म लोहकृत्य	खान विभाग
कर्म धर्मकार	धार्मिक विभाग
कर्म नगरादर	नगर-शासन विभाग

नीचे मै अर्थ सहित कुछ शब्दों की सूची देता हूँ, जिस से ज्ञात हो जायगा कि संस्कृतनिष्ठ शब्दावली ही समस्त भारत, स्याम, सिंहल, डच, हिंदेशिया आदि को पुन. प्रेम की शृङ्खला मे बांध सकेगी।

स्यामी शब्द	अर्थ
कर्मकार परिषद	कम्पनी का डाइरेक्टर
कर्मवाचा	कर्मवाच्य
कर्मशूर	चतुर काम करनेवाला
कर्मसंपादिका सभा	कार्यकारिणी सभा
कर्मसार्थी	साथ में काम करनेवाला
त्रिकोण	त्रिकोण
त्रिकोणमिति	त्रिकोणमिति
बीजगणित	बीजगणित
रेखागणित	रेखागणित
पाटीगणित	अंकगणित
ओष्ठज	ओष्ठ्य वर्ण
ओघ	जल का ओघा

एकचक्षु	काणा
एकमय	समरूपता
एकराज	राजा
एकसार	आवश्यक पत्र
एकवचन	एकवचन
उपराज	वाइसराय
उपचक्षु	चक्षमा

अन्तिम शब्द ध्यान देने योग्य है। स्याम का “उपचक्षु” बतलाता है कि यदि हम संस्कृत से ही सामान्य शब्द लेगे, तभी भारत की सांस्कृतिक एकता स्थिर रह सकेगी।

### राष्ट्रलिपि

हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं, समस्त ससार की लिपियों में सब से अधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमारी लिपि स्वरों और व्यंजनों का जैसा वैज्ञानिक पृथक्करण है, वैसा अन्य लिपियों में नहीं। ‘अ’ का उच्चारण हर स्थान पर ‘अ’ ही होगा और ‘इ’ का ‘इ’ ही ; ‘क’ यदि कहीं लिखा जायगा तो वह ‘क’ ही पढ़ा जायगा और कुछ नहीं। अंग्रेजी में जिस प्रकार ‘बी यू टी’ वट का ‘यू’ ‘अ’ पढ़ा जाता है और ‘पी यू टी’ पुट का ‘यू’ ‘उ’ वैसा हमारी लिपि में नहीं होता। हमारी लिपि में लिखे जाने वाले शब्दों के वर्ण-विन्यास में भी कोई कठिनाई नहीं पड़ती। अंग्रेजी शब्दों में जिस प्रकार मूक (साइलेंट) अक्षर रहते हैं, वैसे हमारे यहाँ नहीं। उर्दू में अक्षरों को मिलाकर लिखने और नुकतो के कारण उसके पढ़ने में जो अड़चने आती हैं, वे हमारी लिपि में नहीं। हर विषय की शिक्षा हमारी लिपि के द्वारा जितनी सुगमता से दी जा सकती है, उतनी अन्य किसी लिपि के द्वारा नहीं। फिर हमारी लिपि संस्कृत लिपि होने के कारण अन्य प्रान्तीय भाषाओं की लिपियों के जितनी सन्निकट है, उतनी अन्य कोई लिपि नहीं। मराठी में तो इसी लिपि का उपयोग होता है, गुजराती लिपि और हिन्दी लिपि में भी अधिक अन्तर नहीं और बंगला लिपि के भी अधिकांश अक्षर नागरी लिपि से मिलते-जुलते हैं। इतना ही नहीं, बर्मा, सिंहल, मलाया, श्याम, हिन्देशिया और हिन्द चीन आदि की वर्णमालाएँ भी प्रायः हमारी वर्णमाला के ही समान हैं। फिर भी आधुनिक यंत्रकाल में उस में थोड़े-बहुत सुधारों की आवश्यकता है। विशेषज्ञों की राय से हमें इन सुधारों को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये। इस दिशा में हम संकुचित वृत्ति न रखें। हमारी भाषा और साहित्य में निर्माण का कार्य हमें तेजी से अवश्य चलाना है, और जीवित भाषा में

भाषा के लिए स्वच्छन्दता की भी आवश्यकता है। स्वच्छन्दता में बंधन अखरते हैं, तथापि कुछ-न-कुछ नियंत्रण भी आवश्यक होते हैं। इस क्षेत्र में हमें बहुत सूक्ष्म अनुसंधान की ओर तो न जाना चाहिए, किंतु भाषा के रूप के सबंध में विद्वानों को एकत्रित होकर, कुछ-न-कुछ निश्चय कर लेना आवश्यक है। दृष्टान्त के लिए किस स्थान पर 'यी' और किस स्थान पर 'ई' कहाँ 'ये' और कहाँ 'ए' का उपयोग हो, इसका निश्चय होना है। इसी प्रकार के अन्य अनेक प्रयोग अभी अनिश्चित हैं। श्री रामचन्द्र वर्मा ने इस विषय पर 'अच्छी हिन्दी' और श्री किशोरीदास बाजपेयी ने 'लेखन कला' पुस्तक लिखी है, पर इसे मैं आरम्भ मात्र मानता हूँ। इस विषय में विद्वानों की एक समिति का आयोजन होना चाहिए।

छपाई, टाइप राइटर, तार आदि के लिए लिपि में सुधारों की और अधिक आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में गत वर्ष सम्मेलन के सभापति पद से दिये गये अपने भाषण में महापण्डित राहुलजी ने जो कुछ कहा था, उसे हमें कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करना चाहिए।

### निर्माण के कार्य में साहित्य का स्थान

देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् राष्ट्राभाषा तथा राष्ट्रलिपि के प्रश्न के अतिरिक्त हमारे सामने देश के निर्माण कार्य में साहित्य के निर्माण का प्रश्न उपस्थित होता है। यहाँ साहित्य शब्द को मैं अत्यन्त व्यापक अर्थ में लेता हूँ। अंग्रेजी के 'लिटरेचर' शब्द से साहित्य शब्द का पूरा अर्थ नहीं निकलता। जिस प्रकार अंग्रेजी का 'रिलीजन' शब्द धर्म का पूरा अर्थ नहीं करता, उसी प्रकार अंग्रेजी का लिटरेचर शब्द हमारे साहित्य शब्द का नहीं। जैसे हमारे 'धर्म' शब्द में जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों का समावेश हो जाता है, वैसे ही साहित्य शब्द के अन्तर्गत इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान, काव्य सब कुछ आ जाते हैं। मनष्य और पशु का सबसे प्रधान अन्तर दोनों की भाषा द्वारा प्रकट होता है। पशु जिस भाषा में बोलता है, मानव नहीं। और बर्बर मानव की जैसी भाषा होती है, सम्य मानव की नहीं। सम्य मानव ही साहित्य का सृजन कर सकता है और इस सृजन का साधन भाषा रहती है। विदेशियों ने विदेशी राज्य के साथ विदेशी भाषा भी हम पर लादी थी। हम सम्य थे, हमारी भाषा थी, अतः वे अपने काम में पूर्णतया सफल तो नहीं हुए, पर विदेशी राज्य तथा विदेशी भाषा के बोझ ने हमें ससार की सम्यता की दौड़ में पीछे अवश्य रख दिया। साहित्य-सृजन में भी पीछे रहने का यही प्रधान कारण है। समृद्ध देश के लिए समृद्ध साहित्य अनिवार्य है। हमारा देश प्राचीनतम देशों में से है। उसका पुराना इतिहास है, संस्कृति है, सम्यता है, सभी कुछ है; और यह सब हमें अपने प्राचीन साहित्य

मे मिलता है, जिसका सृजन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में भी हुआ है ; परन्तु देश के सारे कार्य चलाने के लिए न हमारे पास पूरा साहित्य है और न उस साहित्य सजन के लिए उपयुक्त शब्दावली । हमें एक ओर यह साहित्य-सृजन करना है और दूसरी ओर नयी शब्दावली गढ़नी है ।

गत तीस वर्षों में हिंदी में साहित्य का यथेष्ट सर्जन हुआ है । इतने कम समय में कदाचित् किसी भारतीय भाषा में इतना सृजन नहीं हुआ, जितना कि हिंदी में । अभी तक कुछ लोग समझते हैं कि हिंदी में साहित्य नहीं के बराबर है । हिंदी अहिंदी प्रांतों के रहनेवाले ही यह समझते हैं और इसका प्रचार करते हैं, यह बात नहीं ; हिंदी-भाषा-भाषी भी अनेक बार इसे स्वीकार कर लेते हैं । ये लोग द्वेष-भाव से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं, यह मेरा अभिप्राय नहीं है, अधिकतर भ्रमवश ही ऐसा हो रहा है । तीस-पैंतीस वर्ष पहले हमारे साहित्य के लिए जो कहा जाता था, आज भी प्रायः वही कहा जाता है । इस बीच हिन्दी साहित्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसका हमारे अधिकांश भाइयों को ज्ञान नहीं है । अहिंदी भाषियों को तो बिल्कुल ही नहीं । इस भ्रम का निवारण अत्यन्त आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ । हमारे देश की राजधानी दिल्ली और हमारे समस्त प्रांतों की राजधानियों तथा अन्य मुख्य नगरों में सम्मेलन द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए । इन प्रदर्शनियों में हिंदी की चुनी हुई मौलिक तथा अनूदित पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का सकलन हो । प्रकाशकों और ग्राहकों आदि के आकड़े भी प्रदर्शित किये जायें । बड़े-बड़े पुस्तकालयों के सूचीपत्रों, खोज की रिपोर्टों ; जैसे—लाला सीताराम की 'सरखे कमेटी की रिपोर्ट' डाक्टर माताप्रसाद गुप्त की 'पुस्तक-जगत्' आदि का प्रदर्शन हो । इन प्रदर्शनियों में इन्हीं विषयों पर भाषण, प्रचार आदि विविध कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाय ।

नव शब्द-निर्माण का कार्य कई स्थानों पर चल रहा है । जहाँ तक मुझे मालूम है, इस दिशा में नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, कलकत्ता और मद्रास के विश्वविद्यालय, बंगीय साहित्य-परिषद्, मराठी साहित्य परिषद् और मध्यप्रांतीय सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न हो रहे हैं । यदि इस दिशा में काम करने वाले समस्त विद्वानों और सस्थाओं की सूची बनायी जाये, तो कदाचित् वह बहुत बढ़ जायगी । यह एक विचारणीय विषय है कि पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए इस दिशा में केन्द्रीयकरण उचित होगा अथवा अभी यह सब कार्य पृथक्-पृथक् ही चलने दिया जाय और जब यह यथेष्ट हो चुके, तब इसे संयोजित कर इसका सारभाग ग्रहण कर लिया जाय । दोनों बातें ही हो सकती हैं । पृथक्-पृथक् कार्य यदि अभी चलने भी दिया जाय और यदि पुनरावृत्तियाँ भी हो जायें, तो भी मुझे विशेष हानि नहीं

दिखती, क्योंकि इस में कुछ अधिक आर्थिक व्यय के अतिरिक्त और क्या हानि होगी ? भिन्न-भिन्न विद्वान् शब्दों के भिन्न-भिन्न रूप हमारे सामने रखेंगे और अन्त में सब कृतियों की काट-छाट होकर सभी विषयों पर सुन्दर, प्रामाणिक शब्दावली हमारे सामने आ जायगी। इस शब्दावली का अन्तिम स्वरूप निर्णय करने के लिए केन्द्रीय सरकार और अ० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ये पारिभाषिक शब्द सब प्रांतीय भाषाओं के विद्वानों के सहयोग से समस्त प्रांतीय भाषाओं के लिए समान हो सकते हैं ; परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम इन पारिभाषिक शब्दों को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त बनाना चाहेंगे, तो इनमें से अधिकांश हमें संस्कृत से ही लेने होंगे। यदि इन का स्रोत संस्कृत रहा, तो भारत के अतिरिक्त बर्मा, सिहल, स्याम, आदि बृहत्तर भारत के देशों में भी इन शब्दों का प्रयोग हो सकेगा और इस प्रकार एशिया के देश एक दूसरे के अधिक समीप आ सकेंगे। अंग्रेजी पढ़े-लिखे विद्वानों का मत है कि वैज्ञानिक शब्दावली अंग्रेजी से लेनी चाहिए। यदि २००-४०० शब्द होते तो इसमें भी हमें कोई आपत्ति न होती, किन्तु वैज्ञानिक शब्दों की संख्या लाखों है, और वैज्ञानिक शब्दों का परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध है कि यदि हम एक शब्द अंग्रेजी से लेते हैं, तो उसके साथ साथ सम्बन्ध रखनेवाले सैकड़ों शब्द हमें वही से लेने पड़ते हैं।

उदाहरण के लिए एक शब्द फास्फरस ही लीजिए—

Phos-Phosphagen Phospham, Phosphamide, Phosphatase, Phosphate, Phosphated, Phosphate mia, Phosphate rock, Phosphate se, Phosphatic, Phosphatide, Phosphatization; Phosphatize, Phosphato, Phosphazo; Phosphene, Phosphenyl, Phosphide, Phosphinate, Phosphine, Phosphine oxide, Phosphinic, Phosphite, Phosphor, Phosphoaminolipide, Phosphocarnic acid, Phosphocreatine, Phosphoferrite, Phosphomolybdic, Phospholipide, Phosphomolybdate, Phosphoglycerate, phosphonic, Phosphonium, Phosphophyllite, Phosphoprotein, Phosphor, Phosphorate, Phosphorate oil; Phosphor bronze, Phosphoreal, Phosphoresce, Phosphorescence, Phosphorescent, Phosphoreted, Phosphoreted hydrogen, Phosphohidrosis, Phosphoric, Phosphoric acid, Phosphorical, Phosphoriferous, Phosphorism, Phosphorite, Phosphorize, Phosphoregen, Phospho-

rogenic, Phosphograph, Phosphographic, Phosphography, Phosphoscope, Phosphorous, Phosphorous acid, Phosphorous anhydride or oxide, Phosphoruria, Phosphorus, Phosphorus chloride, Phosphorus disease, Phosphorus oxide, Phosphorus pentachloride, Phosphorus sulphide, Phosphorus sesquisulphide, Phosphorus trichloride, Phosphoryl, Phosphorylation, Phosphoryl chloride, Phosphosilicate, Phosphotartaric Phosphotungstic, Phosphuranylite, Phosphuria, Phosphyl, Phossy, Phossyjaw.

यह काम लम्बा, जटिल और कष्टमाध्य है। कहाँ-कहाँ क्या-क्या हो रहा है, इसका व्योरेवार वृत्त मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, दो स्थानों पर क्या हो रहा है, यह मैं जानता हूँ। महापण्डित राहुलजी ने अभी हाल ही में सम्मेलन से सोलह सहस्र शासन-शब्दों का एक कोश प्रकाशित कराया है। सन् १९४९ के अन्त तक सभी विषयों के लगभग एक लाख शब्द राहुलजी तैयार करनेवाले हैं। हमारी मध्यप्रातीय सरकार ने सन् १९४६ में ही डा० रघुवीरजी की अध्यक्षता में यह कार्य आरम्भ कर दिया था। ५० के लगभग विद्वान् इसमें सलग्न हैं, और केवल शब्दावली ही नहीं; किन्तु ग्रन्थ-निर्माण भी हिन्दी और मराठी भाषाओं में हो रहा है। हमें आशा है कि अगले ५-६ मास में विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यग्रन्थ प्रकाशित होकर विद्यार्थियों के सामने आ जायेंगे। रसायन, भौतिक, वनस्पति तथा प्राणिशास्त्रों और गणित के लगभग ३० ग्रन्थ अब तक बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों की शब्दावली भी तैयार है। हमारे प्रात के सभी वाणिज्य-महाविद्यालयों में हिन्दी और मराठी द्वारा शिक्षण हो रहा है। रेल, मोटर, तार, शासन, पाश्चात्य आयुर्वेद आदि के डेढ़ लाख शब्दों का निर्माण हो चुका है। जो काम मध्यप्रातीय शासन के अधीन रहा है, उसमें विशेषता यह है कि आरम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च गवेषण तक के सभी शब्द प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

### साहित्य के दो विभाग

साहित्य के निर्माण की ओर यदि हम दृष्टिपात करें और साहित्य शब्द को व्यापक-से-व्यापक अर्थ में भी लें, तो साहित्य-निर्माण को दो भागों में बाटा जा सकता है—एक शास्त्रीय साहित्य, जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक साहित्य भी आ जाता है और दूसरा ललित साहित्य। प्रथम प्रकार के साहित्य में विज्ञान, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष आदि शास्त्रों का समावेश होता है। हमारे यहाँ इस प्रकार के साहित्य की

घोर कमी है, यहाँ तक कि हमारा कोई प्रामाणिक इतिहास तक आज उपलब्ध नहीं है। विदेशी विद्वानों ने हमारे प्राचीन इतिहास की कुछ खोज अवश्य की है। मौर्यवंश से लेकर गुप्तवंश तक हमारे प्राचीन इतिहास के अनेक अंश सामने आये हैं, परन्तु अब तक इस काल का भी कोई श्रृंखलाबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। विक्रमीय सवत जिस विक्रमादित्य के नाम से चलता है, उसका भी हमें पता नहीं है। फिर विदेशियों ने एक ओर यदि हमारे इतिहास का पता लगाने का प्रयत्न कर हम पर उपकार किया है, तो दूसरी ओर हमारे ही इतिहास में स्थान-स्थान पर हमें छोटा दिखाने का यत्न कर हमारा अपकार भी कम नहीं किया। दृष्टान्त के लिए अब तक यह माना जाता था, और अभी तक अधिकांश विद्वान यही समझते हैं, कि सिकन्दर हमारे देश से जीतकर लौटा था, परन्तु हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व मेरे मध्यप्रांत के अमरावती कालेज के प्रोफेसर डा० हरिश्चन्द्र सेठ ने यूनानी इतिहास के लेखों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सिकन्दर की यहाँ जीत नहीं, हार हुई थी। हमारे देश के अधिकांश इतिहास का एक तो अभी तक पूरा पता ही नहीं लगा और जितने इतिहास का पता भी लगा है, उसमें भी बहुत-सा विकृत रूप में उपस्थित किया गया है।

साहित्य के ललित विभाग में इन वर्षों में यथेष्ट सृजन हुआ है। ललित साहित्य का कार्य केवल आनन्द देना है या शिक्षा भी—यह एक विवादग्रस्त विषय रहा है। अंग्रेजी में ‘आर्ट फार आर्ट्स सेक’—‘कला कला के लिए ही है’ यह एक बड़ा पुराना सिद्धान्त है। इस सम्बन्ध में फ्रांस के प्रसिद्ध साहित्यकार रोमाँ रोलाँ ने जो कुछ अपने उपन्यास ‘जान क्रिस्तोफर’ में कहा है, वह कुछ लम्बा होने पर भी मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। वे कहते हैं—

“कला के लिए कला ! क्या ही अच्छा धर्म है ; परन्तु यह धर्म तो बलवानों का है। कला ! जीवन को वैसे ही जकड़कर पकड़ना, जैसे गरुड़ अपने आखेट को पकड़ता है, उसे लेकर ऊपर उठना, गगन मण्डल की अखण्ड शांति में उसे लेकर उड़ जाना। इसके लिए तुम्हें सुदृढ़ पंजों, महान् पंखों और बलवान हृदय की आवश्यकता है। कला का अर्थ है—नियंत्रित, संयमित, मर्यादित जीवन। कला जीवन की सम्राज्ञी है। तुम साधारण अभिनेता हो, परन्तु इतने कुशल अभिनेता भी नहीं कि अपने अभिनय में अपने को भी भूल सको। जिस प्रकार ये अभिनेता अपनी शारीरिक त्रुटियों तथा दोषों के द्वारा पैसा पैदा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपनी मानसिक तथा आत्मिक त्रुटियों से लाभ उठाते हो। तुम अपनी तथा जनता की कुरूपता का उपयोग कर साहित्य का निर्माण करते हो। तुम्हारे उपदेश के मूल में ही मृत्यु है। कला तो जीवन का स्रोत है, परन्तु तुम्हारे, सबसे अधिक ईमानदार समझे जाने

वाले लेखक तक इतने कायर है कि उनके आँखों की पट्टी खुल जाने पर भी वे न देख सकने का बहाना करते हैं। वे धृष्टतापूर्वक कहते हैं—‘हाँ, कला के लिए कला का सिद्धान्त भयानक है, विषैला है, परन्तु उसमें बुद्धि है, प्रतिभा है।’ वाह ! कितना विचित्र तर्क है, मानो किसी गुण्डे को दण्ड देते हुए न्यायाधीश कहें कि ‘यह पापी अवश्य है ; परन्तु इसमें बड़ी बुद्धि है, बड़ी प्रतिभा है।’

रोमाँ रोलाँ महोदय के कथनानुसार ललित साहित्य के निर्माताओं को कितना ऊँचा उठना आवश्यक है, यह कहना निरर्थक है , साथ ही ऐसा साहित्य प्रत्यक्ष में उपदेश न देते हुए भी मानव-मन को किस ओर किस प्रकार ले जायगा, यह भी कहना अनावश्यक प्रतीत होता है।

### नाटक और रंगमंच

ललित साहित्य में नाटक का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यह सारे ससार के साहित्यज्ञ मानते हैं। इसके कई कारण हैं—पहला कारण तो यही है कि जहाँ अन्य ललित साहित्य केवल श्रवणेन्द्रिय द्वारा आनन्द देता है, वहाँ नाटक श्रवणेन्द्रिय और दृश्येन्द्रिय दोनों के द्वारा आनन्द देता है। दूसरे, नाटक में अनेक ललित कलाओं का एक स्थान पर समावेश होता है। हिन्दी में भारतेन्दु के पश्चात् बहुत समय तक नाटकों की बड़ी कमी रही , परन्तु इधर कुछ लेखकों ने नाटक लिखे हैं। नाटक रचना तब तक पूर्ण से सफल नहीं हो सकती, जब तक रंगमंच की उचित व्यवस्था न हो। अच्छे रंगमंच हमारे निर्माण कार्य में अत्यधिक सहायता दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में रूस का उदाहरण हमारे सामने है। इस दृष्टि से यह युग ‘सिनेमा युग’ कहा जाता है, परन्तु अमेरिका में जहाँ ‘हालीवुड’ के महान् सिनेमा-स्टूडिओ हैं, वहाँ भी नाटक का पुनरुत्थान हो रहा है। चित्र प्रत्यक्ष का स्थान सदा के लिए नहीं ले सकते। नाटक की अपनी विशेषता है, जो सिनेमा को प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे मतानुसार हिन्दी में रंगमंच एक राष्ट्रीय आवश्यकता है।

### सिनेमा

सिनेमा का स्तर भी हमारे देश में उन्नत होने के स्थान पर अवनत होता जा रहा है। इसी देश में किसी समय चण्डीदास, देवदास, अमृत-मथन, अमर-ज्योति, पुकार इत्यादि के सदृश चित्रपट निकले, परन्तु इधर ऐसे चित्रपटों का निर्माण प्रायः बन्द-सा हो गया है। चित्रपटों में अश्लीलता भी बढ़ती जाती है। मैं इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं कि यहाँ की जनता ही अच्छे चित्र नहीं देखना चाहती। जिन अच्छे चित्रपटों का मैंने उल्लेख किया है, वे अत्यन्त लोक-प्रिय चित्र भी थे। नाटक के सदृश



सिनेमा का भी राष्ट्र-निर्माण में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। सरकारी सेसर को इस दिशा में बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनेक देशों में शिक्षा-सम्बन्धी चलचित्रों के निर्माण की कई संस्थाएँ हैं। हमें भी इस देश में ऐसी संस्थाएँ चाहिए।

### रेडियो

रेडियो को भी आज बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हो गया है। रेडियो द्वारा अनन्त ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है। रेडियो की आवश्यकता नगरों की अपेक्षा गाँवों में अधिक है, क्योंकि वहाँ के निवासियों में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है और ऐसे लोगों की ज्ञानवृद्धि जितनी शीघ्र रेडियो से हो सकती है, अन्य किसी वस्तु से नहीं। भारत में केन्द्र में ही नहीं, अधिकांश प्रान्तों में भी प्रान्तीय ब्राडकास्टिंग स्टेशन खुल गये हैं, परन्तु इन स्टेशनों से जो कुछ प्रसारित किया जाता है, उसकी सामग्री और भाषा दोनों ही दोषों से ओतप्रोत है। भाषा की दृष्टि से तो रेडियो का बहुत समय तक सम्मेलन ने बहिष्कार तक किया था। जिस समय सम्मेलन ने रेडियो का बहिष्कार कर रखा था, उस समय में और आज में बड़ा अन्तर हो गया है। अब देश स्वतन्त्र है। पाकिस्तान की स्थापना हो गयी है; पर इतने पर भी, आज भी रेडियो का सारा वातावरण अराष्ट्रीय है। रेडियो के तीन प्रधान विभाग हैं—

- (१) गृह विभाग (होम-सर्विस)
- (२) समाचार विभाग (सेन्ट्रल न्यूज ऑरगनाइजेशन)
- (३) विदेशी विभाग (एक्सटर्नल सर्विसेज)

प्रथम विभाग भारतवासियों के लिए है, दूसरे का सम्बन्ध समाचारों से है और तीसरे विभाग द्वारा विदेशों में भारत से सम्बन्ध रखने वाली बातों का प्रचार किया जाता है। जो भारतीय भारत के बाहर उपनिवेशों में निवास करते हैं, उनसे सम्पर्क स्थापित करने का कार्य भी यह तीसरा विभाग ही करता है।

तीनों विभागों का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में है, जिनमें अधिकांश को न भारतीय संस्कृति का ज्ञान है और न हमारी भाषा का। रेडियो के इस अवस्था में रहने के अनेक कारण हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

- (१) हमारी राष्ट्रीय सरकार होने पर सरकार का ध्यान अब तक रेडियो की ओर नहीं गया। मंत्रियों के भाषणों को छोड़कर अन्य कौन सा प्रचार रेडियो द्वारा किया जाता है, इस ओर सरकार का कोई लक्ष्य नहीं।

(२) बुखारी साहब और उनके कुछ साथियों के चले जाने पर भी, अभी तक रेडिओ पर बुखारी-समूह का ही अधिकार है।

(३) नये कर्मचारियों की नियुक्तियों में भी भारतीय संस्कृति के जानकारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन नियुक्तियों को करने वाले अधिकारियों में भारतीय संस्कृति को जाननेवाले व्यक्ति ही नहीं हैं।

(४) “रेडिओ-हिन्दी-परामर्श-समिति” के एक भी सुझाव को कार्यरूप में परिणत नहीं किया जाता।

इसके निम्नलिखित फल हुए हैं—

(१) रेडिओ द्वारा किसी भी प्रकार का भारतीय सांस्कृतिक प्रचार नहीं होता।

(२) रेडिओ द्वारा जो रूपक तथा नाटक प्रसारित किये जाते हैं, उनमें आज भी अधिकांश ऐसे होते हैं, जो सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरातल की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं कहे जा सकते।

(३) रदी और टुन्चे फिल्मी गाने गाये जाते हैं, जो लोक-रुचि को दूषित करते हैं।

(४) इस प्रकार के कार्यक्रम विदेशों में भी भारत को नीचा दिखाते हैं।

भाषा की दृष्टि से भी रेडिओ अत्यधिक दूषित है। कुछ समय पूर्व भाषा में थोड़ा-बहुत सुधार हुआ था, पर अब फिर इसमें परिवर्तन हुआ है। इसका मुख्य कारण कदाचित् उर्दू पत्रों का प्रचार है। यह प्रचार किस प्रकार किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में मैं यहाँ एक दृष्टान्त देना चाहता हूँ। ‘तन्वीर’ नामक उर्दू का एक दैनिक पत्र लखनऊ से निकलता है। उर्दू-जगत में इस पत्र की यथेष्ट प्रतिष्ठा है। ता० १४ अक्टूबर सन् १९४८ के अपने अंक में ‘अखिर यह कौन सी जबान है’ शीर्षक अग्रलेख में इस पत्र ने जो कुछ लिखा है, वह ध्यान देने योग्य है। वह लिखता है—

“रेडिओ की जबान में बाज अलफाज तो रायजुल वक्त अलफाज के मुकाबले में इतने भोड़े और लचर होते हैं कि वेखबरी में बाज औकात यह मालूम होता है कि कोई गाली दे रहा है, जो खबरो में शामिल हो गयी है।”

इस प्रकार के अलफाजों की इसी लेख में एक लम्बी सूची दी गयी है। इस सूची के कुछ शब्द को देखिए—

‘आयु, सहायता, वर्ग, चर्चा, अधिकार, विरोध, शनिवार, उचित उपाय, अधिकारी, न्याय, शिक्षा, निश्चय, स्वीकार, इतिहास, शासन, सम्बन्ध, समय, घटना पद की शपथ लेना, समाप्त।’

ये शब्द भोंडे और लचर तथा गालियो से प्रतीत होते हैं।

पत्र सिफारिश करता है—“अगर हिन्दुस्तानी के लफ्ज का इस्तेमाल रखना ही चाहते हैं, तो हिन्दुस्तानी ही जवान भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो तक्सीम से पहले होती रही है। अगर वो इस पर तुले हुए हैं कि हिन्दुस्तानी का लफ्ज भी इस्तेमाल करते रहें और इस्तेमाल इसी जवान को करते रहे, तो उर्दू की खबरे किसी दूसरे वक्त में सुनानी शुरू कर दे ताकि मुल्क की अक्सरीयत जिस जवान को समझ सकती है और शरीफ लोगो की मजलिस में समझी और बोली जाती है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले।”

यह है भारत की अक्सरीयत और शरीफ लोगो की मजलिस में बोली जानेवाली जवान ! धन्य है !

रेडिओ सदृश देश और विदेश में प्रचार के सबसे बड़े साधन की ओर हमें और हमारी सरकार को ध्यान देना ही होगा। छोटे-मोटे सुधार से यहाँ काम न चलेगा, इस विभाग में तो पूर्ण क्रान्ति आवश्यक है।

### पत्र-पत्रिकाएँ

हिन्दी में पत्र-पत्रिकादि का प्रकाशन तो बढ़ता जा रहा है; पर अभी हमारे पत्रों में सुधार के लिए बहुत अधिक स्थान है। अंग्रेजी पढ़े-लिखे मराठी, गुजराती, बंगला भाषा-भाषी अपनी-अपनी मातृभाषा के पत्रों को पढ़कर अंग्रेजी पत्रों को पढ़ने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते, परन्तु अंग्रेजी पढ़े-लिखे हिन्दी-भाषा-भाषियों की यह स्थिति नहीं है। जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान है, ऐसे हिन्दी-भाषा-भाषियों का भी इसमें थोड़ा-बहुत दोष हो सकता है; परन्तु इसमें मैं सबसे अधिक दोष मानता हूँ हिन्दी में मराठी, गुजराती और बँगला के सदृश पत्रों का अभाव। इसका उत्तर-दायित्व पत्रकारों पर नहीं है। उन बेचारों के पास अंग्रेजी या अन्य प्रांतीय भाषाओं के सदृश साधन नहीं है। फिर विज्ञापन आदि के रूप में जो सहायता सरकार और अन्य विज्ञापनदाताओं की ओर से अंग्रेजी तथा बम्बई, कलकत्ते आदि व्यापारिक नगरों से निकलने वाले प्रांतीय भाषाओं के पत्रों में मिलती है, वह हिन्दी-पत्रों को नहीं। इस सम्बन्ध में हम व्यापारियों तथा उनकी कंपनियों से तो केवल अनुरोध कर सकते हैं कि वे हिन्दी-पत्रों को भी उसी दृष्टि से देखें, जिस दृष्टि से वे अन्य भाषाओं के पत्रों को देखते हैं, परन्तु हम अपनी केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों को इस विषय में बाध्य कर सकते हैं।

एक कारण और है, जिससे हमारे हिन्दी-पत्र उन्नति नहीं कर पाते। उन्हें सभी समाचार अंग्रेजी में मिलते हैं, क्योंकि न तो अभी किसी ऐसी समाचार संस्था का

निर्माण हुआ है जो हिन्दी में ही समाचार भेजे और न अभी हिन्दी टेलीप्रिन्टर ही निकला है। हिन्दी-पत्रों को सारे समाचार अंग्रेजी में प्राप्त कर उनका पहले हिन्दी-अनुवाद करना पड़ता है। हिन्दी-पत्रों के लिए हिन्दी में तारों के मिलने की और हिन्दी के टेलीप्रिन्टर द्वारा समाचारों के मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए।

### वाणिज्य-जगत् में अंग्रेजी का प्रभुत्व

यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि हमारे वाणिज्य-जगत् में आज भी अंग्रेजी का ही दौर-दौरा है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यह क्षम्य है, परन्तु देश के व्यापार में नहीं। हमारे पत्र-पत्रिकादि की व्यापार-क्षेत्र में अवहेलना का कारण इस क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व है।

### ग्राम साहित्य

साहित्य-सृजन की ओर दृष्टिपात करते समय हम एक और बात को भी विस्मृत नहीं कर सकते। स्वतन्त्रता के पश्चात् हमें केवल बालकों को ही नहीं, अपने देश के प्रौढों को भी शिक्षित करना है। इस देश की ८० प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है। अभी तक जिस साहित्य का सृजन तथा प्रकाशन हुआ है, उसमें से अधिकांश साहित्य शहराती साहित्य है। हमें अब सबसे अधिक ध्यान गाँवों की ओर देना है और अपने साहित्य, नाटक, रंगमंच, सिनेमा, रेडिओ और पत्र-पत्रिकाओं को ग्रामों के अनुकूल भी बनाना है। रूस ने इस दिशा में अपनी भाषाओं की ही नहीं, पर उपभाषाओं की भी उन्नति की है। क्या हम यह न करेंगे ?

### विदेशी भाषाओं को प्रतिदान

हमने विदेशी भाषाओं से हिन्दी में बहुत कुछ लिया है ; पर अब वह समय आ गया है, जब हम अपनी भाषा से भी विदेशों को कुछ दे। ससार में किसी देश की प्रतिष्ठा उसके विचारक तथा साहित्यिक ही बढ़ाते हैं। गुरुदेव कवि-सम्राट् रवि बाबू ने अपनी कृतियों को अंग्रेजी द्वारा ससार को देकर हमारे देश की भी जैसी प्रतिष्ठा बढ़ायी है, वह किसी से छिपा नहीं है। रवीन्द्र बाबू के अतिरिक्त भी इस देश में ऐसे अनेक साहित्यिक हैं, जिनकी कृतियाँ ससार के किसी भी देश की उत्तम-से-उत्तम साहित्यिक रचनाओं से टक्कर ले सकती हैं। इस दिशा में हमें अंग्रेजी भाषा का ही सहारा लेना होगा। उस भाषा को हम जानते हैं और उसका अन्तर्राष्ट्रीय स्थान भी है। यदि हम अंग्रेजी-द्वारा संसार के साहित्य को कुछ देंगे, तो हमारे साहित्य और देश दोनों का गौरव बढ़ेगा। मैंने 'नोबल पुरस्कार'-विजेता

कई साहित्यिकों की कृतियाँ पढ़ी हैं और मैं बिना किसी सकोच के कह सकता हूँ कि इस देश का साहित्य, यदि ससार के सामने जाता, तो हमारे अनेक साहित्य-सृष्टा 'नोबल-पुरस्कार' प्राप्त करते।

महात्मा गांधी के नेतृत्व के पश्चात् और विशेषकर देश के स्वतन्त्र होने के उपरान्त, भारत को ससार में एक विशेष स्थान प्राप्त हो गया है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू यूरोप गये थे। उन्होंने वहाँ से लौटकर, भारत पश्चिमी जगत् में किस दृष्टि से देखा जाने लगा है, इस सम्बन्ध में हमें कई बातों का दिग्दर्शन कराया है। गत दो महायुद्धों की हिसा से जर्जरित यूरोप पर गांधीजी के व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनके सिद्धान्तों और उनके उपदेशों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। अहिंसा द्वारा भारत को, जो स्वातन्त्र्य-प्राप्ति हुई है, उसने इस प्रभाव को और भी गहरा कर दिया है। विश्व की भावी शांति के लिए आज ससार हमारे देश की ओर देखने लगा है। ऐसे अवसर पर ससार हमारे साहित्य का कितना आदर करेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस आदर के अतिरिक्त हमारा साहित्य ससार के विचार-क्षेत्र में एक नयी धारा बहा कर विश्व का बहुत बड़ा कल्याण भी कर सकता है। किसी भी कृति के पहले विचार की उत्पत्ति होती है और विचार के निर्माण में साहित्य का बड़ा भारी हाथ होता है।

हिन्दी-साहित्य में आलोचना की जितनी कमी है, उतनी हमारी प्रातीय भाषाओं में भी नहीं। विदेशों में हमारा साहित्य पहुँचने पर वह वहाँ आलोचना की कसौटी पर न कसा जाय, यह असंभव है और तब हम स्वयं भी अपने साहित्य को कदाचित् अधिक परख सकेंगे। गुरुदेव रवीन्द्र बाबू को भी तो हम विदेशों में उन के साहित्य का आदर होने पर ही पहचान सके।

यहाँ मैं दो शब्द अपने साहित्यिकों से भी कहना चाहता हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण के लिए लक्ष्य और रचना-विधान दोनों में ही व्यापकता एवं उदारता की आवश्यकता है। अन्य भाषाओं के साहित्यिक यदि थोड़े सकीर्ण भी हों, तो जो भाषा इतने बड़े देश में राष्ट्र-भाषा है, अथवा होने जा रही है, उस के साहित्यिकों में सकीर्णता न होनी चाहिए। वे अपने साहित्य को सारे ससार के लिए उपयोगी बनाने का ही यत्न करें। हमारी परम्परा उदारता की परम्परा रही है।

### साहित्य और साहित्य-संस्थाओं का उत्तरदायित्व

भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् भावी निर्माण के कार्य को देखते हुए साहित्यिक और साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। इन संस्थाओं में अ० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अग्रगण्य है। परन्तु, साहि-

त्यिक और साहित्यिक सस्थाएँ तब तक अपना यह उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकती, जब तक उन्हें स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का पूरा-पूरा सहयोग न मिले।

### सरकार का कर्त्तव्य

हिन्दी राष्ट्रभाषा और नागरी राष्ट्रलिपि घोषित कराने के साथ ही हमें निम्नलिखित बातें सरकार से करनी हैं—

(१) सरकार हिन्दी और अहिन्दी समस्त प्रांतों के भाषा-विज्ञों की एक समिति बनाये, जो पारिभाषिक शब्दों के ऐसे अन्तिम रूपों का निर्णय करे, जिन्हें हिन्दी और अहिन्दी सब प्रांतों की भाषाओं में समान रूप से व्यवहृत किया जा सके।

(२) हिन्दी-भाषी प्रांतों की समस्त शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो। अहिन्दी प्रांतों में हिन्दी अनिवार्य की जाय। समस्त विश्वविद्यालयों को और शिक्षा-संस्थाओं को इस सम्बन्ध में सरकार स्पष्ट आदेश दे।

(३) सरकार द्वारा एक केन्द्रीय ट्रेनिंग कालेज खोला जाय, जहाँ सरकारी नौकरियों के लिए जिन व्यक्तियों का चुनाव हो जाय, उनकी नियुक्ति के पहले यदि वे हिन्दी न जानते हों, तो हिन्दी की शिक्षा दी जाय और उनके लिए हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो।

(४) हिन्दी-भाषी प्रांतों के विश्वविद्यालयों में 'डाक्टरेट' के लिए जो निबंध लिये जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के थीसिस को छोड़, शेष सभी हिन्दी में लिये जायें।

(५) जिस प्रकार संयुक्त प्रांत की धारा-सभा में सारे बिल, प्रस्ताव, प्रश्न आदि हिन्दी में प्रस्तुत किये जाते हैं, उसी प्रकार केन्द्रीय धारा सभा और हिंदी भाषा-भाषी प्रांतों की धारा-सभा में भी कार्यवाही की जाय। केन्द्रीय धारा-सभा में कुछ समय तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी यह कार्य किया जा सकता है।

(६) प्राचीन साहित्य की खोज, वैज्ञानिक और शास्त्रीय साहित्य के निर्माण तथा प्रत्येक विषय के लिए उपयुक्त पाठ्य-पुस्तक लिखाने के लिए सरकार सम्मेलन को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे।

(७) हिन्दी में तार भेजने और हिंदी टेलीप्रिंटर लाइनों की व्यवस्था की जाय।

(८) जिस प्रकार लार्ड कर्जन ने यहाँ की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनवाया था, उसी प्रकार एक नया कानून प्राचीन साहित्य-कारों के जन्म-स्थानों की रक्षा के लिए बनाया जाय। गोस्वामी तुलसीदासजी के जन्म-स्थान की रक्षा के लिए यदि कुछ न किया गया, तो वह स्थान बहुत शीघ्र बह जाने

वाला है। इस सम्बन्ध में तत्काल कुछ-न-कुछ होना अत्यावश्यक है। और इस कार्य में सरकार से सहायता मिलनी चाहिए।

### सम्मेलन का भावी कार्यक्रम

राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-लिपि के प्रश्न का निर्णय होने के पश्चात् भी सम्मेलन को उपयुक्त राष्ट्र-भाषा और उपयुक्त राष्ट्र-लिपि बनाने तथा सरकार द्वारा इन सारे कार्यों की व्यवस्था कराने का बहुत बड़ा काम अभी करना है। इसके अतिरिक्त उसने हिन्दी के अनुकूल सारे देश में वायु-मण्डल तैयार करने का अब तक जो प्रयत्न किया है, उसे भी अभी पूरा करना है। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों में भी हिन्दी-प्रेम जाग्रत करना अभी शेष है। पत्र-पत्रिकादि के क्षेत्र में, जो ज्ञान-प्रसार के सबसे बड़े साधनों में से एक है, अंग्रेजी पत्रकारों के हृदयों में हिन्दी की प्रतिष्ठा स्थापित करनी है। विज्ञान और शास्त्रीय पत्र हिन्दी में नहीं के बराबर है। जहाँ तक मुझे मालूम है, प्रयाग के 'विज्ञान' नामक पत्र के सिवा इस क्षेत्र में और कोई भी पत्र हिन्दी में नहीं निकलता। इस दिशा में भी सम्मेलन ही कुछ कर सकता है। दूसरी भारतीय भाषाओं में किस-किस दिशा में क्या-क्या किया जा रहा है और उसका कितना उपयोग हिन्दी में किया जा सकता है, इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। विदेशों में अफ्रीका, फीजी, मारिशस, ट्रेनीडाड आदि उपनिवेशों में, जहाँ भारतीय लाखों की संख्या में निवास करते हैं, हिन्दी और हिन्दी के द्वारा भारतीय संस्कृति को पहचाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न हल होने पर भी सम्मेलन के सामने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। समूचे देश को और जो देश-वासी भारत के बाहर रहते हैं उन सबको, एक सूत्र में बाँधने का कार्य मुख्यतः हिन्दी-द्वारा ही हो सकता है। यहाँ एक बात और कह दूँ। मेरा विश्वास योजना बनाकर कार्य करने में रहा है। सम्मेलन का सारा कार्य एक निश्चित योजना बनाकर होना चाहिए।

### मेरे दो स्वप्न

इस भाषण को पूर्ण करने से पहले मैं अपने दो स्वप्नों के उल्लेख का लोभ संवरण नहीं कर सकता—मेरे प्रथम स्वप्न के फलस्वरूप सन् १९१९ के अ० भा० हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के पटना अधिवेशन में, जिसके सभापति पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल थे, एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसका आशय था कि भिन्न-भिन्न विषयों पर ग्रन्थ-निर्माण करने के लिए लेखकों को एक स्थान पर रखा जाय और उन्हें जीवन-निर्वाह की चिन्ता से मुक्त कर दिया जाय। इसी उद्देश्य से जबलपुर में 'राष्ट्रीय

हिन्दी-मन्दिर' की स्थापना हुई थी, परन्तु वह प्रयास सफल न हो सका। आज लेखकों की जीविका और साहित्य-सृजन दोनों ही प्रश्न उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं। इस युग में ऐसी संस्था का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। यदि ऐसी संस्था का निर्माण, जो लेखकों को एक स्थान पर रख सके, नहीं हो सकता, तो फिर एक ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए, जो लेखकों को उनकी जीविका की चिन्ता से मुक्त कर उन्हीं के स्थान पर रहने दे और उनसे एक निश्चित समय के भीतर एक निश्चित परिमाण में साहित्य-सृजन का कार्य कराये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि साहित्यकार अपनी जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा कार्य करते रहें और केवल अवकाश का समय ही साहित्य-सृजन में लगाते रहे, तो हमें जिस साहित्य की आवश्यकता है, उसकी रचना में बहुत समय लगेगा। लेखकों को हम उनकी जीविका की चिन्ता से मुक्त कर ही इस कार्य को सुन्दर रूप में करा सकते हैं।

मेरा दूसरा स्वप्न है भारत में भी 'नोबेल-पुरस्कार' के समान कम-से-कम एक लाख रुपये के एक ऐसे पुरस्कार की व्यवस्था, जो किसी भी भारतीय भाषा के सर्वोत्तम ग्रन्थ पर हर तीसरे वर्ष दिया जाये। वह ग्रन्थ चाहे राष्ट्रभाषा हिन्दी में हो अथवा बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़ आदि किसी भी प्रांतीय भाषा में।

इन योजनाओं तथा सम्मेलन के अन्य कार्यों के लिए यथेष्ट धन चाहिए। गत युद्ध में कितना कमाया है लोगों ने, उचित व अनुचित दोनों ही प्रकारों से। करोड़ों रुपये लोगों ने इनकम टैक्स के रूप में दिये हैं। दान के एक-एक करोड़ के ट्रस्ट भी बने हैं। भारत की दान-प्रणाली बड़ी दूषित रही है, अब भी दूषित है। मैं तो समाज का वह संगठन चाहता हूँ जिसमें न किसी के पास दान देने को रहे और न कोई दान के लिये हाथ फैलाये; परन्तु जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति है, तब तक दानप्रणाली रहेगी और इसलिए उसका सुधार भी अभीष्ट है। क्या भारत में भी इन कार्यों के लिये कोई दाता सामने आयेगा? जिन्होंने उचित मार्गों से कमाया है, वे उसमें सार्वजनिक भाग मान कर दान दे सकते हैं और जिन्होंने अनुचित मार्गों से प्राप्त किया है, वे अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए। ध्यान रखें, यह लक्ष्मी चंचला है। 'स्थिराभव, स्थिराभव, स्थिराभव' का जप करते रहने पर भी यह आज तक कहीं स्थिर नहीं रही है और न भविष्य में ही रहने वाली है। बड़े-बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ और नाश। बड़े-बड़े करोड़पति बने और बिगड़े। जिन्होंने इस सम्पदा का उपयोग कर लिया, वे ही धन्य हो गये, शेष का वही हाल हुआ, जो धन पर बैठे सांपों का होता है।



इस भाषण का अन्त करता हूँ मैं राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की इन पंक्तियों से—

जय      देव-मन्दिर-देहली,  
 सम-भाव से जिस पर चढ़ी  
 नृप-हेम-मुद्रा और रंक वराटिका  
 मुनि-सत्य-सौरभ की कली  
 कवि-कल्पना जिसमें बड़ी,  
 फले फले साहित्य की वह वाटिका ।